

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE



MAY 2021

आईपीसी सुधार

WHO में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता

इजरायल-फिलिस्तीन के बीच हिसा

म्यांमार राजनीतिक अस्थिरता

5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधार

WWW.IASBABA.COM

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामयिकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तैयार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट www.iasbaba.com दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – ‘इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए?’

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो MAY-2021 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें <https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/> से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots** अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।
- इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए snippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारित Prelims MCQs) प्रस्तुत किया है जो आपको बेहतर revision के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- **‘Must Read’ section**, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

‘Must Read’ section: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनुसरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

<https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/>

“Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them.”

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- पुटोला नाच (Putola Nach)
- उत्तरी असम में बार-बार आने वाले भूकंपों के पीछे चार कारकों में से एक
- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में नई साइटें जोड़ी गईं
- दहानु घोलवड़ सपोटा
- कलाक्षेत्र फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड

राजनीति / शासन

- सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर फैसला
- विक्केट्रीकरण और कोविड
- दोषियों को उनके घरों में नजरबंद करने पर विचार करें: उच्चतम न्यायालय
- राजनेताओं से सीख
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311
- जीवन के अधिकार को प्राथमिकता
- यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड
- सुरक्षा कवर प्रदान करने का राजनीतिकरण
- भारतीय दंड संहिता (IPC) में सुधार के सुझाव देने के लिए पैनल का गठन
- इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलना

सामाजिक मुद्दे / वेलफेयर

- डिजिटल युग में महामारी और असमानता
- कोविड संकट के मद्देनजर ग्रामीण अनिवार्य
- बाल विवाह और महामारी
- ग्रामीण क्षेत्र और कोविड -19 की दूसरी लहर
- जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी
- भारतीय जेल

स्वास्थ्य समस्या

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)
- भारत में चिकित्सा ऑक्सीजन संकट
- कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन

- भारत के अस्पतालों में बार-बार आग लगना
- भारत के टीकाकरण में आगे की चुनौती
- एंटीफंगल इंजेक्शन की कमी, एम्फोटेरिसिन B
- आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच कोविड -19 संक्रमण की सूचना
- जीवविज्ञान रोगों के उपचार के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करना
- कोरोना वायरस वेरिएंट के लिए नई नामकरण प्रणाली
- भारत के स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ब्रेन ड्रेन
- राज्यों ने म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा
- SARS-COV-2 वायरस का हवा में संचरण (Airborne Transmission)
- आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST असंवैधानिक: दिल्ली हाई कोर्ट
- सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण
- आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ

सरकारी योजनाएँ

- भारत में स्वच्छता प्रणाली की स्थिति
- स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए नया ढांचा
- विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 की अधिसूचना जारी
- SWAMIH ने अपनी पहली आवासीय परियोजना पूरा किया
- वेबेरियन नौकरशाही और उनकी चुनौतियाँ
- चर्चा में वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centre Scheme)
- सेहत ओपीडी पोर्टल (SeHAT OPD Portal) का शुभारंभ
- मध्याह्न भोजन अर्थात् मिड-डे-मील (MDM) योजना के घटक के रूप में मौद्रिक सहायता

अंतरराष्ट्रीय

- ऑपरेशन समुद्र सेतु-II का शुभारंभ
- G-7 शिखर सम्मेलन में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया
- COVID-19 टीकों के लिए TRIPS सुरक्षा को माफ करने की पहल
- कोविड -19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स) छूट
- तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (ASM3) बैठक
- दक्षिण सूडान की संसद भंग
- क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में आवश्यक सुधार
- इजरायल-फिलिस्तीन के बीच हिंसा

- कोलंबो पोर्ट सिटी
- लिथुआनिया ने चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग छोड़ा
- बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका के साथ 'मुद्रा विनिमय समझौता'
- म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता
- कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझोउ-2
- SARS-CoV-2 की उत्पत्ति में अमेरिकी जांच
- टोक्यो ओलंपिक और वायरस (COVID-19)

भारत और विश्व

- USA की COVID बचाव योजना और भारत के लिए सबक
- भारत-यूके आभासी (वर्चुअल) शिखर सम्मेलन
- लचीले भविष्य के लिए सहयोग संगोष्ठी-एशियाई विकास बैंक (ADB) की वार्षिक बैठक का हिस्सा
- 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी (QFCA) के बीच हुए समझौता ज्ञापन
- भारत-चीन: लद्दाख गतिरोध से सबक
- भारत-अफ्रीका संबंध

अर्थव्यवस्था

- 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना
- वैधानिक मेट्रोलॉजी (पैकेजिंग नियम 2011)
- चार मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया
- RBI ने COVID-19 के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए
- दलहन उत्पादन के लिए खरीफ रणनीति 2021
- व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और MSMEs की COVID से संबंधित तनावग्रस्त समाधान फ्रेमवर्क 2.0
- हिमालय में उगाए गए जैविक बाजरा का डेनमार्क को निर्यात
- 5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों का समय
- आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी
- MSME क्षेत्र की वित्त संबंधी समस्याएं
- कनेक्टेड कॉमर्स: डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोडमैप बनाना
- एस जानकीरमन द्वारा निर्देशित, सलाहकार समूह नियम
- राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22
- सार्वजनिक उपक्रम नीति का पुनर्मूल्यांकन
- सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021
- मोबाइल वॉलेट के माध्यम से ATM से पैसे निकालने की अनुमति

- व्यवसाय का स्थानीयकरण
- कॉर्पोरेट ऋण के लिये व्यक्तिगत गारंटर का दायित्व : SC
- बीमा अधिनियम के तहत अधिसूचित नए नियम
- व्हाइट फंगस
- केंद्र और राज्य सरकार के आय पर कोविड -19 का प्रभाव
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि
- शाही लीची
- भारत की GST के सामने चुनौतियां
- आर्थिक स्लाइड को गिरफ्तार करें
- खाद्य तेल की कीमतों में भारी उछाल
- पेटेंट 'ग्राम चावल'
- गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन

कृषि

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)
- कृषि सहयोग पर भारत-इजरायल समझौता
- सुखियों में फसल: कटहल
- डेयरी क्षेत्र पर संकट

पर्यावरण/ प्रदूषण

- समाचारों में प्रजातियां: जाइलोफिस दीपकी" (Xylophis Deepaki)
- जलवायु परिवर्तन कारकों से पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन
- जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक गैस क्षेत्र
- जलवायु संकट के लिए कोविड-19 महामारी से सबक
- ग्रेट निकोबार द्वीप के लिये नीति आयोग की परियोजना
- जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे पुराने रॉक पेंटिंग का अपक्षय
- A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड
- सभी आक्रामक सफेद मक्खियों की सीमा बढ़ रही है
- लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) का निर्माण
- हैबिटेट गिल्ड्स ने भूमि-उपयोग परिवर्तन का अनुभव किया

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- एशियाई शेरों का हैदराबाद चिड़ियाघर में SARS-CoV2 वायरस के लिए परीक्षण पॉजिटिव
- भारतीय शोधकर्ताओं ने पैंगोलिन शल्क का अनुक्रम किया

- रेलवे लाइन पर हाथी हताहत
- समाचारों में प्रजातियां: रेड-ईयर स्लाइडर
- समाचारों में प्रजातियां: सबडॉलूसेप्स नीलगिरिएन्सिस

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- 5G प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम परीक्षण
- देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली
- एकजीबिशन/प्रदर्शनी स्थलों और कन्वेंशन/सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा
- ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन
- मेकेदातु बहुउद्देशीय परियोजना
- श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावरग्रिड को स्थानांतरित किया

विज्ञान और तकनीक

- कोविड -19 टीकों की ड्रोन डिलीवरी
- नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में परिवर्तित करना
- खाना पकाने के प्रयुक्त तेल (यूसीओ) से उत्पादित बायो-डीजल
- विनकोव-19
- भारत में 5जी परीक्षण
- लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट का पुनः प्रवेश
- 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज डीजीसीआई द्वारा अनुमोदित
- धुआं रहित शवदाह प्रणाली विकसित
- चीन द्वारा मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग
- सुर्खियों में प्रजातियां: कॉमन क्रेन
- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप और क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप

आपदाप्रबंधन

- सार्वजनिक भवन और अग्नि सुरक्षा

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- P-8I गश्ती विमान
- इजराइल का आयरन डोम रॉकेट रक्षा प्रणाली
- मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता
- नियम और शासक: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मई 2021 महीने के क्विज़ अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

पुटोला नाच (Putola Nach)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस – I – संस्कृति

सुर्खियों में-

- पुटोला नाच, असम में प्रचलित स्ट्रिंग या धागा पुतली कला है। हाल ही में, यूनिसेफ-असम के सहयोग से एक ट्रस्ट ने असम में कोविड-19 के संबंध में जन जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला के वीडियो जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह तीन क्षेत्रों में अलग-अलग विशेषताओं के साथ किया जाता है।
- यह कला पश्चिमी असम में बारपेटा-नलबाड़ी, उत्तरी असम में कलाईगांव और पूर्वी असम में माजुली "द्वीप" मुख्यतः प्रचलित है।
- रामायण, या तो इसकी संपूर्णता में या एपिसोड द्वारा, साथ ही साथ महाभारत के दृश्यों का भी प्रदर्शन किया जाता है।
- कठपुतली बजाने वाले स्थानीय पारंपरिक रंगमंच, भाओना से लिए गए संवादों या मंत्रों को जोड़कर खुश होते हैं।

विविध

लाग बी'ओमर (Lag B'Omer)

- लाग बी'ओमर एक वार्षिक यहूदी त्योहार (Jewish festival) है। इसे हिब्रू (Hebrew) के इयार (Iyar) महीने में मनाया जाता है।
- यह ओमेर के 33वें दिन मनाया जाता है, यह पासओवर और शवोत के बीच की 49 दिनों की अवधि है।
- इस अवसर को जानने के लिए, अति-रूढ़िवादी यहूदी तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष माउंट मेरोन के आधार पर जाते हैं, दूसरी शताब्दी के ऋषि और रहस्यवादी रब्बी शिमोन बार योचाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी।
- इजराइल में रब्बी का मकबरा एक बहुत ही पूजनीय पवित्र स्थल है।

उत्तरी असम में बार-बार आने वाले भूकंपों के पीछे चार कारकों में से एक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - भूगोल

सुर्खियों में-

- उत्तरी असम के सोनितपुर क्षेत्र में लगातार भूकंप आने के पीछे चार कारकों में से एक अज्ञात रेखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह रेखांकन एक भू-दृश्य में एक रेखीय विशेषता है जो एक अंतर्निहित भूवैज्ञानिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है जैसे कि एक दोष।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार, सोनितपुर जिला एक विवर्तनिक रूप से जटिल त्रिकोणीय क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो पूर्व-पश्चिम ट्रेंडिंग एथेरखेत फॉल्ट, उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व ट्रेंडिंग कोपिली फॉल्ट और एक उत्तर-दक्षिण ट्रेंडिंग लाइनमेंट से घिरा है।
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने 28 अप्रैल को 6.4 भूकंप के बाद सोनितपुर में 2.6 से 4.7 की तीव्रता के 29 भूकंप दर्ज किए, जिसने कई इमारतों, पुलों और एक नदी तटबंध को क्षतिग्रस्त कर दिया।

क्या आप जानते हैं?

- उत्तर-पूर्वी भारत को भूकंपीय क्षेत्र V के रूप में चिन्हित किया गया है, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र को इंगित करता है।
- भारतीय प्लेट हिमालयी क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रही है, जो उनकी तिरछी टक्कर और स्थानीय टेक्टोनिक या फॉल्ट वातावरण में जमा तनाव के कारण भूकंप आते हैं।

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में नई साइटें जोड़ी गईं

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I - संस्कृति

सुर्खियों में-

- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में छह स्थलों को जोड़ा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साइटें प्रस्तुत की गईं।
- यूनेस्को द्वारा अपनी अस्थायी सूची के लिए नौ में से छह स्थलों को स्वीकार किया गया है।
- किसी भी साइट के अंतिम नामांकन से पहले अस्थायी सूची में जोड़ा जाना एक आवश्यकता है।
- साइटें हैं:
 1. मराठा सैन्य वास्तुकला, महाराष्ट्र
 2. हायरबेन्कल मेगालिथिक साइट, कर्नाटक
 3. नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट-लमेताघाट।
 4. गंगा घाट, वाराणसी
 5. कांचीपुरम के मंदिर
 6. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।
- ये प्रस्ताव एक साल के लिए अस्थायी सूची में रहेंगे जिसके बाद सरकार तय करेगी कि उनमें से किसे यूनेस्को को अपने अंतिम फाइल में प्रस्तुत करना है।

संबंधित आलेख:

- हमपी विश्व धरोहर स्थल
- राखीगढ़ी

दहानु घोलवड़ सपोटा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - भूगोल

सुर्खियों में-

- हाल ही में दहानु घोलवड़ सपोटा (चीकू) चर्चा में था।
- महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणित उत्पाद दहानु घोलवड़ सपोटा की एक खेप यूनाइटेड किंगडम भेज दी गई है, जिससे जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ा बढ़ावा मिला।

महत्वपूर्ण तथ्य

- घोवाद सपोटा का जीआई प्रमाणन महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है।

क्या आप जानते हैं?

- **सपोटा उगाने वाले राज्य-** कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश।
- **उच्चतम उत्पादक:** कर्नाटक, महाराष्ट्र।

कलाक्षेत्र फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - कल्चर

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों के रूप में 12 प्रख्यात कलाकारों और संगीतकारों को नामित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- कलाक्षेत्र फाउंडेशन एक कला और सांस्कृतिक अकादमी है।
- यह विशेष रूप से भरतनाट्यम नृत्य और गंधर्ववेद संगीत के क्षेत्र में भारतीय कला और शिल्प में पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित है।
- यह चेन्नई में स्थित है।
- स्थापना:** 1936
- द्वारा स्थापित:** रुक्मिणी देवी अरुंडेल और उनके पति जॉर्ज अरुंडेल।
- 1994 में, भारत की संसद के एक अधिनियम ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन को "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता दी।
- रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा विकसित भरतनाट्यम की कलाक्षेत्र शैली अपने कोणीय, सीधे, बैसे एक तरह का प्रदर्शन नृत्य (कीनेस्थेटिक्स) है, और रेकास से बचने और अंगों के अबाधित फेंक (कसेपा) के लिए विख्यात है।

Baba's Foundation course (Baba's FC)

FACULTY PROFILE



 Strategy Classes & Answer writing sessions by MOHAN KUMAR B.E (Telecommunications) Involved with Teaching and Mentoring students since 9 years	 Ethics, Society, Internal Security by SUNIL OBEROI Retd. IAS Has worked on Civil Services Reforms in India with UNDP and DoPT and Involved in teaching and mentoring students since 8 years
 Geography by ATYAB ALI ZAIDI B. Tech, NIT, Allahabad. Involved with teaching and mentoring students since 6 Years	 Polity & Governance by SUDEEP T B. Tech Involved with teaching and mentoring students since 6 Years
 Economics by SUMANTH MAKAM MA Involved with teaching and mentoring students since 6 Years	 Economics & International Relations by SPHEERANTH B B.Tech, MS (US) Involved with teaching and mentoring students since 5 Years
 History by ABHISHEK CHAHAR BA (Hons), LLB Involved with teaching and mentoring students since 6 Years	 Environment & Science & Technology by VIPIN MISHRA B.Tech, M.Tech Involved with teaching and mentoring students since 5 years
 Ethics by SANDEEP MA in International Relations Published Paper's in International Journals and mentoring students since 7 years	 CSAT by MANJUNATH BADAGI MBA Renowned Mental Ability Expert Known for his book - Mental Ability

सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर फैसला

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान द्वारा, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द कर दिया गया।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

- 2018 में, 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम' के अंतर्गत मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया गया था।
- यह कानून जून 2019 में आरक्षण के दायरे को 16 फीसदी से घटाकर शिक्षा में 12 और नौकरी में 13 फीसदी तय कर दिया
- इस अधिनियम के लागू होने से राज्य में आरक्षण का लाभ 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
- अदालत ने इस मुद्दे पर कानून के छह प्रश्न तैयार किए थे; यह उन तीन मुद्दों पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ, जबकि फैसले को अन्य तीन पर 3:2 में विभाजित किया गया था।

मुद्दा 1 : इंद्रा साहनी के फैसले पर फिर से विचार करने पर

इंद्रा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को देखते हुए नौ जजों की एससी बेंच ने दो महत्वपूर्ण उदाहरण रखी थीं

- सबसे पहले, अदालत ने कहा कि किसी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने हेतु अर्हता कसौटी उसका "सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन" है।
- दूसरा, अदालत ने ऊर्ध्वाधर आरक्षण की 50% सीमा को दोहराते हुए तर्क दिया, कि यह प्रशासन में "दक्षता" सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह 50% की सीमा "असाधारण परिस्थितियों" छोड़कर लागू होगी।

राज्य सरकार का तर्क: इंद्रा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए 11-न्यायाधीशों की खंडपीठ के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मनमाने ढंग से सीमा का निर्धारण कर दिया गया, जिस पर संविधान में कोई विचार नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अदालत ने कहा है, कि इस मामले पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि हालांकि, वर्ष 1992 में अदालत द्वारा 50% आरक्षण की सीमा का निर्धारण मनमाने ढंग से किया गया था, किंतु यह अब संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। असाधारण परिस्थितियों के बिना 50% से अधिक की अधिकतम सीमा से अधिक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

मुद्दे 2 और 3: क्या अपवाद के तहत मराठा कानून को बचाया जा सकता है

- चूंकि 50% की सीमा को वैध माना जाता है, अदालत ने यह देखा कि क्या मराठा कोटा कानून इंद्र साहनी के मामले में विचार की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आता है।
- अदालत ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पर भी गौर किया कि महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण देते समय भरोसा किया था।

राज्य सरकार का तर्क: चूंकि महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 85% है और आरक्षण की सीमा केवल 50% है, आरक्षण सीमा में वृद्धि एक असाधारण परिस्थिति के रूप में योग्य होगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सभी पांच न्यायाधीश उपरोक्त तर्क से असहमत थे। पीठ ने यह भी पाया कि एम.जी. गायकवाड़ आयोग ने भी अतिरिक्त कोटा को सही ठहराने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मराठा आगे के वर्ग में प्रमुख हैं और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में हैं। उपरोक्त स्थिति कोई असाधारण नहीं है।

मुद्दे 4, 5 और 6: SEBCs की पहचान करने के लिए राज्य की शक्ति और 102वां संशोधन पर

- 102वां संवैधानिक अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है।
- संशोधन राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने का अधिकार भी देता है।

राज्य सरकार का तर्क: इसने संशोधन की व्याख्या पर सवाल उठाए और तर्क दिया कि BC को सूचित करने की राष्ट्रपति की शक्ति राज्यों की उनकी शक्तियों को कम करती है (संघवाद की भावना का उल्लंघन)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बेंच ने 102 वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को सर्वसम्मति से बरकरार रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने की राज्यों की शक्ति प्रभावित होती है।

राष्ट्रपति और राज्यों की शक्ति के संबंध में बहुमत का फैसला

- **राष्ट्रपति के साथ अंतिम राय:** पीठ के तीन न्यायाधीशों का विचार था कि SEBCs के समावेश या बहिष्करण (या सूचियों में संशोधन) के संबंध में अंतिम निर्णय पहले राष्ट्रपति के पास होता है, और उसके बाद, संशोधन या सूची से बहिष्करण के मामले में शुरू में प्रकाशित, संसद के साथ।
- **राज्यों के लिए स्थान:** उन्होंने यह भी कहा कि SEBCs की पहचान केंद्र के रूप में की जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों आरक्षण की सीमा निर्धारित करने और "सहकारी संघवाद" की भावना में विशिष्ट नीति बनाने की शक्ति रखती हैं।
- **नई SEBC सूची:** न्यायमूर्ति भट की बहुमत की राय यह कहती है कि अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्यों और केंद्रीय सूची दोनों के लिए SEBCs की एक नई सूची प्रकाशित करनी चाहिए।

असहमति का दृष्टिकोण: न्यायमूर्ति भूषण और न्यायमूर्ति नजीर ने, संशोधन के पाठ पढ़ने को प्राथमिकता दी और कहा कि यह SEBCs की पहचान करने के लिए राज्य की शक्तियों को नहीं लेता है।

उपरोक्त निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण

- **50% की सीमा पार करने से जाति बनी रह सकती है:** SC ने कहा कि "50% की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसे समाज का होना है जो समानता पर नहीं बल्कि जाति नियम पर आधारित हो"।
- **समानता को बरकरार रखा गया:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 50% बेंचमार्क को कम करने के लिए, समानता की गारंटी को प्रभावी ढंग से नष्ट करना होगा, विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार (अनुच्छेद 15 और 16 के तहत)।
- **अस्थिर उतार :** SC ने यह भी देखा कि यदि आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर जाता है तो यह फिसलन वाला ढलान होगा और राजनीतिक दबाव इसे कम करना मुश्किल बना देगा।
- **इसी तरह के कानून की जांच की जाएगी:** "असाधारण परिस्थितियों" की श्रेणी के तहत 50% की सीमा से अधिक आरक्षित करने वाले विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कई कानूनों पर इस फैसले का प्रभाव होने की संभावना है।
- **EWS आरक्षण पर प्रभाव:** इस फैसले का प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर भी पड़ सकता है, जिसे केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 50% की सीमा से अधिक में पेश किया है।

संबंधित लेख पढ़ें

- आंध्र प्रदेश लोकल फर्स्ट पॉलिसी
- मध्य प्रदेश अधिवास आधारित कोटा
- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है

विकेंद्रीकरण और कोविड

संदर्भ: हमें अपने देश को तबाह कर रहे कोविड सेकेंड वेव के ज्वार को मोड़ने के लिए गति और चपलता के साथ प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है।

विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के गुण

- **स्थानीय जानकारी :** स्थानीय निकायों को स्वतंत्रता देना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें कोविड जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीन पर सूचना, निगरानी और तत्काल कार्रवाई का लाभ मिलता है।

- विकेंद्रीकरण स्वामित्व और जिम्मेदारी के बंटवारे को प्रोत्साहित करता है, जबकि एक केंद्रीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल दृष्टिकोण संकट के फैसले के लिए अधिकार के वैकल्पिक स्रोतों के लिए पैसे की ओर इंगित करता है।
- **सामुदायिक भागीदारी :** यदि कोविड-उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है, तो इसके लिए पूरे देश में सामुदायिक स्तर पर सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी।
- **सफलता की कहानियों से सबक:** कोविड की पहली लहर के दौरान विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने 'केरल मॉडल', 'भीलवाड़ा मॉडल', 'धारावी मॉडल' या 'कर्नाटक मॉडल' जैसी सफलता की कहानियों का निर्माण किया। इसी तरह का सबक इस बार सफल मॉडलों (उदाहरण: केरल मॉडल) से सीखने की जरूरत है।
- **टीयरिड टीके का मूल्य निर्धारण:** केंद्र और राज्य सरकारों को एक समान कीमत पर टीकों की पेशकश की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र को खरीदे गए वॉल्यूम के आधार पर मूल्य नम्यता प्रदान किया जा सकता है। इससे टीकाकरण अभियान को गति मिल सकती है।

दोषियों को उनके घरों में नजरबंद करने पर विचार करें: उच्चतम न्यायालय

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - विधानमंडल; न्यायतंत्र

सुर्खियों में-

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने, विधायिका से जेलों में अत्याधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए दोषियों को उनके घरों में नजरबंद करने पर विचार करने के लिए कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की एक खंडपीठ और के.एम. जोसेफ ने एक फैसले में जेलों के "खतरनाक" आंकड़ों पर प्रकाश डाला।
- यह सुझाव COVID-19 के प्रसार को देखते हुए प्रासंगिक है।
- कुछ दिन पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना के नेतृत्व में एक पीठ ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल देने सहित कई निर्देश जारी किए।
- जेलों में अत्याधिक भीड़भाड़- अर्थात्, जेलों में कैदियों के रहने की दर, वर्ष 2019 में बढ़कर 118.5% हो गई।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 18,86,092 कैदियों को जेलों में भर्ती कराया गया था।
- वर्ष 2019 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,30,487 थी, जोकि कुल कैदियों की संख्या का 69.05% है।
- बजट में एक बहुत बड़ी राशि (₹6818.1 करोड़) जेलों के लिए निर्धारित की गई थी।
- जेलों की अधिक भीड़भाड़ और ज्यादा बजट दोनों ही हाउस अरेस्ट की संभावनाओं के संदर्भ में प्रासंगिक थे।

राजनेताओं से सीख

संदर्भ: भारत की सिविल सेवा को भयावह कोरोनावायरस महामारी के आलोक में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे मौजूदा संरचनाएं और प्रक्रियाएं अप्रभावी हो गई हैं।

सिविल सेवक को राजनेताओं से निम्नलिखित सीखने की आवश्यकता है:

1. स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता : सरकार की दृष्टि को स्पष्ट करने, या नीतिगत निर्णय के लाभों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी। सिविल सेवक को संदेश को एक कहानी के रूप में (राजनेताओं की तरह) इसे और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए जनता तक पहुंचाने की जरूरत है।

2. सुनने की क्षमता: राजनेता अच्छे श्रोता होते हैं, जो एक कला है, और घंटों सुन सकते हैं। आम नागरिक के लिए, सिर्फ सुना जाना एक बेहद सशक्त अनुभव है, और नौकरशाहों के शासन को संवेदनशील और लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इस कला का अभ्यास करना चाहिए।

3. जटिल विचारों को सरल बनाने की क्षमता, जबकि इसके मूल के साथ कभी भी संपर्क नहीं खोना एक कौशल है जिसमें सफल राजनेताओं को महारत हासिल होता है। उन्हें इस समस्या की जड़ तक सरलता से पहुंचने और लेकिन जमीनी समाधान प्रस्तावित करने की अनुमति देना है।

4. भावनात्मक रूप से बुद्धिमत्ता: एक जन प्रतिनिधि की एक बड़ी विशिष्ट विशेषता उसका निर्णायक रूप से बेहतर पारस्परिक कौशल और मानवीय स्पर्श प्रदान करने की क्षमता है, विशेष रूप से वंचितों और हाशिए लोगों के लिए।

5. कर्तव्य के प्रति समर्पण: जनता की भलाई की धारणाओं से प्रेरित, आदर्श राजनेता बदल देने वाला परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अधिक तेजी से बेचैन समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्तव्य के प्रति और अधिक समर्पण की आवश्यकता होती है। इसे सिविल सेवकों में भी दोहराया जाना है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - संविधान
सुर्खियों में-

- अनुच्छेद 311 हाल ही में खबरों में था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नियुक्त किया था।
- अनुच्छेद की धारा 2 में कहा गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।
- अनुच्छेद 311 (2) (a) के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे एक विभागीय जांच के बिना बर्खास्त किया जा सकता है।
- 311 (2) (c) के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना सुविधाजनक नहीं है।

क्या आप जानते हैं?

- एक विभागीय जांच (DE) में, एक जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद, सिविल सेवक को आरोपों का औपचारिक आरोप पत्र दिया जाता है।
- सिविल सेवक स्वयं का प्रतिनिधित्व कर सकता है या वकील रख सकता है।

जीवन के अधिकार को प्राथमिकता

संदर्भ: भारत की अधिकांश कामकाजी आबादी आज कई संकटों के प्रभाव से जूझ रही है: एक स्वास्थ्य आपातकाल; बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान, काम से आय में गिरावट; और बड़े पैमाने पर भूख तथा बिगड़ती पोषण में काफी वृद्धि हुई है।

हंगर वाच' सर्वे के अनुसार

- पिछले साल लॉकडाउन हटने के बाद भी, दो-तिहाई परिवारों ने लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने और स्वस्थ भोजन में कमी की सूचना दी।
- सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से एक चौथाई की आय आधी हो गई।
- यह भी पाया गया कि भूख, ग्रामीण की तुलना में शहरी भारत में अधिक थी।

- न्यायपालिका, भूख और जीवन का अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को केंद्र और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सभी प्रवासी कामगारों को आईडी प्रूफ पर बल दिए और मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने और दिन में दो बार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने वाली रसोई चलाने का निर्देश दिया।
- निर्देश से पता चलता है कि शीर्ष अदालत ने देश में भूख के संकट को स्वीकार किया है जिसके लिए तत्काल राज्य कार्रवाई की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रत्यक्ष की कमियां:

- इसने पूरे देश में इस सुविधा का विस्तार नहीं किया;
- इसने भोजन और राशन के अलावा राज्य द्वारा नकद भुगतान को कवर करने की सुविधा का विस्तार नहीं किया;
- इसने सुविधा को अधिकार के बजाय राज्य की उदारता बना दिया।
- अगर उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार से प्राप्त अपने फैसले के आधार के रूप में आजीविका के सार्वभौमिक अधिकार को मान्यता दी होती, तो उपरोक्त तीन कमियों को दूर किया जा सकता था।

वैक्सीन नीति और जीवन का अधिकार

- अपने जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए COVID-19 के खिलाफ टीका लगवाना आवश्यक है।
- सरकार को सभी के जीवन के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और प्राप्तकर्ता के भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना वैक्सीन को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।
- भारत निजी क्लिनिकों में इन टीकों को लगाने के लिए लोगों (18-45 वर्ष की आयु) को भुगतान कर रहा है। इसकी तुलना अमेरिका (अधिकांश निजीकृत चिकित्सा प्रणालियों) से करें, जहां सभी को टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

भारत की वैक्सीन नीति में क्या गलत हुआ?

- सरकार ने अधिक उत्पादकों को अनिवार्य लाइसेंस देकर पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया।
- इसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मूल्य वृद्धि की अनुमति दी।

आगे की राह

- राज्य को ऐसे कई उपाय करने की आवश्यकता है जो जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दें, जो सुनिश्चित (और न्यायसंगत) आर्थिक सुधार शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका भी है।
- नियमित औपचारिक रोजगार के बिना कम से कम तीन महीने के लिए प्रति परिवार लगभग ₹7,000 का मासिक नकद हस्तांतरण, मुफ्त भोजन और राशन के प्रावधान के अलावा।
- COVID-19 टीकों के उत्पादन और केंद्रीय खरीद का विस्तार, और सभी को मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्यों को वितरण;
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए संसाधनों में वृद्धि करना ताकि उनके कार्यक्रमों के पुनरुद्धार और विस्तार को सक्षम बनाया जा सके।
- मनरेगा को शुद्धतया से मांग आधारित बनाना, जिसमें प्रति परिवार दिनों की संख्या या लाभार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
- शहरी भारत को समानांतर मनरेगा जैसी योजना के साथ कवर करना जो शिक्षित बेरोजगारों को भी पूरा करेगी।

- केवल शीर्ष 1% परिवारों पर लगाया गया 1.5% संपत्ति कर सरकार के उपरोक्त उपायों को निधि देने के लिए पर्याप्त होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैक्सीन राष्ट्रवाद
 - वैक्सीन कूटनीति
-

यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अधिनियम और नीतियां

सुर्खियों में-

- हाल ही में उत्तर प्रदेश (यूपी) सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाराबंकी, यूपी में एक मस्जिद के ध्वस्त किए जाने पर कड़ी निंदा की और इसकी बहाली की मांग की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत गठित एक निकाय है।
- यह सुन्नी मुस्लिम वक्फ (दान) संपत्तियों, वक्फ संस्थानों और यूपी के सुन्नी मुस्लिम समुदाय के विवाह रिकॉर्ड के मामलों का प्रबंधन करता है।
- यह बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद में मुख्य मुस्लिम वादी रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- एक वक्फ (जिसे वक्फ या हबस भी कहा जाता है) इस्लामी कानून के तहत एक अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती है।
 - वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई।
 - भारत में "बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर" सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है।
-

सुरक्षा कवर प्रदान करने का राजनीतिकरण

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा भाजपा के 77 विधायकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का हालिया आदेश, जो इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुने गए थे, न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि राजनीति से प्रेरित भी है।

अतिक्रमण नियम

- व्यवहार में, खतरे में व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय गृह मंत्रालय में एक समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो (आईबी), दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
- जबकि आईबी खतरे में पड़े व्यक्तियों और खतरे की डिग्री की सूची तैयार करता है, समिति उस स्थान के आधार पर तैनात किए जाने वाले बल पर निर्णय लेती है जहां व्यक्ति स्थित है।
- इन बैठकों में, सुरक्षित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की खतरे की धारणा पर एक-एक करके चर्चा की जाती है, न कि किसी समूह के लिए सामूहिक रूप से।
- प्रत्येक व्यक्ति (77 भाजपा विधायक) के लिए खतरे की धारणा पर चर्चा नहीं की गई, जिससे राजनीतिक प्रेरणाओं के संदेह को उजागर किया गया।

क्या इस तरह की व्यापक सुरक्षा पहले प्रदान नहीं की गई थी?

- बीते दिनों में, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की ऐसी तैनाती पंजाब और जम्मू-कश्मीर में की जाती थी, जब ये क्षेत्र अशांति और उग्रवाद से प्रभावित थे।

- चूंकि उग्रवादियों ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की, इसलिए आम तौर पर चुनावी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जाता था।
- इसलिए, केंद्र सरकार ने चुनाव खत्म होने तक प्रत्येक उम्मीदवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक निर्णय लिया।

वर्तमान कदम का निहितार्थ

- **केंद्र-राज्य संबंधों के लिए अस्वस्थ संकेत:** कानून-व्यवस्था और विधायकों सहित नागरिकों की सुरक्षा राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्रीय बलों को तैनात करके केंद्र ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भाजपा विधायकों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है।
- **अन्य पुलिस बलों के लिए अनुपयुक्त संकेत:** केंद्र सरकार का उन अधिकारियों के प्रति अविश्वास जो किसी राज्य की सत्ता के करीब माने जाते हैं, देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।
- **संरक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि:** 2019 में, 43,556 कर्मियों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले, 19,467 मंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायाधीशों और नौकरशाहों की सुरक्षा के लिए 66,043 पुलिस और CAPF कर्मियों को तैनात किया गया था।
- **प्रभाव प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सुरक्षा कर्तव्यों पर CAPF कर्मियों की लगातार तैनाती उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करती है। वीआईपी सुरक्षा के लिए शुरुआत के आठ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, कर्मियों को अपने कौशल को सुधारने के लिए समय-समय पर दो सप्ताह के दोबारा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।
- **प्रतिष्ठा का प्रतीक:** सुरक्षा कवर होना अब स्टेटस सिंबल बन गया है जो समाज की लोकतांत्रिक संस्कृति के साथ अच्छा नहीं है, जहां हर कोई समान है।

आगे की राह

- अपने आसपास सुरक्षा कर्मियों की मांग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों को खर्च वहन करने के लिए कहा जाना चाहिए,
- संसद सदस्यों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं से उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों से शुल्क लिया जाना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) में सुधार के सुझाव देने के लिए पैनल का गठन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (Indian Broadcasting Foundation) का नाम बदलकर (Indian Broadcasting and Digital Foundation) के नाम से जाना जाएगा।
- आईबीएफ प्रसारकों का यह शीर्ष निकाय है।
- अब यह डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रहा है

महत्वपूर्ण तथ्य

- चूंकि आईपीसी में "अभद्र भाषा" की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, आपराधिक कानूनों में सुधार समिति पहली बार इस तरह के भाषण को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है।

क्या आप जानते हैं?

- ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें अभद्र भाषा को "एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों (जैसे यौन अभिविन्यास या विकलांगता या धर्म आदि)। ”

- टी.के. विश्वनाथन समिति का गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A के मद्देनजर किया गया था, जिसने 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त की जा रही संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड प्रदान किया था।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) का नाम बदलना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (Indian Broadcasting Foundation) का नाम बदलकर (Indian Broadcasting and Digital Foundation) के नाम से जाना जाएगा।
- आईबीएफ प्रसारकों का यह शीर्ष निकाय है।
- अब यह डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रहा है

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कदम से ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म एक ही आधार के नीचे आ जाएंगे।
- COVID-19 महामारी के बाद OTT ने अपने दर्शकों की संख्या में पर्याप्त उछाल देखा है।
- IBDF डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक स्व-नियामक निकाय, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (DMCRC) भी बनाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) की स्थापना 1999 में हुई थी।
- यह प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) का मूल संगठन है जिसे 2011 में स्थापित किया गया था।
- BCCC भारत में सभी गैर-समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधित सामग्री संबंधी शिकायतों की जांच करता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- ओवर-द-टॉप (OTT) मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली मीडिया सेवा है।
 - ओटीटी केबल, प्रसारण और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को दरकिनार कर देता है।
 - जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि।
-



PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) - 2021

PRELIMS STRATEGY CLASSES BY SUNIL OBEROI - Retd. IAS

Has worked on civil services reforms in India with UNDP and DOPT. Was associated with induction training of new entrants of civil services and in-service training of senior civil servants.



सामाजिक मुद्दे/ वेलफेयर

डिजिटल युग में महामारी और असमानता

संदर्भ: नोवेल कोरोनावायरस महामारी ने भारत में डिजिटल तकनीकों के उपयोग को तेज कर दिया है, यहां तक कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी, जहां उनकी पहुंच खराब हो सकती है।

शिक्षा सम्बंधित डिजिटल मुद्दे

- **कंप्यूटर की जानकारी :** 2017 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, केवल 6% ग्रामीण और 25% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है।
- **इंटरनेट की जानकारी:** पिछले चार वर्षों में डेटा वाले स्मार्टफोन की जानकारी हुई है, फिर भी सबसे कमजोर लोगों में अभी उपयोग में नहीं है। इंटरनेट सुविधाओं की जानकारी भी सार्वभौमिक नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 17% और शहरी क्षेत्रों में 42% तक है।
- **इनकी जानकारी में संरचनात्मक बाधाएं:** अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार, 27% से 60% के बीच कई कारणों से ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी नहीं है, उपकरणों की कमी, साझा डिवाइस, "डेटा पैक" खरीदने में असमर्थता आदि।
- **लड़कियों पर अधिक भार:** लड़कियों के लिए यह अतिरिक्त अपेक्षा रहती है कि यदि वे घर पर हैं तो घरेलू कामों में योगदान देंगी।
- सीखने के ऑनलाइन प्रणाली में बदलाव के कारण पीयर लर्निंग को भी नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य में डिजिटल मुद्दे

- **विकासशील ऐप को समाधान के रूप में देखा जाता है:** अभी आवश्यक वस्तुओं की कमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है: दवाएं, अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन, टीके। कई उदाहरणों में, एक ऐप विकसित करना विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के आवंटन के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
- **अतिरिक्त नौकरशाही:** डिजिटल "समाधान" इन सेवाओं की तलाश में सभी बीमार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त नौकरशाही का निर्माण करते हैं। कागजी कार्रवाई के साथ-साथ मरीजों को डिजी-वर्क भी करना होगा।
- **गरीब और अनपढ़ के लिए चुनौतियाँ:** प्लेटफॉर्म और ऐप-आधारित समाधान गरीबों को पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं, या दुर्लभ स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच को और कम कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के लिए CoWIN का उपयोग फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना उन लोगों के लिए बहुत कठिन बना देता है।

निष्कर्ष

- डिजिटल समाधान कोई जादू की गोली नहीं है जो महामारी की सभी समस्याओं का समाधान करती है। डिजिटल समाधान केवल हमारे देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने का साधन है।

कोविड संकट के मद्देनजर ग्रामीण अनिवार्य

संदर्भ: मुख्य खरीफ बुवाई का मौसम जून के मध्य से ही मानसून की बारिश के आगमन के साथ शुरू होगा।

2020-21 में कृषि क्षेत्र

- वर्ष 2020-21 असाधारण था, जहां कृषि क्षेत्र में 3% का विस्तार हुआ, यहां तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में 6.5 और अनुबंधित किया गया।
- कृषि निर्यात में भी 17.5% की वृद्धि हुई, जबकि देश के कुल व्यापारिक माल के मूल्य में 7.2 की गिरावट आई।
- 2020-21 में ग्रामीण मांग में ट्रैक्टर, FMCG और सीमेंट कंपनियों जैसे उद्योगों ने उच्च प्रदर्शन किया।
- अंतिम परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण भारत ने अर्थव्यवस्था के लिए एक गद्दी प्रदान की, जिसे आजादी के बाद से सबसे खराब मंदी और 1979-80 के बाद पहली बार झेलनी पड़ी।

उपरोक्त परिदृश्य के कारण

- **महामारी का कम प्रभाव:** पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड -19 मामले बहुत कम थे और सरकार ने कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी थी
- **अनुकूल मानसून:** एक अन्य कारण उत्कृष्ट बारिश और अनुकूल सर्दियों का तापमान था जिससे किसानों को बंपर फसल लेने में मदद मिली।
- **सरकार द्वारा सही हस्तक्षेप:** सबसे पहले, सरकार ने गेहूं, धान, सरसों और रबी दालों की बड़े पैमाने पर खरीद की, जिन्हें लॉकडाउन के बाद विपणन किया गया था। दूसरा रिकॉर्ड 389.37 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार था जो 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत उत्पन्न हुआ। इन दोनों के साथ, पीएम-किसान के तहत प्रति किसान 6,000 रुपये का नकद हस्तांतरण हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित हुई।

इस साल क्या होगा परिदृश्य?

- भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है, जबकि FAO's का विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल में 83 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इन दोनों मोर्चों पर वर्षा और कीमते इस प्रकार कृषि के लिए दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है।
- पिछले साल कृषि क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई कुशन की उपलब्धता आज संदेह के घेरे में है, महामारी की दूसरी लहर ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं बख्शा रही है।
- इस साल गेहूं को छोड़कर एमएसपी खरीद की ज्यादा जरूरत नहीं है।
- जब कोविड ने ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पैठ बना ली है तब मनरेगा के कार्यों का दायरा भी सीमित है।

निष्कर्ष

- यदि खरीफ की बुवाई के मौसम से वर्तमान लहर कम हो जाती है, तो चीजें बहुत खराब नहीं होनी चाहिए।
- सरकार का ध्यान नकद हस्तांतरण पर अधिक होना चाहिए। JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए अब से बेहतर समय नहीं है।

बाल विवाह और महामारी

संदर्भ: हाल ही में जारी ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2020 (The Global Girlhood Report 2020) के अनुसार कम से कम आधा मिलियन (half-a-million) लड़कियों को जबरन बाल विवाह का शिकार होने का खतरा है। सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट (Save the Children report) कहती है कि अगले पांच साल में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों की शादी जल्दी हो सकती है।

महामारी और बाल विवाह

- **बढ़ी हुई गरीबी का सीधा संबंध बाल विवाह से है:** महामारी से आर्थिक संकट में, कमजोर परिवारों को एक लड़की, भूख और अभाव की संभावना के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक लड़की को एक बोझ माना जाता है, जिससे वह जल्दी विवाह के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- **विवाह को सुरक्षित जाल के रूप में देखा जाता है:** कई सर्वेक्षणों में माता-पिता द्वारा उद्धृत एक कारण यह है कि विवाह एक ऐसे समय में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है जब कई युवा नौकरी से बाहर हैं और युवा लड़कियों के लिए खतरा बन रहे हैं।
- **बाधित शिक्षा:** स्कूल कब खुलेंगे, इस बारे में इतनी अनिश्चितता के साथ, लड़कियों के स्कूल नहीं लौटने की पूरी संभावना रहती है और इससे उनकी जल्दी शादी होने का खतरा बढ़ जाता है।
- **काउंसलर तक पहुंच का अभाव:** स्कूलों के सुरक्षित सम्बंधित जाल के बिना, लड़कियों को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है, तो शिक्षक या परामर्शदाता के साथ किसी भी संभावित संचार से हट जाता है। उनमें से अधिकांश के पास चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंच नहीं है, हालांकि सरकार ने इन्हें स्थापित किया है।

बाल विवाह के परिणाम

- बाल विवाह न केवल लड़कियों के मानवाधिकारों और उनके बच्चों का उल्लंघन है, बल्कि देशों के लिए एक पर्याप्त आर्थिक बोझ का भी प्रतिनिधित्व करता है (प्रारंभिक बाल विवाह => अधिक बच्चों की प्रवृत्ति => उच्च जनसंख्या वृद्धि)
- कम उम्र में शादी करने से घरेलू गुलामी, पति-पत्नी की हिंसा और खराब स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों में शारीरिक हिंसा का अनुभव होने की संभावना लगभग 50% अधिक होती है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और इसमें नया संशोधन
-

ग्रामीण क्षेत्र और कोविड -19 की दूसरी लहर

संदर्भ: कोविड -19 से प्रभावित बड़े शहर अब दूसरी लहर से उबरने के शुरुआती संकेत दिखा रहे हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को लेकर अब चिंता बढ़ रही है जहां वायरस ने जगह बना ली है।

पहली लहर के दौरान, वायरस का ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से फैला नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि-

- प्रतिबंधित यात्रा , निर्धारित या स्वैच्छिक, लॉकडाउन हटने के बाद भी लागू रहे।
- क्योंकि ग्रामीण आबादी में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी सह-रुग्णताएं कम हैं, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा भी कम था।

हालाँकि, दूसरी लहर के दौरान, COVID-19 की गंभीरता के बारे में आत्मसंतुष्टि और नए उपभेदों के उद्भव ने ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में लचर स्वास्थ्य प्रणालियों के कारण भारत को दूसरी लहर का सामना करना पड़ा।

- अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना
- प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यबल की कमी
- दवाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की खराब उपलब्धता,
- कई जिलों में उच्च स्तर की देखभाल के लिए खराब कनेक्टिविटी की कमी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी लहर से निपटने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?

- लक्षण निगरानी और मामले का पता लगाने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर का दौरा।
 - स्थानीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जहां उपलब्ध हो, वहां NSS और NCC संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। समुदाय-आधारित संगठन, जिनकी जमीनी स्तर पर उपस्थिति है, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के वितरण में सहायता कर सकते हैं।
 - कम से कम छह महीने के लिए होने वाली बड़ी सभाओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
 - विकेंद्रीकृत, डेटा-संचालित निर्णय लेना
 - रीयल-टाइम अलर्ट और जल्द प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक डेटा स्थानीय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
 - अधिक विस्तृत (सर्वोत्तम) डेटा सेट पाठ्यक्रम सुधार और संसाधन आवंटन के लिए राज्य के पूंजी स्तर पर प्रवाहित हो सकते हैं।
 - स्थानीय स्तर पर, मुख्य मुखबिरों के साक्षात्कार से प्राप्त गुणवत्तापरक सूचना को बाधाओं और समाधानों की पहचान करने में मदद करने के लिए मात्रात्मक डेटा का पूरक होना चाहिए।
-

जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शिक्षा

सुर्खियों में-

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की शुरुआत शामिल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को कौशल प्रदान करना।
- **विजन:** एक समावेशी, कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना,
- समझौता ज्ञापन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) और आश्रम स्कूलों जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 ईएमआरएस स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट ने गोद लिया है, जिसमें से 50 ईएमआरएस स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainer) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- भारत में राज्यों के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा।

रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी

संदर्भ: COVID-19 संक्रमण की लगातार दूसरी लहर से प्रभावित, भारत ने कई राज्यों में स्थानीय लॉकडाउन देखा है।

क्या आपको पता है?

- श्रम भागीदारी दर (LPR) जनसंख्या के उस वर्ग का माप है जो नौकरी लेने के लिए इच्छुक है।
- बेरोजगारी एक उपसमुच्चय है, जो उन लोगों का एक माप देने में मदद करता है जो नौकरी करने के इच्छुक हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं।

लॉकडाउन ने नौकरियों को कैसे प्रभावित किया है?

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, मार्च 2021 में बेरोजगारी दर 6.5% थी, लेकिन अप्रैल में बढ़कर लगभग 8% हो गई, जिस महीने कई राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी थी या पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था।
- अप्रैल 2020 में, जो पिछले साल राष्ट्रीय लॉकडाउन का पहला महीना था, बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% हो गई थी।

बेरोजगारी में ग्रामीण-शहरी बदलाव	• 7.13% पर, अप्रैल 2021 के लिए ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.8% के शहरी आंकड़े से कम है। • मई के महीने में राष्ट्रीय स्तर पर दरों में और वृद्धि हुई है। 21 मई तक, समग्र बेरोजगारी के लिए 30-दिवसीय गतिशील औसत 10.3 प्रतिशत थी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक आंकड़े क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 9.4% थे।
बेरोजगारी में लैंगिक भिन्नता	• महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुरुषों की तुलना में कम श्रम भागीदारी और महिलाओं के लिए उच्च बेरोजगारी दर (15 वर्ष से अधिक आयु के लिए) होती है। • जनवरी-अप्रैल 2021 की अवधि में, शहरी पुरुष की 64.8% की तुलना में शहरी महिला LPR 7.2% थी, जबकि शहरी पुरुष बेरोजगारी दर 6.6% के मुकाबले शहरी महिला बेरोजगारी 18.4% थी, जैसा कि CMIE के आंकड़ों से पता चलता है।
कृषि क्षेत्र	• पहली लहर के दौरान कृषि बचत की कृपा थी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान ऐसा नहीं है।

	● अप्रैल 2020 में इस क्षेत्र में नौकरियों को जोड़ने वाला एकमात्र क्षेत्र देखा गया - कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या, वित्त वर्ष 2020 में औसत गणना की तुलना में 6 मिलियन या 5% बढ़ गई थी। ● मनरेगा आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में नौकरियों की मांग में वृद्धि देखी गई, इसमें 2.7 करोड़ परिवारों ने काम के लिए साइन किया, जो एक साल पहले 1.3 करोड़ से बढ़ रहा था - श्रम के रिवर्स माइग्रेशन के रूप में उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में लोगों की उपलब्धता हुई।
वेतनभोगी वर्ग	● CMIE के आंकड़ों के अनुसार, महामारी शुरू होने के बाद से वेतनभोगी नौकरियों का संचयी नुकसान 12.6 मिलियन आंका गया है।
राज्यों में भिन्नता	● CMIE के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 35% दर्ज की गई, इसके बाद राजस्थान में 28%, दिल्ली में 27.3% और गोवा में 25.7% थी। ● महत्वपूर्ण रूप से, गुजरात, जिसने उपरोक्त राज्यों की तरह, महामारी की दूसरी लहर की तीव्रता को भी देखा, यहाँ बेरोजगारी 1.8% के काफी निचले स्तर पर देखी गई।

बढ़ती बेरोजगारी के परिणाम क्या हैं?

- पारिवारिक आय में कमी
- गरीबी स्तर में वृद्धि
- **बढ़ी हुई भुखमरी** : हंगर वॉच सर्वेक्षण से पता चला है कि सर्वेक्षण किए गए 66% परिवारों के पास पिछले साल के लॉकडाउन के पांच महीने बाद भी खाने के लिए कम था।
- **बढ़ा हुआ कर्ज स्तर**: परिवार इस झटके का सामना बड़े पैमाने पर अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेकर और संपत्ति बेचकर करते हैं।
- कमजोर उपभोक्ता भावना - मांग को झटका - अस्थिरता का नुकसान, कम विवेकाधीन खर्च और इन्वेंट्री संचय।
- उम्मीद से कम आर्थिक सुधार

आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सरकारों द्वारा किए गए उपाय

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह पूरे देश में राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल और गेहूं मुफ्त में वितरित करेगी। अलग-अलग राज्यों ने इसे जोड़ा है।
- कर्नाटक ने 1,250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके माध्यम से किसानों, ऑटो, टैक्सी और मैक्सी कैब ड्राइवर्स, निर्माण श्रमिकों और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को एकमुश्त अंश के रूप में अलग-अलग राशि प्राप्त होगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

भारत में मंदी

भारतीय जेल

प्रसंग: जेल, यह प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, समाज का आईना रखती है।

भारतीय जेल प्रणाली के मुद्दे

- भीड़भाड़ वाली जेलें- औसतन सीमा से कम से कम 118 प्रतिशत अधिक
- खराब स्वच्छता की स्थिति

- अंतरिम चिकित्सा जमानत की दलीलें अक्सर अदालतों द्वारा टाल दी जाती हैं
- भीड़भाड़ वाली जेलों को बनाए रखने के लिए राजकोष की बढ़ती लागत।

हाउस अरेस्ट का विकल्प

- सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से उन मामलों में सक्रिय रूप से हाउस अरेस्ट के विकल्प का उपयोग करने का आग्रह किया जहां "आयु, स्वास्थ्य की स्थिति और आरोपी की पूर्ववृत्त" एक मानदंड है।
- स्वतंत्र भारत में, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह निवारक निरोध के अधीन होते हैं, तो घर में नजरबंदी का उपयोग आंदोलन को प्रतिबंधित करने और निगरानी सुनिश्चित करने के साधन के रूप में किया जाता है।

हाउस अरेस्ट से चिंता

- घर में नजरबंद होने पर भी, कुछ ऐसे होंगे जो यह मानेंगे कि कारावास बहुत उदार है जबकि अन्य लोग इसे बहुत अपमानजनक मानते हैं।
- भारत में एक संबंधित मुद्दा यह है कि कुछ सरकारों ने राजनीतिक बंदियों के मुद्दे के बारे में एक कानूनी समझ विकसित की है।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक समाज हमेशा विकसित होते हैं। इस विकास में सार्वजनिक दृष्टिकोण और अपराधों की परिभाषाओं में बदलाव शामिल हैं: कभी-कभी वे कठोर और विस्तार हो जाते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पुलिस सुधार और महत्वपूर्ण न्यायिक अभिनेता



IAS baba

BABAPEDIA

(Prelimspedia + Mainspedia) 2021

One Stop Destination For UPSC Current Affairs
(Prelims And Mains)







CONTACT US: ✉ ilp@iasbaba.com ☎ 8429688885 | 9169191888

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)

बारे में-

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) का मतलब सूक्ष्मजीव से है जो बैक्टीरिया, कवक, वायरस या परजीवी आदि हो सकते हैं इन्हीं सूक्ष्मजीव के द्वारा एंटीमाइक्रोबॉयल दवाओं (जैसे एंटी फंगल, एंटीमाइरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक तथा एंटीहेलमिंटिक्स) के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेते हैं जिसका परिणाम किसी भी उपचार को अप्रभावी करना है इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
- रोगाणुओं में दवा प्रतिरोध कई कारणों से सामने आता है। इसमें शामिल है
 - दवा में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग
 - कृषि में अनुपयुक्त उपयोग
 - दवा निर्माण स्थलों के आसपास अगर संदूषण शामिल होता है, वहां अनुपचारित अपशिष्ट से ज्यादा मात्रा में एक्टिव रोगाणुरोधी वातावरण में मुक्त हो जाते हैं।

चिंता-

- **चिकित्सा प्रगति को नष्ट कर देता है:** AMR आधुनिक चिकित्सा के लिए एक संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।
- **बढ़ी हुई मृत्यु दर:** AMR हर साल 7, 00,000 लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार है। एएमआर से नवजात और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होगी।
- **आर्थिक नुकसान:** जब तक इस खतरे को दूर करने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए जाते, हम जल्द ही एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं, जिसमें 10 मिलियन वार्षिक मौतें और 2050 तक 100 ट्रिलियन डॉलर तक की लागत शामिल है।

आगे की राह

- **व्यापक निगरानी ढांचा:** रोगाणुओं में प्रतिरोध के प्रसार को ट्रैक करने, इन जीवों की पहचान करने, देखभाल उपायों को अस्पतालों से परे विस्तारित करने और पशुधन, अपशिष्ट जल और खेत के अपवाह को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **सतत निवेश:** अंत में, चूंकि रोगाणु हमेशा विकसित होते रहेंगे और नए रोगाणुरोधी भी प्रतिरोधी बनेंगे, इसलिए हमें निरंतर आधार पर नए प्रतिरोधी उपभेदों का पता लगाने और उनसे निपटान के लिए निरंतर निवेश और वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है।
- **बहु-क्षेत्रीय समन्वय:** AMR अब केवल स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि कृषि, व्यापार और पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ाव की आवश्यकता है। क्लीनिकल चिकित्सा में समाधान कृषि, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण में AMR की बेहतर निगरानी के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

भारत में चिकित्सा ऑक्सीजन संकट

संदर्भ: COVID प्रभावित रोगियों के उपचार में मेडिकल ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण अवयव है। COVID-19 संक्रमण की चल रही दूसरी लहर के मद्देनजर देश के कई हिस्सों के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण देश भर में कई मौतें हुई हैं।

भारत कितनी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की दैनिक उत्पादन क्षमता 7,127 मीट्रिक टन (MT) ऑक्सीजन थी, जिसके बारे में उसने कहा कि यह पर्याप्त है क्योंकि 12 अप्रैल तक देश भर में चिकित्सा ऑक्सीजन की खपत 3,842 मीट्रिक टन थी।

- PMO ने विज्ञप्ति में कहा है कि देश में LMO [लिविड मेडिकल ऑक्सीजन] का उत्पादन अगस्त 2020 में 5,700 मीट्रिक टन/दिन से बढ़कर वर्तमान 8,922 मीट्रिक टन (25 अप्रैल, 2021 को) हो गया। LMO का घरेलू उत्पादन अप्रैल 2021 के अंत तक 9,250 मीट्रिक टन/दिन को पार करने की उम्मीद है।

किस कारण से कमी हुई?

- अत्यधिक मांग से चकमा दिया गया:** जबकि केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को चिकित्सा ऑक्सीजन सहित आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2020 में वरिष्ठ अधिकारियों के एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समूह (EG2) का गठन किया, यह समूह ऐसा प्रतीत होता है संक्रमण में वृद्धि के व्यापक पैमाने और गति से गार्ड को पकड़ा गया।
- मांग के पूर्वानुमान की विफलता:** ऑक्सीजन की मांग के अनुमान वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत पीछे रह गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत से पहले कुल उत्पादन का लगभग 10% या 700 मीट्रिक टन / दिन थी, हाल के हफ्तों में बढ़कर ~ 5700MT / दिन हो गई, जिसमें गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों की घटना होती है। वर्तमान दूसरी लहर के दौरान सांस की तकलीफ तेजी से बढ़ रही है।
- खराब लॉजिस्टिक तैयारी:** भारत में दूसरी लहर के लिए लॉजिस्टिक तैयारी पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होती है। LMO के परिवहन के लिए केवल 1,224 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध होने के कारण, महत्वपूर्ण स्थानों पर जल्द समय में चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त वाहन नहीं हैं। नतीजतन, आपूर्ति समय पर नहीं पहुंचने के कारण आपूर्ति समाप्त हो गई और कई गंभीर रूप से बीमार रोगियों की हांफते हुए मौत हो गई।

हम आपूर्ति चुनौतियों का सामना क्यों कर रहे हैं?

- चिकित्सा संस्करण सहित ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए स्टैंड-अलोन सुविधाएं अब तक भौगोलिक रूप से देश के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मुख्य रूप से समूहों में केंद्रित हैं, इस प्रकार सड़क मार्ग से दूरियों पर मूलवस्तु के परिवहन की आवश्यकता होती है।

आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है?

संकट से निपटने के लिए केंद्र बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है।

- इस्पात संयंत्रों से डायवर्जन:** एक के लिए, इसने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित देश भर में इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध तत्व के अधिशेष स्टॉक को तैनात करने का निर्णय लिया है।
- ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश भर के विभिन्न अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले 162 प्रेशर स्विंग सोखना (PSA) संयंत्रों को चालू करने के लिए युद्धस्तर पर तेजी ला रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता:** अभी के लिए, सरकार रूस और सिंगापुर सहित कई देशों के साथ ऑक्सीजन उपकरण भेजने के लिए विदेशों से भी सहायता स्वीकार कर रही है।

कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- सीटी स्कैन तब से चर्चा में है जब से हल्के से मध्यम कोविड लक्षणों वाले कई कोविड पॉजिटिव रोगी और कुछ नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जिनमें कोविड के लक्षण हैं, परीक्षण के लिए आ रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

सीटी स्कैन

- इसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन के रूप में भी जाना जाता है।

- यह एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में क्लिनिकल उद्देश्यों के लिए गैर-आक्रामक रूप से शरीर की विस्तृत छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- आयनकारी विकिरणों का उपयोग कभी-कभी इसके प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर देता है।

भारत के अस्पतालों में बार-बार आग लगना

संदर्भ: अगस्त 2020 से भारत के अस्पतालों में आग लगने की 24 घटनाओं में 93 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर कोविड-19 मरीज हैं।

1. ओवरस्ट्रेस्ड ICUs, ACs

- अस्पताल में अधिक कोविड रोगियों को भर्ती करने के लिए बिस्तर, उपकरण और स्टाफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिजली के तारों की व्यवस्था का तत्काल विस्तार करना संभव नहीं हो पाया है।
- वेंटिलेटर, उपकरण, एयर कंडीशनर अब 24 x 7 घंटे काम कर रहे हैं। सही रूप से एयर कंडीशनर को 15-16 घंटे तक चलने की आवश्यकता होती है और फिर उसे ठंडा करने की अवधि की आवश्यकता होती है। यह पूरे सिस्टम पर दबाव बना हुआ है।
- चिकित्सा उपकरण या तार अपनी क्षमता से अधिक करंट ले जाने से आग लग सकती है।

2. अधिक ज्वलनशील सामग्री

- गुजरात में, अग्निशमन अधिकारियों ने नोटिस किया है कि आईसीयू में क्रॉस-वेंटिलेशन की कमी है यह सभी आईसीयू के मामले में है क्योंकि उन्हें विसंक्रमित रखने के उद्देश्य से सील कर दिया गया।
- कई बार ICU में उच्च ऑक्सीजन प्रतिशतता और सैनिटाइजर के धुएं के कारण अचानक आग लग जाती है जिससे प्रतिक्रिया करने का समय कम हो जाता है।

आगे की राह

- अस्पतालों को स्प्रिंकलर अवश्य लगाना चाहिए। यदि तापमान 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो स्प्रिंकलर स्वचालित रूप से 35 लीटर प्रति मिनट का वितरण शुरू कर देता है। वे प्रतिक्रिया का पहला रूप बन सकते हैं,
- प्रमुख कोविड अस्पतालों में और अधिक अग्निशमन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है।
- घनी आबादी वाले अस्पतालों में सप्ताह में एक या दो बार नियमित ऑडिटिंग की आवश्यकता होती है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पटाखों से बार-बार दुर्घटनाएं

भारत के टीकाकरण में आगे की चुनौती

संदर्भ: कोविड-19 के टीके आश्चर्यजनक गति से विकसित किए गए। अभी तक किसी और बीमारी ने तेजी से इतने टीके विकसित होते नहीं देखा गया। विकसित किए जा रहे 250 उम्मीदवार टीकों में से कम से कम 10 को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आपातकालीन उपयोग के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

- **अधिक मांग:** दुनिया भर में लगभग सात अरब लोगों को टीका लगाया जाना है, जिनमें से प्रत्येक में ज्यादातर दो जैब्स हैं, दुनिया भर में टीकों की मांग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है।
- **विकसित राष्ट्रों द्वारा भंडारण:** अमीर राष्ट्रों ने हमेशा की तरह व्यवहार किया है। उपलब्ध टीकों के 80% से अधिक का आदेश दिया गया है और/या पहले से ही कुछ देशों द्वारा स्टॉक किया गया है जो दुनिया की आबादी का केवल 20% है।
- **अमीर राष्ट्रों का टीकाकरण योजनाएं:** पश्चिमी देश, जो पहले से ही अपनी वयस्क आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का टीकाकरण कर चुके हैं, छोटे बच्चों और शायद, यहाँ तक कि बच्चों को भी टीका लगाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए इन टीकों को मुक्त बाजार में पहुंचाना और भी मुश्किल हो गया है।

- **नए वायरस म्यूटेंट:** दुनिया भर में नई तरंगें म्यूटेंट द्वारा संचालित होती हैं हालांकि वर्तमान में टीके इनके खिलाफ प्रभावी दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, प्रतिरक्षा-एस्केप म्यूटेंट के उभरने की संभावना केवल बढ़ेगी।
- **भारत में विशाल जनसंख्या:** हालांकि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसकी कुल आबादी में से केवल 13% को ही एक ही जैब मिला है और लगभग 2% को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
- **मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने में समय लगता है:** भारत वैक्सीन निर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता है, हालांकि, टीके कई घटकों के जटिल फॉर्मूलेशन हैं और कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति पर निर्भर हैं जो ज्यादातर आयात किए जाते हैं। पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बाद भी मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने में अनिवार्य रूप से कम से कम 2-3 महीने लगेंगे।

आगे की राह

- स्पुतनिक V, जेनसेन और नोवावैक्स सहित कम से कम तीन या चार और टीकों को भारत में पहले से ही उत्पादित होने की उम्मीद है कई और स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं, भारत निश्चित रूप से अपनी आबादी का टीकाकरण करने के लिए टीकों का उत्पादन करेगा।
- प्रस्तावित IP छूट भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में बड़े पैमाने पर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) के साथ कोविड टीकों के उत्पादन के लिए स्थान रख सकती है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- वैक्सीन राष्ट्रवाद

एंटीफंगल इंजेक्शन की कमी, एम्फोटेरिसिन B

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटी-फंगल इंजेक्शन 'एम्फोटेरिसिन' और अन्य एंटी-फंगल दवाओं की भारी कमी अब मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रही है।
- म्यूकोर्मिकोसिस एक जानलेवा संक्रमण है जो लगभग 30% मधुमेह रोगियों में कोविड -19 के बाद होता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन का उपयोग गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है।
 - यह एंटीफंगल नामक दवाओं के एक वर्ग में है।
 - यह संक्रमण पैदा करने वाले फंगस के विकास को धीमा करके काम करता है।
 - यह आमतौर पर नस में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है।
 - एम्फोटेरिसिन B को 1955 में स्ट्रेप्टोमाइसेस नोडोसस से अलग किया गया था और 1958 में चिकित्सा उपयोग में लाया गया।
 - यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है।
-

आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी।

- यह डब्ल्यूएचओ की हरी बत्ती प्राप्त करने वाला पहला चीनी जैब है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह दो खुराक वाला टीका है, जो पहले से ही दुनिया भर के दर्जनों देशों में तैनात किया जा रहा है।
- WHO ने पहले ही फाइजर-बायोएनटेक, मॉडर्न, J & J और एस्ट्राजेनेका जैब द्वारा भारत और दक्षिण कोरिया में निर्मित किए जा रहे टीकों को आपातकालीन उपयोग सूची दी है।

यह वैक्सीन कैसे काम करता है?

- सिनोफार्म वैक्सीन एक निष्क्रिय कोरोनावायरस वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सिन को भारत बायोटेक इंडिया (बीबीआईएल) द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- निष्क्रिय टीके रोग वाहक वायरस (इस मामले में SARS-CoV-2) लेते हैं और गर्मी, रसायनों या विकिरण का उपयोग करके इसे मार देते हैं।
- डब्ल्यूएचओ नोट्स करता है कि इन टीकों को बनाने में अधिक समय लगता है और इन्हें प्रशासित करने के लिए दो या तीन खुराक की आवश्यकता हो सकती है। फ्लू और पोलियो के टीके भी इसी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं।
- दुनिया में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख टीकों में से, सिनोफार्म, कोवैक्सिन और सिनोवैक (चीन द्वारा भी विकसित) ही एकमात्र ऐसे टीके हैं जो निष्क्रिय वायरस का उपयोग करते हैं।
- फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्न जैसे अन्य mRNA टीके हैं।
- ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल खुराक वाले टीके एक वायरल वेक्टर का उपयोग करते हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच कोविड -19 संक्रमण की सूचना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच कोविड -19 संक्रमणों की सूचना दी जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य में आठ अलग-अलग PVTGs में से 21 आदिवासियों ने अब तक पॉजिटिव परीक्षण किया है, जिसमें बोंडा जनजाति के दो लोग भी शामिल हैं।
- बोंडा लोग मलकानगिरी के ऊंचे इलाकों में रहते हैं।
- एक अन्य PVTGs डोंगरिया कोंध के सदस्यों ने रायगडा जिले में पॉजिटिव परीक्षण किया है।

क्या आप जानते हैं?

- ओडिशा राज्य देश में सबसे बड़ी और विविध जनजातीय आबादी में से एक है।
- ओडिशा में रहने वाले 62 आदिवासी समूहों में से 13 को PVTGs के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनजातीय आबादी में ओडिशा का भाग 9% था।
- राज्य की जनसंख्या का 22.85 प्रतिशत आदिवासी हैं।
- **राज्यों में PVTGs :** बोंडा, बिरहोर, चुक्तिया भुंजिया, दीदयी, डोंगरिया कांधा, हिल खरिया, जुआंग, कुटिया कोंध, लांजिया सौरा, लोढ़ा, मनकीरदिया, पौड़ी भुइयां और सौरा।

जीवविज्ञान रोगों के उपचार के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- हाल ही में एक नैनोकण को मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है।
- यह रोगों के उपचार के लिए एक नया और संभावित क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नई अवधारणा, प्रोटीन-एंटीबॉडी संयुग्म या PACs, दवा वितरण के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को जोड़ती है।
 - यह अग्नाशय के कैंसर जैसे लाइलाज रोगों पर प्रभाव डाल सकता है।
-

कोरोना वायरस वेरिएंट के लिए नई नामकरण प्रणाली

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तूफानों के नाम के समान ही कोरोनावायरस के प्रकारों के नामकरण की एक प्रणाली का अनावरण करेगा
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड-19 के वेरिएंट के नामकरण के लिए एक नये सिस्टम का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पहल उस देश से जुड़े धब्बे को दूर करने का प्रयास करती है जिसमें इसकी खोज की गई थी।
- जनता के लिए अपनी वंशावली संख्या के बजाय याद रखना भी आसान होगा
- वैज्ञानिक औपचारिक वंश नामों से वायरस और उनके रूपों का उल्लेख करते हैं, जो अक्षरों और नामों का एक संयोजन है जो विभिन्न रूपों के बीच संबंधों को इंगित करता है।
- B.1.1.7 और B.1.617 जैसे प्रकार बताते हैं कि उनमें कुछ उत्परिवर्तन समान हैं और उनके विकासवादी इतिहास के लिए सुराग प्रदान करते हैं।
- हालांकि, 1.1.7 को 'यू.के. वेरिएंट' के रूप में और B.1.351 को 'साउथ अफ्रीकन' वेरिएंट के रूप में जाना जाने लगा।

संबंधित आलेख

दक्षिण अफ्रीकी कोविड संस्करण

भारत के स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ब्रेन ड्रेन

संदर्भ: देश भर में COVID मामलों में वृद्धि से स्वास्थ्य कर्मियों पर अत्यधिक बोझ पड़ा है और अंततः उनकी कमी हो सकती है। कोविड रोगियों के इलाज के अलावा, उन्हें टीके भी लगाने होंगे, जो अब देश की पूरी वयस्क आबादी के लिए उपलब्ध हैं।

क्या आपको पता है?

- सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1.7 नर्स हैं और एक डॉक्टर से रोगी अनुपात 1:1,404 है - यह WHO के प्रति 1,000 जनसंख्या पर तीन नर्सों के मानदंड और 1:1,100 के एक डॉक्टर से रोगी अनुपात से काफी नीचे है।
- 2020 की मानव विकास रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में प्रति 10,000 लोगों पर पांच अस्पताल के बिस्तर हैं दुनिया में सबसे कम में से एक।

- डॉ देवी शेटी के अनुसार, भारत को अगले कुछ हफ्तों में अतिरिक्त पांच लाख ICU बेड, दो लाख नर्स और 1.5 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता होगी।

स्वास्थ्य कर्मियों के ब्रेन ड्रेन की समस्या

- **स्वास्थ्य कर्मियों के प्रवास से कमी होती है:** कई दशकों से, भारत विकसित देशों, विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के देशों, यूरोप और अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का एक प्रमुख स्रोत रहा है। और यह नर्सों और डॉक्टरों की कमी का एक हिस्सा है।
 - OECD के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में लगभग 69,000 भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टरों ने यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काम किया। इन चार देशों में, एक ही वर्ष में 56,000 भारतीय प्रशिक्षित नर्सें काम कर रही थीं।
- **प्रवासन के कारक:** पुल (Pull) कारकों में गंतव्य देशों में उच्च वेतन और बेहतर अवसर शामिल हैं, जबकि पुश (Push) कारकों में भारत के निजी क्षेत्र में कम वेतन, सरकारी निवेश की कमी, नियुक्ति में देरी और सार्वजनिक क्षेत्र में कम अवसर शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य कर्मियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए नीतियों में बदलाव करने वाले देश:** महामारी की शुरुआत में, OECD देशों ने स्वास्थ्य पेशेवरों को यात्रा प्रतिबंधों से नौकरी की पेशकश के साथ छूट दी। यूके ने योग्य विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों और उनके आश्रितों को एक वर्ष के लिए निःशुल्क वीजा प्रदान किया है। इसी तरह, फ्रांस ने महामारी के दौरान अप्रवासी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नागरिकता देने की पेशकश की है।

क्या सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कदम उठाए हैं?

- 2014 में, सरकार ने अमेरिका में प्रवास करने वाले डॉक्टरों को भारत लौटने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NORI) जारी करना बंद कर दिया।
- NORI जारी न करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि डॉक्टरों को तीन साल की अवधि के अंत में भारत लौटना होगा।
- ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार की नीतियां प्रतिबंधात्मक प्रकृति की हैं और हमें समस्या का वास्तविक दीर्घकालिक समाधान नहीं देती हैं।

आगे की राह

- हमें व्यवस्थित परिवर्तनों की आवश्यकता है जो कि हो सकते हैं
 - स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश वृद्धि
 - श्रमिकों को उचित वेतन सुनिश्चित करना
 - एक समग्र वातावरण का निर्माण करना जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो और उन्हें देश में रहने के लिए प्रेरित कर सके।
- सरकार को ऐसी नीतियां बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो सर्कुलर माइग्रेशन और रिटर्न माइग्रेशन को बढ़ावा दें। ऐसी नीतियां जो स्वास्थ्य कर्मियों को उनके प्रशिक्षण या अध्ययन के पूरा होने के बाद घर लौटने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- यह द्विपक्षीय समझौतों को तैयार करने की दिशा में भी काम करता है जो भेजने और प्राप्त करने वाले देशों के बीच "ब्रेन-शेयर" की नीति को आकार देने में मदद कर सकता है। प्रवासियों के गंतव्य स्थान जरूरत के समय में अपने मूल देश में स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत में चिकित्सा ऑक्सीजन संकट

राज्यों ने म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - स्वास्थ्य; नीतियां और हस्तक्षेप सुर्खियों में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित करने की अपील की है
- म्यूकोर्मिकोसिस, COVID-19 रोगियों में होने वाला काला कवक संक्रमण है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे महामारी घोषित करने से स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाएगी और ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी।
- राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु पहले ही इसे महामारी घोषित कर चुके हैं।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस, फंगल संक्रमण के कारण होने वाली जटिलता है
- वातावरण में कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोग म्यूकोर्मिकोसिस पकड़ लेते हैं।
- इस बीमारी का पता उन मरीजों में लगाया जा रहा है जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं।

संबंधित आलेख

- एंटीफंगल इंजेक्शन की कमी, एम्फोटेरिसिन B

SARS-COV-2 वायरस का हवा में संचरण (Airborne Transmission)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - हेल्थ इन न्यूज सुर्खियों में-

- सरकार ने एक नई एडवाइजरी में चेतावनी दी है कि SARS-COV-2 वायरस को हवा के साथ-साथ एयरोसोल के रूप में छोटे कणों के साथ वायरस हवा में ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। और यह 10 मीटर दूर तक लोगों को संक्रमित कर सकता है।
- कोविड-19 पर सामान्य परामर्श प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह दिशानिर्देश नवीनतम सबूतों के अनुरूप है जो यह सुझाव देते हैं कि वायरस के हवाई संचरण, विशेष रूप से संलग्न स्थानों में, से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- शुरुआत में यह सुझाव दिया गया था कि वायरस मुख्य रूप से बड़ी बूंदों के माध्यम से फैलता है जो किसी व्यक्ति के बात करने, छींकने या खांसने पर निकलता है।
- ये बूँदें, अपने बड़े आकार के कारण, जमीन पर गिरने से पहले केवल कम दूरी तक फैलता है।
- हालांकि, पिछले कुछ महीनों में, वैज्ञानिकों को एरोसोल के माध्यम से भी वायरस के फैलने प्रमाण मिले।

क्या आप जानते हैं?

- एरोसोल हवा में घूमते हुए छोटे ठोस कण होते हैं।
- अपेक्षाकृत हल्के, एरोसोल वायरस को बहुत बड़ी दूरी तक ले जाते हैं।
- इसके अलावा, वे हवा में कई मिनट या घंटों तक निलंबित रह सकते हैं, जिससे आस-पास के व्यक्ति को संक्रमित करने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

संबंधित आलेख

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) शुरू किया गया

वायरस उत्परिवर्तन: नया SARS-CoV-2 तनाव

आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST असंवैधानिक: दिल्ली हाई कोर्ट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; न्यायतंत्र

सुर्खियों में-

- दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrator) पर जीएसटी लगाए जाने को असंवैधानिक करार दिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसमें कहा गया है कि COVID-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक जीवन रक्षक उपकरण का निर्माण करते हैं और एक महामारी के दौरान एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- अदालत ने महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए सरकार से इस तरह के आयात पर लगाए गए 12% जीएसटी को अस्थायी रूप से हटाने पर विचार करने को कहा।

क्या आप जानते हैं?

- संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसा उपकरण है जो ऑक्सीजन से समृद्ध उत्पाद गैस स्ट्रीम की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन को मुख्य रूप से हटाकर गैस आपूर्ति (आमतौर पर परिवेशी वायु) से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

तीसरी लहर, अगर ऐसा होता है, तो स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। यहाँ कुछ चिंताओं के बारे में-

- खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के प्रभुत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते संक्रमण
- टीकों की कमी और सभी पात्र व्यक्तियों को टीका लगाने के लिए अपेक्षित वर्ष भर की समय सीमा
- बच्चों पर वायरस के प्रभाव की अशुभ संभावना
- ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा ढांचा

भारत की नौकरशाही को किसी भी गंभीर स्थिति के साथ-साथ सामान्य समय में सुलभ, स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं को तेजी से बनाने की जरूरत है।

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फोकस होना चाहिए

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को सुदृढ़ बनाना और उनका नवीनीकरण करना लाभप्रद स्थिति हो सकती है।
- दुर्लभ घटनाओं को छोड़कर, सभी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल से निपटने के लिए इन्हें सुसज्जित और तैनात किया जाना चाहिए।
- यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी मरीज को स्वास्थ्य देखभाल के लिए शहरी क्षेत्रों में 10 से 15 किमी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 25 किमी से अधिक की यात्रा न करनी पड़े।

2. जिला प्रबंध समूह

- जिला स्तर पर विभिन्न संबंधित विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक प्रबंध समूह बनाया जाना चाहिए।
- यह समुदाय के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों और महत्वपूर्ण हितधारकों को अपने साथ ला सकता है।
- प्रबंध समूह का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट या उनके वरिष्ठ नामित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

- इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जा सकता है, और राज्य सरकार द्वारा परिभाषित जल्द और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।
- उदाहरण के लिए जिला प्रबंध समूह की कुछ शक्तियों और अधिदेशों का उल्लेख नीचे किया गया है।
 - सबसे पहले, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान अधिसूचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला क्षेत्र, सार्वजनिक या निजी के भीतर सभी या सूचीबद्ध चिकित्सा देखभाल केंद्रों को सूचित और कमांडर करना।
 - दूसरा, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को शामिल करके सभी लोजिस्टिक्स व्यवस्थाओं को पहले से ही करना।
 - तीसरा, आवश्यक विशेष सेवाओं और मांग की प्रत्याशा में क्षमता वाले चिकित्सा केंद्रों का विकास करना।
 - चौथा, मौजूदा (PHCs) को बनाए रखना और अपग्रेड करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गैरहाज़िर चिकित्सा अधिकारियों के प्रतिस्थापन, नवीन स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त चिकित्सा और तकनीकी कर्मचारियों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
 - पांचवां, कंटेनमेंट जोन घोषित करना और यह भी सुनिश्चित करना कि नागरिक एहतियाती सलाह और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
 - छठा, रिसाव के मामलों से निपटने के लिए, आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की कालाबाजारी
 - सातवां, प्राथमिकताएं तय करना और जल्द परीक्षण, ट्रेसिंग और टीकाकरण के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
 - आठवां, आम जनता को प्रतिदिन उपलब्ध चिकित्सा और अन्य सुविधाओं से अवगत कराना। और बाधाओं को दूर करने के लिए यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम-सुधार सुनिश्चित करने के लिए दैनिक बैठक करना।

3. राज्य स्तर पर

- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को अपनी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र द्वारा निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुरूप एक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को यह देखना चाहिए कि ऐसी सक्षम कार्यान्वयन मशीन जोशीले टीम लीडरों द्वारा संचालित हो। यहां आवश्यक मिशनरी भावना को बाधित करने के लिए किसी नौकरशाही नियम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- बॉटम-अप दृष्टिकोण न केवल कोविड लहर में किसी भी संभावित उछाल को कम करने में मदद करेगा, बल्कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण करेगा। भारत को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने का यह मौका नहीं गंवाना चाहिए।

आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य

सुखियों में-

- हाल ही में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** आयुष मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी (ACCR) पोर्टल

- यह आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- उद्देश्य: आयुष चिकित्सकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्राप्त क्लिनिकल परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की ताकत का दस्तावेजीकरण करने की उम्मीद है।

- इसमें आयुष प्रणालियों के माध्यम से इलाज किए गए कोविड-19 मामलों की रिपोर्टिंग और विवरण प्रकाशित करने के लिए एक समर्पित अनुभाग है।

आयुष संजीवनी ऐप

- यह चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन/दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आयुष 64 और कबासुरा कुदिनीर दवाएं स्पर्शोन्मुख और हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन में शामिल हैं।

IAS baba

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) - 2021

HISTORY AND ART & DAILY CLASS AND TESTS
(Offline And Online)

Illustration of a person in a white lab coat examining a large scroll with a magnifying glass, while another person in an orange shirt kneels nearby.

Rs. 2,800/- (+ 18% GST)

REGISTER NOW

IAS baba

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) - 2021

GEOGRAPHY DAILY CLASS AND TESTS
(Offline And Online)

Illustration of a person in an orange shirt pointing at a world map on a screen.

Rs. 2,800/- (+ 18% GST)

REGISTER NOW

सरकारी योजनाएँ

भारत में स्वच्छता प्रणाली की स्थिति

संदर्भ: मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार के निषेध और ग्रामीण भारत में नवनिर्मित "शुष्क शौचालय" और "हैंगिंग शौचालय" 2020-21 के लॉकडाउन का ही परिणाम हैं।

मुद्दे

- **उपयोग में गिरावट :** COVID-19 के डर के कारण स्वच्छता शौचालय के उपयोग में गिरावट आई है, क्योंकि वर्तमान में, ग्रामीण भारत में छह लाख से अधिक शौचालयों में पानी की भारी कमी है।
- **खुले में शौच का उजागर :** उत्तर प्रदेश में निर्माण स्थलों के पास मानव मल-मूत्र से भरे छोटे-छोटे गड्ढे भारत में एक बार फिर से खुले में शौच के पैटर्न में वृद्धि को उजागर करते हैं।
- **"हैंगिंग शौचालय" का मुद्दा:** पश्चिम बंगाल में, केंद्र में "छोटे छिद्र वाले आधार" के रूप में अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें हैंगिंग शौचालयों के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण उन परिवारों द्वारा किया जाता है जो सैनिटरी शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे हमेशा मल मूत्र आदि से भरे होते हैं।
- **स्वच्छता कर्मियों पर बढ़ता बोझ:** ग्रामीण भारत में, महामारी के बीच बिना पानी के लंबे समय तक बिजली कटौती ने स्वच्छता कर्मचारियों पर स्वच्छता शौचालय बनाए रखने का बोझ फिर से डाल दिया है। "शुष्क शौचालय" (बिना फ्लश या गड्ढे वाले शौचालय) भारत के सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप रहा है क्योंकि इसे बनाए रखना उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाता है।
- **लैंगिक आधारित स्वच्छता असुरक्षा:** शौचालय सुविधा की तलाश करते समय या खुले में शौच के लिये जाते समय महिलाएँ अपने जीवन के प्रति खतरे का सामना करती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं।
- **भ्रष्टाचार:** ठेकेदारों द्वारा ज़ब्त किए गए बिल और शौचालयों को ज्यादा समय तक चलने वाले बुनियादी ढांचे से दूर रखते हैं।
- **लॉकडाउन का प्रभाव:** लॉकडाउन ने भारत में स्वच्छता संघर्ष को फिर से कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को हर दिन इन शौचालयों के उपयोग के परिणाम का डर सता रहा है।

आगे की राह

- **शौचालयों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन:** स्वच्छता वाले शौचालयों के भीतर भी ग्रामीण भारत में असंगठित जल स्रोतों पर निर्भरता भारत में शौचालय निर्माण के प्रति जुनून का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को बढ़ाती है।
- **शुष्क शौचालयों और हैंगिंग वाले शौचालयों का उन्मूलन:** शुष्क शौचालयों और हैंगिंग शौचालयों दोनों का उपयोग उनके आसपास के समुदायों को कोविड-19 से परे बीमारी के अधिक खतरे में डालता है। इसलिए, इन इकाइयों के निर्माण और उपयोग दोनों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- नए शौचालयों के निर्माण पर इतना अधिक ध्यान देने के बजाय, हमें ग्रामीण भारत में शौचालय के वास्तविक उपयोग की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- स्वच्छ भारत अभियान
-

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए नया ढांचा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट को चिह्नित करने के लिए स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए नया ढांचा जारी किया।

अन्य सम्बंधित तथ्य

स्वामित्व

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
 - **मंत्रालय:** पंचायती राज मंत्रालय
 - इसे 9 राज्यों में योजना के प्रारंभिक चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया।
 - **उद्देश्य:** ड्रोन सर्वेक्षण और CORS नेटवर्क का उपयोग करके भारत में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना जो 5 सेमी का मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
-

विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - गवर्नेंस; नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD), भारत सरकार ने 1 जून से सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID) पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विकलांगता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- केंद्र सरकार ने RPwD अधिनियम, 2016 के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया।
 - नियम 18(5) केंद्र सरकार को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र जारी तथा अनिवार्य बनाने के लिए एक तिथि निर्धारित करने के लिए अनिवार्य करता है।
 - यह अखिल भारतीय वैधता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र की क्रॉस-चेकिंग के लिए एक व्यवहार्य तंत्र प्रदान करने और दिव्यांगजन के लाभ के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा, 01.06.2021 से विकलांगता के प्रमाणीकरण का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेगा।
-

सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 की अधिसूचना जारी

भाग- जीएस प्रीलिम्स जीएस-II- नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार (Aadhaar) की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता- 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा।

- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (National Data Base for unorganised workers-NDUW) को विकसित कर रहा है।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से अपने आप को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं।

SWAMIH ने अपनी पहली आवासीय परियोजना पूरा किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और शासन

सुर्खियों में-

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने भारत सरकार की स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग (SWAMIH) की विशेष खिड़की द्वारा अपनी पहली आवासीय परियोजना पूरी किये जाने के साथ वर्चुअल माध्यम से घर खरीदने वालों को कब्जा सौंपा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आवासीय परियोजना - उपनगरीय मुंबई में स्थित आवासीय परियोजना – रिवाली पार्क, भारत की पहली ऐसी आवासीय परियोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था।
- यह SWAMIH राशि 2019 में शुरू किया गया।
- यह रिवाली पार्क विंटरग्रीन फंड द्वारा किया गया पहला निवेश है तथा पूरा होने वाला पहला प्रोजेक्ट भी है।
- स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड भारत में सबसे बड़ी निजी इक्विटी टीमों में से एक है और इसने COVID-19 संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद सहायनीय कार्य किया है।
- यह राशि कुल मिलाकर 1,16,600 घरों को पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है।
- यह फंड वित्त के किसी अन्य स्रोत पर निर्भर किए बिना घर का निर्माण और डिलीवरी पूरा करके घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास की कमी को पूरा कर रहा है।

वेबेरियन नौकरशाही और उनकी चुनौतियाँ

संदर्भ: अपने प्रयासों के बावजूद, नौकरशाही COVID-19 संकट की अप्रभावी प्रतिक्रिया के लिए एक प्रमुख चिंता के रूप में उभरी है।

वर्तमान मॉडल

- वेबेरियन नौकरशाही एक विशेषज्ञ के बजाय एक सामान्यवादी को चुनती है। प्रत्येक सरकारी विभाग के विशेषज्ञों को सामान्य अधिकारियों के अधीन रहना पड़ता है।
- न्यायोचित यह है कि सामान्य विशेषज्ञ की तुलना में व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
- **महामारी की स्थिति:** स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जो विशेषज्ञ हैं उन्हें सामान्य अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए बनाया गया है और नीति के विकल्प सामान्यवादियों के लिए छोड़ दिए गए हैं जब उन्हें विशेषज्ञों के साथ में होना चाहिए।

मुद्दे

- वेबेरियन नौकरशाही स्थिति के आधार पर नेतृत्व को प्राथमिकता देती है।
- पारंपरिक नौकरशाही अभी भी समारोह के नेतृत्व पर स्थिति के नेतृत्व के साथ लगी हुई है।

- प्रशासनिक सुधार आंदोलन सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन में सुधार की तलाश के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में निजी क्षेत्र के निजीकरण और प्रबंधकीय तकनीकों को बढ़ावा देता है। लेकिन यह एक व्यवहार्य समाधान नहीं है, कम से कम भारत में जहां विकास में सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं।

आगे की राह - सहयोगात्मक शासन

- सहयोगात्मक शासन एक ऐसा मॉडल है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी खिलाड़ी और नागरिक समाज, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठन, प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मिलकर काम करते हैं।
- नीति निर्माण और कार्यान्वयन में एकमात्र एजेंसी के रूप में सार्वजनिक नौकरशाही का कोई वर्चस्व नहीं है।
- नए सार्वजनिक शासन के हिस्से के रूप में, सामाजिक अभिनेताओं और निजी खिलाड़ियों का एक नेटवर्क शासन के विभिन्न पहलुओं में जिम्मेदारी लेगा, जिसमें सार्वजनिक नौकरशाही जहाज को चलाने के बजाय उसे चलाएगी।
- महामारी के दौरान, हम देखते हैं कि नागरिक समाज जीवन बचाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नए लोक प्रशासन के हिस्से के रूप में, इस भूमिका को संस्थागत बनाना होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अल्पतम सरकार, अधिकतम शासन

चर्चा में वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centre Scheme)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - नीतियां और हस्तक्षेप और उनके प्रभाव सुखियों में-

- वन स्टॉप सेंटर योजना (OSCs) हाल ही में चर्चा में थी।
- इसने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है।
- **द्वारा कार्यान्वित:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (UT) प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- **उद्देश्य:** निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना और पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता सहित सेवाओं की एक शृंखला के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना। और परामर्श, महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन आदि।
- अब तक 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 701 OSCs चालू किए जा चुके हैं।

सेहत ओपीडी पोर्टल (SeHAT OPD Portal) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- राजनीति और शासन सुखियों में-

- 'सर्विसेज़ ई-हेल्थ असिस्टेन्स एवं टेली-कंसल्टेशन (Services e-Health Assistance & Tele-consultation, SeHAT) ओपीडी पोर्टल शुरू किया है।
- **मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पोर्टल सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है।
 - यह उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ सेहत ओपीडी पोर्टल का अंतिम संस्करण है।
 - परीक्षण संस्करण को अगस्त 2020 में कार्यात्मक बनाया गया था।
 - **द्वारा विकसित:** सैन्य मामलों के विभाग (DMA), सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS), एकीकृत रक्षा कर्मचारी (IDS) और कृत्रिम कंप्यूटिंग के विकास केंद्र (C-DAC) मोहाली।
 - यह पोर्टल अस्पतालों पर भार को कम करने में मदद करेगा और मरीज आसान और प्रभावी तरीके से संपर्क रहित परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।
-

मध्याह्न भोजन अर्थात मिड-डे-मील (MDM) योजना के घटक के रूप में मौद्रिक सहायता

भाग- जीएस प्रारंभिक और जीएस-II-कल्याणकारी योजनाएं
सुखियों में-

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याह्न-भोजन योजना के रूप में सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों (118 मिलियन छात्रों) को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
 - **उद्देश्य:** नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना और साथ ही साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना।
 - 2001 में यह पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बनाया गया।
 - इस योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित मदरसों / मकतबों में पढ़ने वाले कक्षा I-VIII के बच्चे शामिल हैं।
 - यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है।
 - यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आता है।
-



IAS  BABA

RAPID REVISION (RaRe) SERIES

Road Map For The Next 120 Days For UPSC 2021!

10 Stepping Stones To Success!
A Dedicated Portal For Focused Preparation

REGISTER NOW

Prelims+Mains Focus **#ReviseWithBaba**  **Starting From 31st May, 2021**

FREE INITIATIVE

अंतरराष्ट्रीय

ऑपरेशन समुद्र सेतु-II का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- देश में COVID-19 मामलों में तीव्र उछाल के बीच ऑक्सीजन की लगातार मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय मिशन का समर्थन करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु-II शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट का कार्य करेंगे।

- आईएनएस कोलकाता (INS Kolkata) और आईएनएस तलवार (INS Talwar) नाम के इन दो जहाजों ने मुंबई में 40 टन तरल ऑक्सीजन को लेकर आने के लिए मनामा, बहरीन के बंदरगाह में प्रवेश किया।
- पिछले साल भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था और मालदीव, श्रीलंका और ईरान से लगभग 4,000 फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया था।

G-7 शिखर सम्मेलन में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- भारत को G-7 बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया।

अन्य सम्बंधित तथ्य

जी-7 या 'जी-7 समूह'

- गठन: 1975
- देश: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए।
- बैठकों की अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा बारी-बारी से की जाती है।
- शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी हैं।

क्या आप जानते हैं?

- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G- 8' के रूप में जाना जाता रहा।
- हालाँकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुनः G-7 कहा जाने लगा।

COVID-19 टीकों के लिए TRIPS सुरक्षा को माफ करने की पहल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में COVID-19 टीकों के लिए व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) संरक्षण को माफ करने की पहल का समर्थन करेगा।

अन्य सम्बंधित तथ्य

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स)

- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है।
- यह अन्य WTO सदस्य देशों के नागरिकों पर लागू बौद्धिक संपदा (IP) के विभिन्न रूपों के राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विनियमन के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करता है।
- ट्रिप्स पर 1989 और 1990 के बीच टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर के अंत में बातचीत की गई थी और इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित किया जाता है।

कोविड -19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स) छूट

संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कोविड -19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण को माफ करने के लिए इस समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है।

सभी 164 डब्ल्यूटीओ सदस्यों के मसौदे पर सहमत होना चाहिए और कोई भी एक सदस्य इसे वीटो कर सकता है। यूरोपीय संघ, जिसने पहले छूट का विरोध किया था, ने अब अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर चर्चा करने का इरादा जताया है।

पेटेंट और आईपी अधिकार क्या हैं?

- पेटेंट एक शक्तिशाली बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, और यह सीमित, पूर्व-निर्दिष्ट समय के लिए एक आविष्कारक को सरकार द्वारा दिया गया एक विशेष एकाधिकार है।
- यह दूसरों को आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए एक प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- पेटेंट या तो प्रक्रिया पेटेंट या उत्पाद पेटेंट हो सकते हैं।
 - एक उत्पाद पेटेंट यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद के अधिकार सुरक्षित हैं, और पेटेंट धारक के अलावा किसी को भी एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान इसे बनाने से रोका जा सकता है, भले ही वे एक अलग प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हों।
 - एक प्रक्रिया पेटेंट, पेटेंट धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को विनिर्माण अभ्यास में कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करके पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।
- भारत 1970 के दशक में उत्पाद पेटेंटिंग से प्रक्रिया पेटेंटिंग की ओर बढ़ गया, जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बनने में सक्षम बनाया और 1990 के दशक में सिप्ला जैसी कंपनियों को अफ्रीका को एचआईवी-विरोधी दवाएं प्रदान करने की अनुमति दी।
- लेकिन ट्रिप्स समझौते से उत्पन्न दायित्वों के कारण, भारत को वर्ष 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और फार्मा, रसायन और बायोटेक क्षेत्रों में एक उत्पाद पेटेंट व्यवस्था पर स्विच करना पड़ा।

कोविड -19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा छूट का क्या अर्थ है?

- **बढ़ा हुआ उत्पादन:** वर्तमान में अधिकांश उत्पादन उच्च आय वाले देशों में केंद्रित है। आईपी छूट, मध्यम आय वाले देशों में बड़े पैमाने पर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) के साथ कोविड टीकों के उत्पादन के लिए स्थान उन्मुक्त कर सकती है। मध्यम आय वाले देशों द्वारा उत्पादन लाइसेंसिंग या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से हो रहा है।
- कनाडा, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश सहित देशों ने कोविड के टीके बनाने में रुचि दिखाई है यदि उन्हें पेटेंट छूट मिल सकती है।
- **भारत की भूमिका:** आईपी छूट के लिए अमेरिका का समर्थन पिछले साल विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के एक प्रस्ताव से उठा है।
- हालाँकि, उस प्रस्ताव में परीक्षण निदान और उपन्यास चिकित्सा विज्ञान सहित सभी कोविड हस्तक्षेपों पर छूट का आह्वान किया गया था।

छूट के लिए क्या बाधाएं हैं?

- **R & D निवेश को कमजोर करें:** फाइजर और एस्ट्राजेनेका सहित फार्मा कंपनियों ने प्रस्तावित छूट का विरोध किया है यह कहते हुए कि आईपी सुरक्षा को समाप्त करने से महामारी के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया कमजोर होगी, जिसमें नए वेरिएंट से निपटने के लिए चल रहे R & D प्रयास भी शामिल हैं।
- **नई सुविधाओं से सुरक्षा पर संदेह:** फार्मा कंपनियों ने यह भी तर्क दिया कि विकासशील देशों में IPR को माफ करने और उत्पादन सुविधाओं को खोलने से भी वैक्सीन सुरक्षा में जनता के विश्वास को कम किया जा सकता है और सूचना साझा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

पेटेंट के अलावा, उत्पादन बढ़ाने में अन्य बाधाएं क्या हैं?

- **व्यापार बाधाएं:** अमेरिका जैसे देशों ने अमेरिकी रक्षा उत्पादन अधिनियम नियमों का उपयोग करते हुए कुछ कोविड -19 टीकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल के निर्यात को रोक दिया था।

- आपूर्ति श्रृंखला में अड़चनें
- आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे माल और सामग्री की कमी
- गरीब देशों के साथ खुराक साझा करने के लिए अमीर देशों की इच्छा न होना।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैक्सीन राष्ट्रवाद
-

तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (ASM3) बैठक

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- भारत तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (ASM3) में भाग लिया।
- आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और सहयोग के लिये दीर्घकालिक योजनाओं को भी साझा किया है।
- यह एशिया में आयोजित होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय बैठक है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पहली दो बैठकों- ASM1 और ASM2 का आयोजन क्रमशः वर्ष 2016 (अमेरिका) और वर्ष 2018 (जर्मनी) में किया गया था।
- ASM3 संयुक्त रूप से आइसलैंड और जापान द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह बैठक विभिन्न हितधारकों को आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ को बढ़ाने, निरंतर निगरानी में जोर देने और संलग्न करने और टिप्पणियों को मजबूत करने के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **थीम (Theme) :** 'संवहनीय आर्कटिक के लिये जानकारी' (Knowledge for a Sustainable Arctic)

भारत और आर्कटिक

- आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ।
 - जुलाई 2008 से, भारत का आर्कटिक में एक स्थायी अनुसंधान केंद्र है, जिसे हिमादरी कहा जाता है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र में स्थित है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से भारत द्वारा निसार (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार) उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जा रहा है।
 - भारत सतत आर्कटिक प्रेक्षण नेटवर्क (SAON) में भी योगदान देता है।
 - भारत से आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वय, संचालन और प्रचार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा द्वारा किया जाता है।
-

दक्षिण सूडान की संसद भंग

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सलवा कीर ने संसद को भंग कर दिया है।
- जिससे 2018 के शांति समझौते के तहत देश के गृह युद्ध के लिए विरोध करने वाले सांसदों की नियुक्ति की जा सकेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पांच साल के गृहयुद्ध के दौरान विपक्षी पक्षों पर सालों तक श्री कीर और उप-राष्ट्रपति रीच मचर के बीच सितंबर 2018 में हस्ताक्षर किए गए समझौते के तहत एक नए विधायी निकाय का हिस्सा था।
- 2018 के समझौते के अनुसार, नई विधानसभा में 550 विधायकों की संख्या होगी, बहुमत – 332 – श्री कीर की गवर्निंग एसपीएलएम पार्टी से।
- सांसदों को विभिन्न दलों द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- दक्षिण सूडान पूर्वी/मध्य अफ्रीका में एक भू-आबद्ध देश है
- इसकी सीमा पूर्व में इथियोपिया, उत्तर में सूडान, पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण में युगांडा से लगती है।
- यह 2011 में सूडान गणराज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे यह सबसे हालिया संप्रभु देश बन गया।
- सफेद नील नदी जुबा से गुजरते हुए इस देश से होकर गुजरती है।

क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - आतंकवाद

सुर्खियों में-

- हाल ही में भारत 'क्राइस्टचर्च कॉल' पहल से जुड़ गया है। गौरतलब है कि 'क्राइस्टचर्च कॉल' का उद्देश्य इंटरनेट से आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्रियों को हटाना है।
- यह ऑनलाइन हिंसक उग्रवाद पर मुहर लगाने के लिए न्यूजीलैंड के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- क्राइस्टचर्च कॉल का नाम न्यूजीलैंड शहर के नाम पर रखा गया है जिसमें 15 मार्च 2019 को इंटरनेट पर लाइव प्रसारण किए गए आतंकवादी हमलों में मुस्लिम समुदाय के 51 लोग मारे गए थे।
- क्राइस्टचर्च कॉल एक कार्य योजना है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इंटरनेट खिलाड़ियों को विशेष रूप से उपायों की एक श्रृंखला लेने के लिए प्रतिबद्ध करती है
 - लाइवस्ट्रीमिंग के माध्यम से आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्री को प्रसारित करने से उत्पन्न विशिष्ट जोखिम को कम करने के लिये तत्काल प्रभावी उपायों को लागू करना।
 - नियमित और पारदर्शी सार्वजनिक रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करना।
 - एल्गोरिदम और अन्य प्रक्रियाओं के संचालन की समीक्षा करना जो उपयोगकर्ताओं का ध्यान आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्री की ओर ले जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में आवश्यक सुधार

संदर्भ: हाल ही में, न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम हेलेन क्लार्क की सह-अध्यक्षता में एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने वैश्विक प्रकोप की गंभीरता को सरकारों, डब्ल्यूएचओ और अन्य बहुपक्षीय संगठनों की कमियों से जोड़ा।

पैनल द्वारा उठाए गए मुद्दे

- 1. देर से चेतावनी:** महामारी के पहले हफ्तों में, WHO देशों को यह मानने के लिए चेतावनी दे सकता था कि SARS-CoV-2 वायरस एहतियात के तौर पर लोगों में फैल रहा था।
- 2. महामारी की देर से घोषणा:** WHO भी चीन के वुहान शहर में फैलने की घोषणा कर सकता था, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल -वैश्विक अलर्ट का उच्चतम स्तर - पहले कम से कम 22 जनवरी, 2020 तक।

3. कमजोर निकाय: WHO के पास तेजी से जांच करने की शक्ति और सदस्य राज्य की मंजूरी (चीन) की प्रतीक्षा किए बिना सूचना प्रकाशित करने की क्षमता के साथ, प्रकोपों की तेजी से जांच करने का अधिकार होना चाहिए।

4. खोये अवसर का एक महीना: अधिकांश देश चेतावनी पर ध्यान देने में विफल रहे, उन्होंने "प्रतीक्षा करें और देखें" का चयन किया, बजाय इसके कि वायरस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।

5. अंतरराष्ट्रीय नियमों में कमियों को दूर करने तथा राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए पैनल द्वारा छह महीने के भीतर एक महामारी फ्रेमवर्क कन्वेंशन की सिफारिश की गई।

6. वित्त पोषण में परिवर्तन: एक अंतरराष्ट्रीय महामारी-वित्तपोषण सुविधा की आवश्यकता है जो तैयारियों के लिए \$ 5 बिलियन से \$ 10 बिलियन प्रति वर्ष और संकट की स्थिति में \$ 50 बिलियन से \$ 100 बिलियन तक वितरित करने में सक्षम हो।

7. पैनल ने WHO के महानिदेशक और क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एकल, सात साल के कार्यकाल की भी सिफारिश की।

निष्कर्ष

कोविड -19, 21वीं सदी का चेरनोबिल क्षण है - इसलिए नहीं कि बीमारी का प्रकोप एक परमाणु दुर्घटना की तरह है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए खतरे की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दिखाया।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- डब्ल्यूएचओ और इसकी फंडिंग

इजरायल-फिलिस्तीन के बीच हिंसा

संदर्भ: इजरायली सेना और हमास के बीच चल रही हिंसा-2014 के बाद से सबसे भीषण लड़ाई - ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद थी।

हिंसा का क्या कारण था?

- **रमजान महीने के दौरान इजरायली पुलिस कार्रवाई:** वर्तमान संघर्ष के लिए तत्काल उकसावे की कार्रवाई इजरायली पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा रमजान की नमाज के बाद यरूशलेम में दमिश्क गेट पर फिलिस्तीनियों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई प्रतीत होती है - यह एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। जिसमें सैकड़ों नागरिक घायल हो गए।
- **हमास काउंटर:** कार्रवाई ने हमास (कई फिलिस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूहों में से सबसे बड़ा) को "रक्षक" का पद संभालने की अनुमति दी और उनके द्वारा शुरू किए गए बमों ने शुरू में तीन इजरायली नागरिकों को मार डाला।
- **इजरायली सेना द्वारा असंगत प्रतिक्रिया:** बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की प्रतिक्रिया अनुपातहीन थी। इसने गाजा में सैकड़ों हवाई हमले किए और कथित तौर पर तोपखाने और सैनिकों को भी तैनात किया।
- 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से कम से कम 27 बच्चे हैं। हमास और इस्राइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले और बम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाके इस्राइली हमलों का खामियाजा भुगत रहे हैं और कई दंगों की खबरें आ रही हैं।

हिंसा से किसे लाभ हो रहा है?

- जबकि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है, निश्चित रूप से कुछ ऐसे होते हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं।
- नेतन्याहू ऐसे समय में हमास के खिलाफ हमले का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं जब उनकी सरकार - जो विधायिका में अल्पमत में रही है और गिरने के कगार पर है। यह राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काता है और राजनीतिक लाभ प्रदान करता है।
- हमास भी संघर्ष में प्रासंगिकता पाता है, असंतोष की लपटों को भड़काने में जो कि गाजा जैसे स्थानों में सतह के नीचे होने के लिए बाध्य हैं, जहां एक पूरी पीढ़ी नाकाबंदी और कब्जे के माध्यम से रहती है।

हाल की हिंसा के निहितार्थ

- **हाल के लाभ का क्षरण:** इस क्षेत्र में कई इस्लामी शासनों द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की तुलना में कठोर रुख में नरमी आई थी (उदाहरण: अब्राहम समझौते)। हालांकि, हिंसा इस क्षेत्र में शांति के लिए एक गंभीर झटका है।
- **बिगड़ती स्थिति:** इस क्षेत्र में, इस्राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करने वालों के लिए यह कठिन हो सकता है।
- **चरम स्थितियों को बढ़ावा देता है:** इस्राइल और फ़िलिस्तीन के भीतर, यह चरमपंथी, शांति-विरोधी आवाज़ों को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **मूल समस्याएं अनसुलझी हैं:** अर्ध-कानूनी बंदोबस्तों, फ़िलिस्तीनियों और इजरायलियों द्वारा प्राप्त विभेदक अधिकारों और राजनीतिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में हिंसा के मूलभूत प्रश्न का समाधान नहीं किया गया है।

भारत

- भारत, अपने हिस्से के लिए, अब तक फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को इजराइल के साथ अपनी बढ़ती निकटता को संतुलित करने में कामयाब रहा है।
- दिल्ली को अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों या अपने मूल मानवीय मूल्यों से समझौता किए बिना, एक अच्छी दिशा में चलना जारी रखा है।

कोलंबो पोर्ट सिटी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- श्रीलंका में एक चीनी-वित्त पोषित कर-मुक्त एन्क्लेव ने हाल ही में अंतिम कानूनी बाधा को दूर किया क्योंकि इसके सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आगे बढ़ाया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे "कोलंबो पोर्ट सिटी" नाम दिया गया।
- यह श्रीलंका में चीन द्वारा अन्य बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सबसे बड़ा एकल विदेशी निवेश है।
- पोर्ट सिटी व्यापार, बैंकिंग और अपतटीय सेवाओं के लिए अरबों डॉलर को आकर्षित करेगा जो दुबई और सिंगापुर में उपलब्ध है।
- पोर्ट सिटी को एक आयोग द्वारा प्रशासित किया जाएगा जिसके पास निवेश अनुमोदनों को तेजी से ट्रैक करने के लिए विभिन्न शक्तियां होंगी।
- पोर्ट सिटी के भीतर सभी लेनदेन विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित होंगे और किसी भी कर्मचारी द्वारा अर्जित सभी वेतन कर-मुक्त होंगे।

लिथुआनिया ने चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग छोड़ा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- लिथुआनिया ने 22 मई, 2021 को 'मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच' को छोड़ दिया है। लिथुआनिया ने इसे "विभाजनकारी" करार दिया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग (चीन-CEE, चीन-CEEC)

- यह चीन की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों (CEEC) के 16 देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना।
- स्थापित: 2012 वारसों में
- लिथुआनिया के इसे छोड़ने के बाद इसे 16+1 मंच के रूप में जाना जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- मध्य और पूर्वी यूरोप एक शब्द है जिसमें मध्य यूरोप, बाल्टिक, पूर्वी यूरोप और दक्षिणपूर्व यूरोप (बाल्कन) के देश शामिल हैं।
- आमतौर पर इसका मतलब पूर्वी ब्लॉक से पूर्व कम्युनिस्ट राज्य और यूरोप में वारसों संधि है।
- लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है।
- **राजधानी:** विनियसा।

बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका के साथ 'मुद्रा विनिमय समझौता'

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है।
- यह श्रीलंका को उसके विदेशी मुद्रा संकट में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मुद्रा स्वेप को प्रभावी रूप से ऋण के रूप में देखा जा सकता है, जो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर के रूप में दिया जाएगा, साथ ही इसमें यह समझौता भी शामिल है कि ऋण और उसके साथ ब्याज का भुगतान श्रीलंकाई रुपए में किया जाएगा।
- यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिये सामने आया है।
- यह भी पहली बार है कि श्रीलंका भारत के अलावा किसी अन्य सार्क देश से ऋण ले रहा है।

श्रीलंका ने भारत से संपर्क नहीं किया क्योंकि

- कोलंबो बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण कंटेनर टर्मिनल परियोजना को रद्द करने के कोलंबो के फैसले पर भारत-श्रीलंका संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे भारत ने क्रेडिट स्वेप के निर्णय को टाल दिया है।
- पिछले जुलाई में, आरबीआई ने श्रीलंका को \$400 मिलियन की क्रेडिट स्वेप सुविधा प्रदान की थी, जिसे फरवरी में तय किया गया था।
- इससे पूर्व जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट स्वेप सुविधा प्रदान की थी और इस सौदे को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने फरवरी माह में निपटा दिया था।
- व्यवस्था का विस्तार नहीं किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के भीतर एक स्वेप व्यवस्था की पेशकश करता है।
- सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई थी।

संबंधित आलेख

भारत डॉलर स्वेप लाइन को सुरक्षित करना चाहता है।

म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता

संदर्भ: म्यांमार में 1 फरवरी के सैन्य तख्तापलट (म्यांमार के इतिहास में तीसरा ऐसा तख्तापलट) ने सत्तारूढ़ सैन्य शक्ति के खिलाफ देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया - है। वहाँ की सेना ने सत्ता हासिल की क्योंकि उन्हें डर था कि शानदार चुनावी जीतने के बाद, आंग सान सू की सरकार सेना की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

क्या तुम्हें पता था?

- म्यांमार का वर्ष 2008 का संविधान सेना को एक विशेष स्थान प्रदान करता है, जिसमें संसद और स्थानीय विधानमंडलों में 25% सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, वास्तव में गृह, रक्षा और सीमा मामलों जैसे प्रमुख मंत्रालयों के लिए।
- यह संविधान वहाँ पर विदेशी पत्नियों वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति बनने से भी अयोग्य ठहराता है।

भारत के लिए तख्तापलट के निहितार्थ

- **पिछले दशक में हुई प्रगति का खत्म होना :** म्यांमार ने एक दशक पहले जो अर्ध-लोकतांत्रिक प्रयोग शुरू किया था, अब वह निरस्त कर दिया गया है। भारत म्यांमार में लोकतंत्र का चैंपियन था और उसने अपने लोकतांत्रिक परिवर्तन में मार्गदर्शन प्रदान किया था।
- **चीन का उदय:** सेना के नेतृत्व में म्यांमार सरकार का बढ़ता अंतरराष्ट्रीय अलगाव एक बार फिर देश को चीन पर निर्भरता में धकेल सकता है।
- **विदेश नीति एजेंडा में बाधाएं:** म्यांमार में हाल के घटनाक्रम भारत के लिए एक गंभीर नीति चुनौती पेश करते हैं। भारत की 'पड़ोसी पहले', 'एक्ट ईस्ट' और 'इंडो-पैसिफिक' नीतियों की सफलता के लिए म्यांमार एक महत्वपूर्ण अंग है।
- **सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा:** तख्तापलट के बाद के समय में राजनीतिक अस्थिरता से म्यांमार सेना का ध्यान उसकी क्षेत्र और उसकी सीमाओं से हटने की उम्मीद है। इससे भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव पैदा हो सकता है (शरणार्थी, विद्रोही, अवैध आंदोलन) आदि।
- **विलंबित कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** म्यांमार के चिन और खाइन राज्यों में शांति कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राजनीतिक अस्थिरता इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को धीमा कर देती है जिससे उप-क्षेत्रीय एकीकरण में और देरी हो रही है।
- **शरणार्थी मुद्दा:** म्यांमार से मणिपुर और मिजोरम में शरणार्थियों की अन्तर्वाह (सामान्य जातीय संबंधों और पारिवारिक संबंधों के कारण) म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत के लिए चिंता का विषय है।

भारत का रुख

- भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की कि म्यांमार द्वारा पिछले दशकों में किए गए लोकतांत्रिक लाभ को कम नहीं आंकना चाहिए।
- भारत ने लोकतांत्रिक संक्रमण की प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दोहराया और आश्वासन दिया कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से म्यांमार में भारत के विकासात्मक और मानवीय प्रयास जारी रहेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत ने UNHRC को बताया कि म्यांमार में कानून -शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कायम रखा जाना चाहिए और हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- 2021-2022 के दौरान UNSC के एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में, भारत अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में वियतनाम जैसे अन्य भागीदारों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यह देखते हुए कि वियतनाम भी इस वर्ष UNSC का गैर-स्थायी सदस्य है। यदि संयुक्त राष्ट्र और आसियान के माध्यम से एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का निर्माण किया जाता है, तो म्यांमार में सेना को लोकतांत्रिक रोड मैप पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझोउ-2

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- चीन ने हाल ही में एक कार्गो अंतरिक्ष यान, तियानझोउ-2 को लॉन्च किया और सफलतापूर्वक डॉक किया।
- यह अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे लॉन्ग मार्च-7 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
- इसके बाद एक अन्य कार्गो अंतरिक्ष यान, तियानझोउ-3 और दो मानवयुक्त मिशन, शेनझोउ-12 और शेनझोउ-13 का प्रक्षेपण किया जाएगा।
- मानवयुक्त मिशनों में से प्रत्येक में तीन अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कक्षा में कई महीने बिताएंगे।

क्या आप जानते हैं?

- हाल के सप्ताहों में यह प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए तीसरा मील का पत्थर साबित हुआ।
- चीन ने अपने पहले मार्स रोवर, ज़ूरोंग को लेकर 15 मई को मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा।
- तियानझे मॉड्यूल, जिसे कार्गो अंतरिक्ष यान के साथ डॉक किया गया था, यह 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था।

संबंधित आलेख

- चीन द्वारा मंगल ग्रह की लैंडिंग
 - लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट का पुनः प्रवेश
-

SARS-CoV-2 की उत्पत्ति में अमेरिकी जांच

संदर्भ: 14 मई को, 18 वैज्ञानिकों के एक समूह, जिनमें से अधिकांश यू.एस. से थे, उन्होंने जर्नल साइंस में एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें COVID-19 महामारी की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए आगे की जांच का आह्वान किया था।

यह आवश्यक था क्योंकि उत्पत्ति पर दो सिद्धांत-

- वायरस गलती से चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से निकल गया होगा या
- यह कुछ जानवरों की प्रजातियों से मनुष्यों में फैलने का परिणाम था

वायरस की उत्पत्ति को समझना आवश्यक क्यों है?

- बायोलॉजिकल अनुसंधान करने वाली प्रयोगशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने और पशु उत्पत्ति की महामारियों को रोकने के लिए वायरस की उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को क्या करने के लिए कहा गया है?

- वैज्ञानिकों द्वारा जारी आह्वान के बाद से, यू.एस. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, 26 मई को, खुफिया एजेंसियों द्वारा वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश दिया।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक ने भी स्वीकार किया है कि प्रयोगशाला रिसाव सिद्धांत पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है, हालांकि वुहान का दौरा करने वाली WHO टीम ने रिसाव को कम से कम संभावित परिकल्पना माना।
- यू.एस. में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने अनुमान लगाया है कि वायरस प्राकृतिक उत्परिवर्तन से उभरा है।

नए सिरे से जांच की मांग क्यों उठी?

- WHO के गवर्निंग फोरम, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2020 में महानिदेशक को SARS-CoV-2 की उत्पत्ति की जांच करने का आदेश दिया और जनवरी-फरवरी 2021 में WHO और चीन द्वारा एक संयुक्त जांच की गई।
- चूंकि दोनों में से किसी भी परिकल्पना के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था - प्राकृतिक स्पिलओवर या प्रयोगशाला रिसाव - जब रिपोर्ट पशु मूल परिकल्पना के पक्ष में थी, तो इसे संभावित होने की संभावना के रूप में वर्णित किया गया था, और कहा गया था कि एक प्रयोगशाला घटना थी इसकी बहुत संभावना नहीं थी।
- WHO के महानिदेशक ने कहा कि उन्होंने जांच को पर्याप्त व्यापक रूप में नहीं देखा, और इस दृष्टिकोण के साथ गए कि आगे की जांच की आवश्यकता है, संभावित रूप से विशेषज्ञ विशेषज्ञों को शामिल करने वाले अतिरिक्त मिशन आवश्यक थे।
- अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि WHO टीम द्वारा प्रयोगशाला रिसाव की संभावना पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया था और वास्तव में, इसे "षड्यंत्रकारी सिद्धांत" के रूप में माना गया।

प्राकृतिक उत्पत्ति की परिकल्पना का आधार क्या है?

- संभावित प्राकृतिक उत्पत्ति के अपने अध्ययन के आधार पर, संयुक्त WHO-चीन अध्ययन रिपोर्ट एक (घोड़े की नाल) चमगादड़ (SARSr-CoV; RaTG13) में SARS से संबंधित कोरोनावायरस की पहचान करती है, जिसमें SARS-CoV-2 वायरस में 96.2% जीनोमिक समानता है।
- नोवल कोरोनावायरस, SARS (गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम) और MERS (मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम) जैसी अन्य महामारियों का कारण बनने वाले वायरस के जीनोम की तुलना में कम समान है।
- फिर से, SARS-CoV-2 की उच्च संक्रामकता को इसके स्पाइक प्रोटीन में चार अमीनो एसिड के अनूठे सम्मिलन के रूप में शामिल विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उदाहरण के लिए, जो इसे SARS पैदा करने वाले वायरस से अधिक कुशल बनाता है।
- चीन में पैंगोलिन पाए जाने वाले कुछ कोरोनावायरस आरबीडी में SARS-CoV-2 के समान हैं, जो यह दर्शाता है कि मानव जैसे ACE2 के साथ कुशल बंधन के लिए अनुकूलित स्पाइक प्रोटीन प्राकृतिक चयन के परिणामस्वरूप हो सकता है।
- यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब दुनिया को पंगु बनाने वाले के लिए एक पूर्वज वायरस के लिए कोई सीधा लिंक नहीं पहचाना जा सका है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायरस मध्यवर्ती जानवरों के बीच फैलने के लिए खुद को अनुकूलित कर सकता है और फिर मनुष्य एक स्वाभाविक था।
- यह भी संभव है कि एक पहले का वायरस मनुष्यों द्वारा अधिग्रहित किया गया हो, और यह संचरण में अधिक कुशल हो गया क्योंकि यह एक अज्ञात चरण के दौरान मनुष्यों में फैल गया।
- वैज्ञानिकों ने इस संभावना की जांच की कि प्रयोगशाला से अनजाने में SARS-CoV-2 का विमोचन हो सकता है, लेकिन उनका तर्क है कि इस तरह के प्रयोग के लिए बहुत अधिक आनुवंशिक समानता वाले किसी भी पूर्वज वायरस का वर्णन नहीं किया गया है, और वायरस में होने वाले परिवर्तनों को संचारित करने के कुशलता से सेल संस्कृतियों या समान ACE2 रिसेप्टर्स वाले जानवरों के माध्यम से इसके बार-बार पारित होने को शामिल किया होगा, जिनका वर्णन भी नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान संकट में जो बात सबसे अलग है, वह है सुरक्षित बायोलॉजिकल प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए एक वैश्विक ढांचे के लिए उभरती हुई कॉल, और संबंधित कोरोनावायरस, मेजबानपशु, उत्परिवर्तन और उन रास्तों में अधिक अंतर्दृष्टि, जिनके द्वारा उपन्यास वायरस मनुष्यों को संक्रमित करते हैं।

टोक्यो ओलंपिक और वायरस (COVID-19)

संदर्भ: जुलाई 2021 में, जापान ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए कमर कस कर रहा है क्योंकि ताजा संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है।

हालाँकि, अप्रैल के मध्य से चीजें बदलने लगीं जब जापान कोविड -19 महामारी की चौथी लहर की चपेट में आ गया।

जापान में कोविड की स्थिति

- इस मार्च महीने में जापान में सात दिनों में औसतन 1,000 से कम कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और विशेषज्ञों का मानना था कि देश ने पिछले एक साल में तीसरी बार महामारी पर काबू पाया है।
- 8 मई को, जापान के कोविड-19 मामले जनवरी के मध्य के बाद पहली बार 7,000 से ऊपर हो गए और वर्तमान में, जापान अभी भी एक दिन में 4,000 से अधिक मामले दर्ज कर रहा है।
- देश में वायरस से 700,000 से अधिक संक्रमण और 12,000 कोविड -19 मौतें दर्ज की गई हैं।
- जापान में कोविड-19 के मामले इतनी तेजी से देखे जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था, प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने पहले ही देश के नौ प्रान्तों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है, जिसमें टोक्यो भी शामिल है जुलाई के महीने में यह ओलंपिक खेलों का स्थान भी है।
- चौथी लहर ने जापान को इतनी बुरी तरह क्यों प्रभावित किया है? (इन बिंदुओं की भारत की स्थिति से तुलना करें)
- **धीमा टीकाकरण:** जापान की वैक्सीन का रोलआउट औद्योगिक दुनिया में सबसे धीमी गति से किया गया है, जिसमें केवल 2.4 प्रतिशत आबादी ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है। इसने अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत बाद में फरवरी में ही लोगों को टीका लगाना शुरू किया।
- **छोटा लक्ष्य समूह:** इसके अलावा, इस सप्ताह ही सरकार ने टोक्यो और ओसाका में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया। लेकिन सरकार के मौजूदा लक्ष्य केवल 65 से अधिक लोगों को जुलाई के अंत तक पूरी तरह से टीका लगाने के लिए कहा गया, जब ग्रीष्मकालीन में खेल शुरू होने की उम्मीद है।
- **टीकाकरण के लिए कई बाधाएं:** हालांकि, आपूर्ति की कमी और लॉजिस्टिकल संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति काफी धीमी है, जैसे कि मदद के लिए पर्याप्त स्थानीय डॉक्टरों का मिलना। स्लॉट सुरक्षित करने के बारे में भी काफी भ्रम है। देश भर में कई लोगों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे नए जन टीकाकरण केंद्रों के लिए अपने स्लॉट बुक करते समय त्रुटियों के बारे में शिकायत की है।

ओलंपिक के बारे में क्या?

- एक साल के लिए स्थगित होने के बाद (माना जाता है कि 2020 में आयोजित किया गया था), टोक्यो ओलंपिक दुनिया भर से कड़ी आलोचना के बावजूद आगे बढ़ने के लिए निर्धारित है।
 - जापान में महामारी के साथे में खेलों को आयोजित करने का विरोध भी बढ़ गया है, देश के प्रमुख बिजनेस टाइकून में से एक ने खेलों को जारी रखने के अपने फैसले पर सरकार की आलोचना की है।
 - जापान में जारी एक सर्वेक्षण में, मतदान करने वालों में से 83 प्रतिशत ने कहा कि वे नहीं चाहते कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक आयोजित करें। अप्रैल महीने में एक सर्वेक्षण से यह कुल 14 प्रतिशत अंक ऊपर था।
 - ओलंपिक, अब तक 1916, 1940 और 1944 में केवल तीन बार रद्द किया गया है तीनों मामले दोनों विश्व युद्धों के कारण। इसलिए, बढ़ती आलोचना और विरोध के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष जॉन कोट्स ने वादा किया है कि कोविड प्रतिबंधों के तहत भी खेल को बिल्कुल आगे बढ़ाया जायेगा।
-

भारत और विश्व

USA की COVID बचाव योजना और भारत के लिए सबक

संदर्भ: राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी कांग्रेस में जो बिडेन के पहले संयुक्त संबोधन के दौरान, उन्होंने अमेरिकी विकास पथ के लिए एक नए प्रतिमान की रूपरेखा तैयार की।

जो बिडेन के योजना की मुख्य विशेषताएं

- **ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन:** बाइडेन ने कहा कि "अमेरिकन जॉब्स प्लान में सृजित इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स में से लगभग 90% के लिए कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। और 75% को सहयोगी के डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकन जॉब्स प्लान अमेरिका के निर्माण का ब्लू-कॉलर ब्लूप्रिंट है।
- **कामगारों को मजबूत करने का अधिकार:** मजदूर वर्ग की बार्गेनिंग की क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने कांग्रेस से संगठित होने के अधिकार की रक्षा करने का कानून पारित करने का आह्वान किया, जो संघ बनाने के अधिकार का समर्थन करेगा।
- **लैंगिक समानता और न्यूनतम वेतन बढ़ाना:** बाइडेन ने अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और महिलाओं को समान वेतन प्रदान करने के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने कहा, चलो न्यूनतम वेतन बढ़ाकर \$15 करें। सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहना चाहिए।
- **अच्छी शिक्षा तक पहुंच:** यहां, बिडेन सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा को 12 से बढ़ाकर 16 साल करके साथ ही अनुदान में वृद्धि करना चाहते हैं और ऐतिहासिक ब्लैक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, आदिवासी कॉलेजों, अल्पसंख्यक-सेवारत संस्थानों में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि इन संस्थानों के पास बंदोबस्ती नहीं है।
- **चाइल्ड केयर गरीबी को संबोधित करना:** बाइडेन की योजना का एक अन्य प्राथमिकी एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के लिए टैक्स क्रेडिट का विस्तार करके सीधे लाखों अमेरिकियों की जेब में पैसा डालता है - जिसका उद्देश्य 65 मिलियन से अधिक बच्चों की मदद करना और बच्चों की देखभाल की गरीबी को आधा करना है।
- **अफोर्डेबल हेल्थकेयर:** बिडेन ने हेल्थकेयर प्रीमियम और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की कीमत को कम करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल एक अधिकार होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं।
- **"ट्रिकल डाउन" अर्थशास्त्र के बजाय बॉटम अप / मिडल आउट अर्थशास्त्र:** इन योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, बिडेन ने "ट्रिकल डाउन" अर्थशास्त्र (TDE) की लंबे समय से चली आ रही धारणा को तोड़ दिया, जो धनी लोगों के लिए कर कटौती की सिफारिश करती थी। उन्होंने घोषणा की कि सबसे धनी 1 प्रतिशत अमेरिकियों को अपने उचित हिस्से का भुगतान करना शुरू करना होगा।

तो, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बाइडेन के भाषण का क्या महत्व है?

- **नव-उदारवाद से दूर जाना:** बिडेन की रणनीति - बड़े सरकारी खर्च के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमीरों और व्यापारी वर्ग से राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना। 2014 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई न्यूनतम सरकारी रणनीति के नव-उदारवादी दृष्टिकोण के विपरीत है।
- **बढ़ती असमानता समस्या है:** वर्ष 2020, भारत में मध्यम वर्ग के एक तिहाई कम होने की संभावना थी और लगभग 75 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए थे, जबकि भारत दुनिया में तीसरा सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश बन गया था। इसी प्रकार की बढ़ती असमानता को सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि करके धन के पुनर्वितरण की बिडेन की रणनीति द्वारा संबोधित करने की मांग की गई है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पूंजीवाद बनाम समाजवाद बनाम मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था
-

भारत-यूके आभासी (वर्चुअल) शिखर सम्मेलन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- भारतीय प्रधान मंत्री और यूके के प्रधान मंत्री ने वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

रोडमैप 2030

- द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक ले जाने के लिए।
- यह रोडमैप अगले दस वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन व मजबूत जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उन्नत व्यापार भागीदारी (ETP)

- यह 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।
- 'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ईटीपी) के एक हिस्से के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यापक एवं संतुलित एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) पर बातचीत करने के लिए एक रोडमैप पर भी सहमति जताई है।

भारत-यूके 'ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप'

- इसका उद्देश्य अफ्रीका से शुरू होकर चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों के हस्तांतरण का समर्थन करना है।

प्रवास और गतिशीलता पर एक व्यापक साझेदारी

- यह दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता के लिए अधिक अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- दोनों पक्षों ने डिजिटल एवं आईसीटी उत्पादों सहित नई व उभरती प्रौद्योगिकियों पर आपसी सहयोग बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है।
 - दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की जिनमें समुद्री क्षेत्र, आतंकवाद का मुकाबला करना और साइबरस्पेस क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं।
 - यूके अनुसंधान और नवाचार सहयोग में भारत का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है।
-

लचीले भविष्य के लिए सहयोग संगोष्ठी-एशियाई विकास बैंक (ADB) की वार्षिक बैठक का हिस्सा

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां "लचीले भविष्य के लिए सहयोग" विषय पर गवर्नरों की संगोष्ठी में भाग लिया जिसका आयोजन एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक 2021 के हिस्से के रूप में किया गया था।

अन्य सम्बंधित तथ्य

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- इसकी कल्पना 1960 के दशक की शुरुआत में की गई थी जब 1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- इस संस्था को, 1966 में फिलीपींस के मनीला में 31 प्रारंभिक सदस्यों के साथ खोला गया था।
- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस
- **सदस्य:** इसमें 67 सदस्य हैं- जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के भीतर तथा अन्य 19 बाहर से हैं।
- भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- **उद्देश्य:** एक वित्तीय संस्थान जो एशियाई चरित्र का होगा और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देगा।
- यह एडीबी ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है।
- **कार्य :** एडीबी को विश्व बैंक पर नजदीकी से तैयार किया गया, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है जहां सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं।
- 31 दिसंबर 2016 तक, जापान और यूएसए के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात (15.607%), चीन के पास 6.444%, भारत के पास 6.331% और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.786% है।
- एडीबी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।

‘इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी (QFCA) के बीच हुए समझौता ज्ञापन

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी (QFCA) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्वीकृति प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस एमओयू से कतर में लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
- ICAI का दोहा, कतर में एक सक्रिय चैप्टर है जो वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था और ICAI के 36 विदेशी अध्यायों में सबसे पुराना है।
- कतर (दोहा) अध्याय आईसीएआई के सबसे जीवंत अध्यायों में से एक है।

अन्य संबंधित तथ्य

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)

- यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
 - उद्देश्य: भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी व्यवसाय को विनियमित करने के लिए।
-

भारत-चीन: लद्दाख गतिरोध से सबक

संदर्भ: एक साल से अधिक समय के बाद, पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध समाधान के कोई संकेत नहीं दिखाता है। विघटन स्थिर गया है, चीन अपने सैनिकों को मजबूत कर रहा है, और बातचीत विफल रही।

सीमा तनाव के निहितार्थ

- मोटे तौर पर, भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध टूट गए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि संबंध सीमा पर शांति की शर्त पर हैं।
- राजनीतिक संबंध शत्रुता और अविश्वास से चिह्नित होते हैं।
- एक लंबे समय से चली आ रही नीति को उलटते हुए, भारत संभावित रूप से आकर्षक व्यापक संबंधों के लिए समस्याग्रस्त सीमा विवाद की अनदेखी नहीं करेगा;
- यदि विघटन जारी रहता है, तो भी संबंध अस्थिर करने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील रहेंगे।

सीखने के लिए महत्वपूर्ण सबक

1. चीन को भौतिक लागतों के बजाय राजनीतिक लागतों के खतरे से डराने या जबरदस्ती करने की अधिक संभावना है।

- चीन का रक्षा बजट भारत की तुलना में तीन से चार गुना बड़ा है, और इसकी पश्चिमी थिएटर कमान में 200,000 से अधिक सैनिक हैं। संकट का भौतिक बोझ इसकी मौजूदा प्राथमिकताओं को बाधित नहीं करेगा।
- इसके विपरीत, भारत ने चीन के लिए संकट के जोखिम को राजनीतिक टूटने की धमकी के माध्यम से सफलतापूर्वक उठाया, न कि सैन्य दंड के द्वारा।

2. हिंद महासागर प्रमुख क्षेत्र

- भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक उत्तोलन और प्रभाव के बदले एलएसी पर अधिक जोखिम स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए।
- भूमि सीमा पर, कठिन भूभाग और यहां तक कि सैन्य बल के संतुलन का मतलब है कि प्रत्येक पक्ष केवल मामूली लाभ ही प्राप्त कर सकता है।
- इसके विपरीत, भारत पारंपरिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्ति रहा है और यदि इस क्षेत्र में चीनी सैन्य शक्ति के तेजी से विस्तार का जवाब देने में विफल रहता है तो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा खो देता है।
- लद्दाख संकट, एलएसी के बढ़ते सैन्यीकरण को प्रेरित करके, लंबे समय से लंबित सैन्य आधुनिकीकरण और हिंद महासागर में समुद्री विस्तार को स्थगित नहीं करना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पाकिस्तान के नए मानचित्र पर - महत्वपूर्ण विश्लेषण
 - भारत-नेपाल सीमा विवाद: कालापानी और लिपुलेख
-

भारत-अफ्रीका संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1920 के दशक की शुरुआत में दोनों क्षेत्रों ने औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, यह संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी उपनिवेशवाद के समर्थन में एक अग्रणी वोट बन गया।

- स्वतंत्र भारत, हालांकि दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शोषण के बाद बेहद गरीब, दक्षिण सहयोग के बैनर तले अफ्रीकी देशों के साथ अपने सीमित संसाधनों को साझा करने का प्रयास किया।
- 1964 में, भारत ने अन्य विकासशील देशों को मानव संसाधन विकास के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम शुरू किया। यह अफ्रीका सबसे बड़ा लाभार्थी था
- दूसरी ओर, अफ्रीका के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभ में ही तेज होने लगी थी। अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार 2003 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018 में 76.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और भारत अब अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

चुनौतियां

- सरकार का लक्ष्य अफ्रीकी महाद्वीप को एक करोड़ वैक्सीन खुराक निर्यात करना है। हालांकि दूसरी लहर और घरेलू मांग बढ़ने से निर्यात की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
- भारतीय क्रेडिट लाइन (LoCs) को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा या सभी के लिए शिक्षा जैसे बड़े विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किया गया है। LoCs आमतौर पर प्राप्तकर्ता देशों द्वारा सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों जैसी छोटी विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए उपयोग किया जाता है।
- भारत के विभिन्न विकास उपकरणों के बीच कोई तालमेल नहीं है।
- इसके अलावा, खराब संवितरण दरों और परियोजना के पूरा होने के रिकॉर्ड के साथ, कार्यान्वयन भारतीय नियंत्रण रेखा के लिए एक प्रमुख बाधा रही है।
- भारत में अफ्रीकी छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं आम हैं, जिसने भारत-अफ्रीका संबंधों में खटास पैदा की है
- यद्यपि भारत के पास अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच अपार सामाजिक पूंजी है, लेकिन भौतिक संबंधों में इसका मिलान नहीं हुआ है, और अफ्रीका में चीन की आर्थिक और निवेश उपस्थिति कई वर्षों से भारत से आगे निकल रही है।
- चीन अनिवार्य रूप से अफ्रीकी देशों को विकास का एक वैकल्पिक सत्तावादी मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसका संदेश यह है कि अब उदार अंतरराष्ट्रीय मार्ग अफ्रीकी देशों के लिए एकमात्र रास्ता नहीं रह गया है जिससे वे आगे बढ़ सकें और समृद्ध हो सकें।

अपने सीमित संसाधनों के साथ, भारत अफ्रीका के साथ अपने विकास सहयोग को निम्नलिखित तरीकों से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर सकता है:

- अफ्रीकी विकास के लिए स्पष्ट रणनीति
- क्षमता निर्माण पर वर्तमान फोकस जारी रखें
- भारतीय नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और प्रवासी भारतीयों का उपयोग करें:
- विकास के अनुकूल निजी निवेश को बढ़ावा देना:
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना
- भारत में अफ्रीकियों के अनुभवों में सुधार करना
- एक सोची समझी योजना बनाई वैक्सीन रणनीति जो भारत और अफ्रीका के हितों को संतुलित करती है

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अफ्रीका में महामारी और भारत के लिए अवसर
- एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा



अर्थव्यवस्था

2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त रकम प्रदान करने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए “राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना” पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और राज्य सरकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2021-22 में इसे जारी रखने का फैसला लिया है।

क्या आप जानते हैं?

- 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय को लेकर राज्यों की विशेष सहायता की योजना के तीन भाग हैं :
 - **भाग-I:** यह उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए है
 - **भाग-II:** यह भाग-I में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्यों के लिए है। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।
 - **भाग-III:** योजना का यह भाग बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसई) के विनिवेश के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है।
1. योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
 2. इस भाग के तहत परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, सूचीकरण और विनिवेश के माध्यम से राज्यों को उनके द्वारा प्राप्त की गई रकम का 33 फीसदी से 100 फीसदी तक 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

कानूनी मेट्रोलाजी (पैकेजिंग नियम 2011)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, चिकित्सा उपकरणों के आयातकों, जो विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, को अब इन उपकरणों को पूर्व अनिवार्य घोषणा के बिना आयात करने की अनुमति है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कस्टम क्लीयरेंस के बाद आयातक सभी आवश्यक घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उपभोक्ताओं को बेची जाएं।
- कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011, आयात से पहले अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बनाते हैं।
- उपभोक्ता मामले विभाग कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 का प्रशासन करता है।

क्या आप जानते हैं?

- अधिनियम माप और माप उपकरणों के लिए कानूनी आवश्यकताओं के आवेदन के लिए प्रदान करता है।
- कानूनी मेट्रोलॉजी का उद्देश्य तौल और माप की सुरक्षा और सटीकता की दृष्टि से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना है।
- कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ता पहले से पैक की गई वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाओं के बारे में सूचित करके सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हैं।

चार मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी पर गठित कोडेक्स समिति (CCSCH) ने लौंग, ओरगैनो, तुलसी और अदरक के लिए मानक तय किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- समिति ने इन चार नए मानकों को पूर्ण विकसित कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) को अग्रेषित किया।
- नई कार्य मर्दों को भी लिया गया: समिति की ओर से छोटी इलायची और हल्दी के लिए कोडेक्स मानकों को विकसित करना और 'सूखे फल और जामुन' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मसालों के लिए पहला समूह मानक विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- CCSCH कोडेक्स कमोडिटी समितियों में सबसे युवा है।
- इस समिति की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है।
- स्पाइसेस बोर्ड इंडिया इसका सचिवालय है।
- **अधिदेश:** उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के कोडेक्स सिद्धांतों के अनुसार, मसालों और पाक जड़ी बूटियों के लिए दुनिया भर में विज्ञान आधारित गुणवत्ता मानकों को विस्तृत करने के लिए।
- डॉक्टर एम आर सुदर्शन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

RBI ने COVID-19 के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से गंभीर रूप ले चुकी कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक अव्यवस्था से मुकाबला करने के लिए नये उपायों की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रेपो दर पर तीन साल तक के कार्यकाल के साथ 50,000 हजार करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा करने के लिए एक अनिर्धारित पते का उपयोग किया।
- **लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन:** लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और सहायता प्रदान करना है। एसएफबी के लिए रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये के विशेष तीन साल के दीर्घकालिक रेपो परिचालन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के नए ऋण देने के लिए तैनात किया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर, 2021 तक खुली रहेगी।
- **SFBs द्वारा MFIs को दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:** नई चुनौतियों और छोटे एमएफआई की उभरती हुई तरलता की स्थिति को देखते हुए, एसएफबी को अब व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को चालू करने के लिए छोटे एमएफआई (500 करोड़ रुपये तक की संपत्ति के साथ) के लिए नए ऋण देने की अनुमति दी जा रही है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में। यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध होगी।
- **बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए केवाईसी मानदंडों का युक्तिकरण:** प्रस्तावित किए जा रहे कदमों में शामिल हैं -
 - प्रोपराइटरशिप फर्मों जैसी नई ग्राहक श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी का क्षेत्र बढ़ाना,
 - सीमित केवाईसी खातों को पूरी तरह से केवाईसी अनुपालक खातों में बदलना,
 - केवाईसी अपडेट करने में अधिक ग्राहक-अनुकूल विकल्पों का परिचय और
 - वी-सीआईपी के लिए केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) के केवाईसी पहचानकर्ता के उपयोग को सक्षम करना और पहचान प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जमा करना
- फ्लोटिंग प्रावधान और काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर: बैंक अब एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक अपने द्वारा रखे गए फ्लोटिंग प्रावधानों के 100% का उपयोग कर सकते हैं; (31 मार्च 2022 तक)
- राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा में छूट: राज्य सरकारों के लिए एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिनों की अधिकतम संख्या 36 से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है।

दलहन उत्पादन के लिए खरीफ रणनीति 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से खरीफ 2021 सत्र में कार्यान्वयन के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य सरकारों के साथ परामर्श के माध्यम से, अरहर, मूंग और उड़द की बुआई के लिए रकबा (क्षेत्र) और उत्पादकता दोनों बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
- रणनीति के तहत, सभी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना शामिल है। केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध यह उच्च उपज की किस्म वाले बीज, एक से अधिक फसल और एकल फसल के माध्यम से बुआई का रकबा बढ़ाने वाले क्षेत्र में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

- किसानों को प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATARIs) और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा।

व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और MSMEs की COVID से संबंधित तनावग्रस्त समाधान फ्रेमवर्क 2.0

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- आरबीआई ने उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणियों - व्यक्तियों, उधारकर्ताओं और एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले तनाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 25 करोड़ रुपये तक के कुल एक्सपोजर वाले व्यक्ति, उधारकर्ता और एमएसएमई, जिन्होंने किसी भी पिछले ढांचे के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं उठाया है, लेकिन उन्हें 31 मार्च, 2021 को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वे संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 के तहत विचार करने के पात्र होंगे।
- इसे 30 सितंबर, 2021 तक लागू किया जा सकता है और आह्वान के 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा।
- उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए जिन्होंने रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत ऋणों के पुनर्गठन का लाभ उठाया है, जहां 2 साल से कम की प्रतिबंध की अनुमति थी, उधार देने वाली संस्थाएं अब अवधि बढ़ा सकती हैं और/या शेष अवधि को कुल 2 साल तक बढ़ा सकती हैं।
- पहले पुनर्गठित किए गए छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को अब एकजुट उपाय के रूप में कार्यशील पूंजी स्वीकृति सीमाओं की समीक्षा करने की अनुमति है।

हिमालय में उगाए गए जैविक बाजरा को डेनमार्क में निर्यात

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देवभूमि में पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप, उत्तराखंड से डेनमार्क को निर्यात की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एपीडा, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड (यूकेएपीएमबी) और एक निर्यातक के रूप में जस्ट ऑर्गेनिक उत्तराखंड के किसानों से रागी (फिंगर मिलेट), और झिंगोरा (बार्न यार्ड मिलेट) खरीदकर और उसे प्रसंस्कृत निर्यात करता है, जो यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करता है।
- उच्च पोषक मूल्यों और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण भी बाजरा विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- ऑयल केक देश से जैविक उत्पाद निर्यात की एक प्रमुख उत्पाद है। जिसके बाद ऑयल सीड, फलों की पल्प और प्यूरी, अनाज और बाजरा, मसाले, चाय, औषधीय पौधों के उत्पाद, सूखे फल, चीनी, दालें, कॉफी, आवश्यक तेल आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में उन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है जो जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) की आवश्यकताओं के अनुसार फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबल किए जाते हैं।

- एनपीओपी के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत शामिल उत्पादों को भारत में आयात के लिए दोबारा प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है।

5वीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों का समय

संदर्भ: सरकार ने हाल ही में नए बैंकिंग सुधारों की घोषणा की, जिसमें बुनियादी ढांचे के लिए एक विकास वित्त संस्थान (DFI) की स्थापना, पुरानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या का समाधान करने के लिए एक बैड बैंक का निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का निजीकरण शामिल है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र निरंतर आधार पर विकसित हो रहा है-

	सुधार	परिणाम
पहली पीढ़ी	स्वतंत्रता-पूर्व अवधि (1947 तक) के दौरान स्वदेशी आंदोलन ने कई छोटे और स्थानीय बैंकों को जन्म दिया।	उनमें से अधिकांश आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर संबद्ध उधार और व्यापार एवं बैंकिंग बुक के संयोजन के कारण विफल रहे।
दूसरी पीढ़ी (1947-1967)	भारतीय बैंकों ने खुदरा जमा के माध्यम से संसाधन जुटाने की सुविधा प्रदान की)	बैंकिंग क्षेत्र कुछ व्यावसायिक परिवारों या समूहों में केंद्रित हो गया। कृषि के लिए उपेक्षित ऋण प्रवाह।
तीसरी पीढ़ी (1967-1991)	सरकार द्वारा दो प्रमुख चरणों (1969 और 1980) में 20 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उद्योगों तथा बैंकों के बीच सांठ-गांठ तोड़ने तथा प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रवाह को लागू करने (1972) में सफल रही।	इन पहलों के परिणामस्वरूप 'क्लास बैंकिंग' से 'मास बैंकिंग' में बदलाव संभव हुआ। इसके अलावा भारत (ग्रामीण) में शाखा नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक जमा और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, बैंकिंग उद्योग ने इस अवधि के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट मानकों में छूट के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति गुणवत्ता, वित्तीय सुदृढ़ता और दक्षता में गिरावट का अनुभव किया।
चौथी पीढ़ी (1991-2014)	भारतीय बैंकिंग ने ऐतिहासिक सुधारों को देखा ● निजी एवं विदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी करना ● इसकी प्राप्ति प्रौद्योगिकी की सहायता से; विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत करके; ● कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ बैंकों के परिचालन में लचीलापन प्रदान करके; ● कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके;	वर्तमान मॉडल: वर्ष 2014 के बाद से, बैंकिंग क्षेत्र ने JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) को अपनाने और भुगतान बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों (SFB) को लाइसेंस जारी करने जैसे कार्यों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

	• बेसल मानदंडों के अनुसार पूंजी आधार को मज़बूत करना	
--	---	--

पांचवीं पीढ़ी के सुधार - आला/विभेदित बैंकिंग को बढ़ावा देना

- आला बैंक विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशिष्ट और विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- ये विशेष बैंक, RAM (Retail, Agriculture, MSMEs) जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य वित्त की पहुँच को आसान बनाएँगे। इसके अलावा, प्रस्तावित DFI/विशिष्ट बैंक को ऐसे प्रमुख बैंकों के रूप में स्थापित किया जा सकता है जिनके पास कम लागत वाले सार्वजनिक जमा और बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन तक पहुँच हो।
- विभेदित बैंकों को भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है और दीर्घकाल में अपने हितधारकों हेतु उन्हें ESG (पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन) फ्रेमवर्क का भी पालन करना चाहिये।
- सरकार को विविधतापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का निर्माण करके, क्षेत्र-वार नियामकों की स्थापना करके, विलफुल डिफॉल्टर्स से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अधिक-से-अधिक शक्तियाँ प्राप्त करने की अनुमति देकर इस क्षेत्र के लचीलेपन को दूर करना चाहिये।

निष्कर्ष

- बढ़ती आबादी की मौजूदा चुनौतियों, चल रही कोविड-19 महामारी और पश्चिम के अपने विनिर्माण आधार को भारत और अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने की मंशा को देखते हुए, पांचवीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों के लिए 'हां' कहना आवश्यक है।

आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुखियों में-

- आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा।
- भारत सरकार (जीओआई) और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी (भारत सरकार 45.48%, एलआईसी 49.24%) है।
- एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह-प्रमोटर है।
- यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कारोबारी क्षमता के इष्टतम विकास के साथ-साथ बैंक के विकास के लिए उसमें आवश्यक धनराशि डालेगा एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करेगा।
- सरकार के रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से संसाधन, लेन-देन से इक्विटी का उपयोग नागरिकों को लाभान्वित करने वाले सरकार के विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

MSME क्षेत्र की वित्त संबंधी समस्याएं

संदर्भ: MSME मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने सकल घरेलू उत्पाद का 30% योगदान दिया

MSMEs भी 100 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है।

वित्त संबंधी क्षेत्र की समस्याएं तीन मुख्य कारकों के कारण होती हैं:

1. व्यवहार्य ऋण प्रदाताओं की अनुपस्थिति
2. क्रेडिट उत्पादों और योजनाओं की अनुपस्थिति जैसे सूक्ष्म बीमा जो उद्यमों को व्यापार मंदी से निपटने में मदद करते हैं
3. विलंबित भुगतान के कारण कार्यशील पूंजी में लगातार कमी हो रही है। उद्यमों को क्रेडिट बिक्री के लिए नकद प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रमशः 176, 112 और 81 दिन लगते हैं।

विलंबित भुगतान में फर्मों के लिए चार प्रकार की लागत आती हैं :

- कर्मियों, समय और प्रयास के रूप में भुगतान प्राप्त करने की लागत;
- निर्धारित अवधि के बाद छोड़ दिया गया ब्याज;
- कार्यशील पूंजी की कमी के कारण व्यवसाय छूट गया;
- समझौता न होने करने के कारण नुकसान।

आगे की राह

- MSME क्षेत्र की श्रम प्रधान प्रकृति को देखते हुए, सरकार को अपनी महामारी के बाद की आर्थिक सुधार रणनीति में इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- इसलिए, सरकार को अपनी वर्तमान MSME योजनाओं में कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें

कनेक्टेड कॉमर्स: डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोडमैप बनाना

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुखियों में-

- नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने 'कनेक्टेड कॉमर्स: डिजिटली इनक्लूसिव भारत के लिए रोडमैप बनाना' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करती है।
- यह अपने 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करती है।

मुख्य सिफारिशें

- रिपोर्ट में NBFC और बैंकों के लिए कार्य क्षेत्र के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है;
 - MSME के विकास के अवसरों को सक्षम करने के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना;
 - 'फ्रॉड रिपॉजिटरी' सहित सूचना-साझाकरण प्रणाली का निर्माण, और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने के लिए चेतावनी देते हैं;
 - कम लागत वाली पूंजी तक पहुँचने के लिए कृषि NBFC को सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक 'भौतिक (भौतिक + डिजिटल) मॉडल' को तैनात करना.
 - न्यूनतम भीड़-भाड़ के साथ शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए, एक समावेशी, इंटरऑपरेबल, और पूरी तरह से खुले सिस्टम जैसे कि लंदन 'ट्यूब' बनाना।
-

एस जानकीरमन द्वारा निर्देशित, सलाहकार समूह नियम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- रिजर्व बैंक ने कहा एक नियामक समूह का गठन दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की सहायता के लिए किया गया है।
- जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा इस महीने की शुरुआत में नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए गठित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **अध्यक्षता:** एसबीआई के प्रबंध निदेशक एस. जानकीरमन।
- समूह उन क्षेत्रों, विनियमों, दिशानिर्देशों, रिटर्न की पहचान करके RRA की सहायता करेगा जिन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सकता है
- यह अनुशंसाओं/सुझावों वाली RRA को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- 1999 में, RBI ने नियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की स्थापना की थी, जो जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिले फीडबैक पर आधारित थी।

राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत रसायन बैटरी (Advanced Chemistry Cell) के आयात को कम करने के लिये इसके निर्माताओं हेतु 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **उद्देश्य:** इस योजना के तहत पचास (50) गीगावॉट ऑवर्स और पांच गीगावॉट ऑवर्स की “उपयुक्त” एसीसीबैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसकी लागत 18,100 करोड़ रुपये है।
- उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell-ACC) नई पीढ़ी की बैटरी है। एसीसी के तहत बिजली को इलेक्ट्रो-कैमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जब जरूरत पड़े, तो इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है।
- यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा देगा, जिससे तिपहिया, चौपहिया और भारी वाहनों को लाभ होगा।
- भारत वर्तमान में बैटरी भंडारण उपकरण आयात कर रहा है।
- यह योजना देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सॉवरेन गोल्ड बांड 17 मई से सितंबर 2021 तक छह चरणों में जारी किए जायेगा।
- बांड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे।
- न्यूनतम अनुमेय निवेश एक ग्राम सोना होगा।
- निवेशकों को नाममात्र मूल्य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय 2.50% प्रति वर्ष की निश्चित दर पर मुआवजा दिया जाएगा।
- बांड निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
- बांड की अवधि 8 वर्ष की अवधि के लिए होगी और 5वें वर्ष के बाद बाहर निकलने का विकल्प अगले ब्याज भुगतान तिथियों पर प्रयोग किया जाएगा।

सार्वजनिक उपक्रम नीति का पुनर्मूल्यांकन

संदर्भ: हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि वह मिशन COVID सुरक्षा के तहत Covaxin के निर्माण हेतु विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिये तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) का उपयोग करेगी। ये थे-

- हाफकाइन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र सरकार के अधीन एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम;
- इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL), हैदराबाद - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत एक सुविधा;
- भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BIBCOL), बुलंदशहर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सीपीएसई।

यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रासंगिकता पर बहस को पुनर्जीवित किया है

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते:** भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी स्थापना के बाद से देश के उच्च विकास और समान सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में उनका निरंतर योगदान वर्तमान परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।
- **परीक्षण के समय में महत्वपूर्ण भूमिका:** इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के कई सार्वजनिक उपक्रमों ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसके परिवहन व सरकार के प्रयासों को पूरा करने में मदद की है।
- **सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों का योगदान:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी अंतर्निहित कार्य संस्कृति के कारण जनशक्ति प्रशिक्षण और विशेषज्ञता विकसित करने में बहुत समय और संसाधन खर्च करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्व कर्मचारियों ने, सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ दी और फिर निजी क्षेत्र में शामिल हो गए, वे उद्योग, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र को सही तरह का प्रोत्साहन दिया है।

फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) का महत्व

- **आत्मनिर्भरता:** देश के लोगों के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों की स्थापना की गई थी
- **मुक्त और निष्पक्ष बाजार:** फार्मा PSE की मजबूत उपस्थिति दवा उद्योग जैसे उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पकड़ से बचाने में मदद करती है।

- **संकट के समय में वहनीयता सुनिश्चित करता है:** महामारी के कारण चीन से आयात का नुकसान हुआ है। इसका सीधा परिणाम भारतीय बाजार में पेरिसिटामोल जैसी रोजमर्रा की दवाओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आया। फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) नीति के विस्तार से इस समय दवाएं सस्ती होंगी।

आगे की राह

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन उनके कामकाज के संदर्भ में - इन संस्थाओं के बोर्डों को सशक्त बनाकर, उन्हें और अधिक स्वायत्त बनाकर।
- इन कंपनियों को बिना सरकारी हस्तक्षेप के एक पेशेवर बोर्ड द्वारा चलाया जाना चाहिये। इन सार्वजनिक उपक्रमों को पीपीपी मॉडल के तहत या संयुक्त उद्यम के रूप में भी चलाया जा सकता है।
- बोर्ड के सदस्यों को अत्यधिक सम्मानित, जानकार और उद्योग, प्रबंधन, वित्त और अनुसंधान क्षेत्रों से होना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- **निजीकरण:** गुण और महत्वपूर्ण विश्लेषण
- बैंकों का निजीकरण

सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- सरकार व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, IGCR 2017 में बदलाव लाया है।
- आईजीसीआर, 2017 के तहत उन प्रक्रियाओं और तरीके को निर्धारित किया जाता है जिसके अनुसार ही कोई आयातक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परिवर्तन प्रस्तावित किए गए।
- हालांकि, कुछ क्षेत्रों जैसे सोना, आभूषण, कीमती पत्थरों और धातुओं को बाहर रखा गया।
- एक और बड़ा बदलाव उन लोगों को अनुमति देता है जो रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करते हैं, उन्हें मूल्यहास मूल्य पर शुल्क और ब्याज के भुगतान पर घरेलू बाजार में उन्हें पुनः बेचने की अनुमति है।
- इसके पहले अनुमति नहीं थी और निर्माता आयातित पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उनके साथ फंस गए थे क्योंकि उन्हें आसानी से पुनः निर्यात नहीं किया जा सकता था।

मोबाइल वॉलेट के माध्यम से ATM से पैसे निकालने की अनुमति

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- अब अमेज़ॅन पे, ओला मनी, मोबिक्विक, फोन पे, दिल्ली मेट्रो कार्ड इत्यादि जैसे विभिन्न ऑनलाइन वॉलेट में रखे गए पैसे को एटीएम या पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल का उपयोग करके पैसा निकाला जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आरबीआई ने प्रति लेनदेन 2,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 10,000 रुपये प्रति माह की नकद निकासी की अनुमति दी है।
- सभी गैर-बैंक भुगतान प्रीपेड साधन यह सेवा प्रदान कर सकते हैं।
- अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में 37 प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की अनुमति दी है।
- पूरा केवाईसी पूरा होने के बाद अधिकतम दो लाख रुपये विभिन्न वॉलेट में रखे जा सकते हैं।
- सभी PPIs को 31 मार्च 2022 तक इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी

अन्य सम्बंधित तथ्य

- PPIs वित्तीय सेवाओं, प्रेषण और ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के खिलाफ फंड ट्रांसफर सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं।
 - ये उपकरण आमतौर पर प्री-लोडेड कार्ड होते हैं।
 - **उदाहरण:** Paytm और GPay (सेमी-क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई), गिफ्ट कार्ड (क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई) और डेबिट या क्रेडिट कार्ड (ओपन सिस्टम पीपीआई)।
-

व्यवसाय का स्थानीयकरण

संदर्भ: जैसा कि वैश्विक व्यवसाय अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' (आत्मनिर्भर भारत) अभियान पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है।

स्थानीयकरण के लिए लाभ

1. ग्राहकों के लिए लाभ:

- स्थानीय रूप से उत्पादित सामान उनके घरेलू बाजारों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होते हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों में विकसित और परीक्षण किया जाता है।
- स्थानीय निर्माण के कारण, ग्राहक (मध्यस्थ या अंतिम उपयोग) तेजी से वितरण की उम्मीद कर सकते हैं।
- कराधान की भिन्न दरों के कारण स्थानीय उत्पाद आयातित वस्तुओं की तुलना में सस्ते होते हैं।

2. कंपनियों को लाभ

- स्थानीय निर्माण में काफी लचीलापन आता है जो लागत दक्षता, गुणवत्ता पर नियंत्रण, उत्पादन, परिवहन, डिलीवरी आदि के मामले में तेजी से टर्न-अराउंड समय की अनुमति देता है।
- स्थानीय स्तर पर विनिर्माण से भारत के उद्योगों को बढ़ने में मदद मिलती है और इसके टैलेंट पूल को विशेष कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
- स्थानीयकरण आगे के अवसरों जैसे निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, और अनुबंध निर्माण के लिए प्रवेश द्वार हो सकता है।

3. देश को लाभ

- भारत में रोजगार योग्य उम्र में युवाओं की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। स्थानीय निर्माण देश के लिए अपने उद्योगों को कार्यबल की आपूर्ति करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- स्थानीयकरण क्षेत्र में जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता करता है।
- स्थानीयकरण अन्य देशों के साथ ज्ञान साझा करने और तकनीकी हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे देश को नवीनतम वैश्विक तकनीकों तक पहुंच भी मिलती है।

- देश को अन्य देशों के लिए खुद को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

- अधिक से अधिक सरकारी समर्थन और उद्योगों के संयुक्त प्रयासों से, भारत निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में स्थानीयकरण के अनेक लाभों को प्राप्त करेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आत्मानिर्भर भारत अभियान
 - क्या आपको लगता है कि आत्मानिर्भर भारत का विजन घरेलू उद्योगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपने विचारों की पुष्टि करें।
-

कॉर्पोरेट ऋण के लिये व्यक्तिगत गारंटर का दायित्व : SC

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऋणदाताओं को निजी गारंटर्स के साथ-साथ तनावग्रस्त कॉर्पोरेट संस्थाओं, जो ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।
- ये व्यक्तिगत गारंटर आमतौर पर बड़े व्यापारिक घरानों के प्रवर्तक होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह माना गया कि 15 नवंबर, 2019, सरकारी अधिसूचना जिसने लेनदारों (आमतौर पर वित्तीय संस्थानों और बैंकों) को भारतीय दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) के तहत व्यक्तिगत गारंटर्स के विरुद्ध जाने की अनुमति दी थी, वह "कानूनी और वैध" थी।
 - सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटर्स के साथ एक ही न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से एक साझा मंच - नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
 - इसके अलावा, IBC कोड की धारा 60 (2) के तहत कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटर की दिवालियापन की कार्यवाही को एक सामान्य मंच यानी NCLT के समक्ष आयोजित करने को अनिवार्य बनाया गया है।
-

बीमा अधिनियम के तहत अधिसूचित नए नियम

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- बीमा अधिनियम के तहत अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, विदेशी भागीदारों के साथ बीमा संयुक्त उद्यमों के भारतीय प्रवर्तक अब बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को नामित नहीं कर पाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए हालिया संशोधनों के बाद नियम लागू होते हैं।
 - यह नया मानदंड सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होगा, भले ही विदेशी भागीदार की हिस्सेदारी कुछ भी हो।
 - उन फर्मों के लिए बोर्ड की संरचना पर आगे की शर्तें भी निर्दिष्ट की गई हैं जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 49% से अधिक है।
-

व्हाइट फंगस

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - स्वास्थ्य; विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- हाल ही में भारत में 'व्हाइट फंगस' या 'कैंडिडिआसिस' के बढ़ते मामलों का पता चला है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है या अगर लोग ऐसी चीजों के संपर्क में आते हैं जिनमें ये संरचना होती है जैसे पानी आदि।
- व्हाइट फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है।
- संक्रमण का क्लिनिकल सीटी-स्कैन या एक्स-रे के माध्यम से किया जाता है।
- यह एक प्रकार का कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है।
- व्हाइट फंगस न केवल फेफड़े बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है जिसमें नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, निजी अंग और मुंह शामिल हैं।
- हालांकि, इसे केवल एक सामान्य फंगल संक्रमण माना जाता है।

संबंधित आलेख

म्यूकोर्मिकोसिस

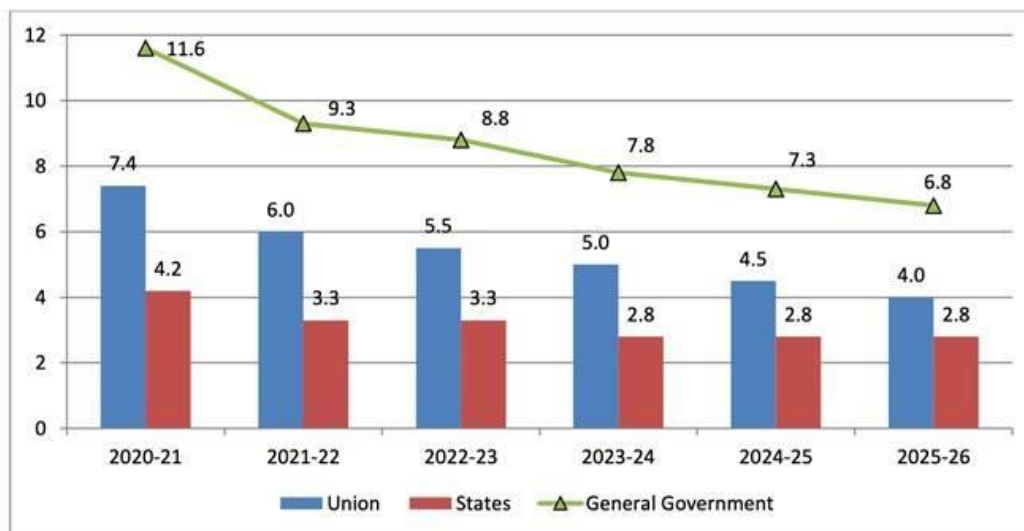
केंद्र और राज्य सरकार के आय पर कोविड -19 का प्रभाव

संदर्भ: यह देखना प्रासंगिक है कि पिछले एक साल में कोविड ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आय पर कैसे प्रभावित किया।

केंद्र की आय

- केंद्र सरकार का राजस्व (कर और गैर-कर दोनों स्रोतों से) तेजी से गिर गया, दूसरी ओर, सरकार ने अपने खर्च को भी बढ़ा दिया।
- इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार का राजस्व घाटा (इसकी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर) के साथ-साथ इसका राजकोषीय घाटा (इसके समग्र उधार का एक उपाय) तेजी से बढ़ रहा है।
- कोविड व्यवधान का मतलब है कि सरकार का राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर) आने वाले कुछ वर्षों के लिए दशा से बाहर हो जाएगा।
- इसलिए, राजकोषीय घाटे में 61% वृद्धि (जैसा कि फरवरी 2020 में बजट पेश करते समय कल्पना की गई थी) राजस्व में गिरावट के कारण था और 39% व्यय में वृद्धि के कारण था।

Figure A1: Fifteenth Finance Commission's Prescribed Glid Path of Fiscal Deficits (% of Nominal GDP)



Source: Figure 1.1, Page No. 10 of XV Finance Commission (2020)

किस प्रकार के राजस्व में गिरावट आई और क्यों?

- नीचे दी गई तालिका-1 यह बताती है कि किस प्रकार के कर राजस्व को कोविड के कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ। हम देख सकते हैं कि उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के थे।
- आय कम होने से खपत भी कम हो जाती है और इस तरह, तीसरी सबसे बड़ी मार खपत पर बढ़ाए गए करों-GST की थी।
- लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूनियन एक्साइज ड्यूटीज (UED) में चलन है, जो एक साल में 35% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें समग्र विकास में 8% की कमी आई है।
- कच्चे पेट्रोलियम की अंतरराष्ट्रीय कम कीमतों ने केंद्र सरकार के लिए उन परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर यूईडी जुटाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो GST को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)।

तालिका 1: उपकरणों और अधिभारों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने प्रवृत्ति को कम किया

राजस्व का प्रकार	FY21 (BE) बनाम FY21 (RE) [% शब्दों में बदलें]
सकल कर राजस्व जिसमें से	- 21.6
निगम कर (CIT)	-34.5
आय पर कर (PIT)	-28.1
कस्टम	-18.8
संघ उत्पाद शुल्क (UED)	35.2
माल और सेवा कर (GST)	-25.4
गैर-कर राजस्व	-45.3

UED में वृद्धि के साथ चिंताएं

- UED संग्रह में इस भारी उछाल से राज्यों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने मूल UED दर को बढ़ाने के बजाय UED पर उपकर और अधिभार बढ़ाकर इसे एकत्र किया।

- उपकर और अधिभार की आय राज्य सरकारों के साथ साझा करने योग्य नहीं है।
- वास्तव में, यदि कोई उपकर और अधिभार हटा देता है, तो पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए UED संग्रह वास्तव में 50% बढ़ने के बजाय 20% गिर जाएगा।
- नीचे दी गई तालिका यह समझने का एक और तरीका प्रदान करती है कि राज्यों को लूप से बाहर रखते हुए उपकरणों और अधिभारों ने केंद्र सरकार की कितनी मदद की।

Table A1: Collection of Union Excise Duties and Annual Growth

Year	Gross Collection (Rs. Crore)			Annual Growth (%)		
	Union Excise Duties (UED) (A)	Cesses under UED (B)	UED - without Cesses (A-B)	Union Excise Duties (UED) (A)	Cesses under UED (B)	UED - without Cesses (A-B)
2018-19	231,044.93	69,137.03	161,907.90			
2019-20	239,452.43	81,505.77	157,946.66	3.64	17.89	-2.45
2020-21RE	361,000.00	233,900.00	127,100.00	50.76	186.97	-19.53

Source: Compiled by authors based on Union Budget Documents (various years)

वित्त वर्ष 2021 में सभी UED संग्रह का 65% उपकर था — पंजीकरण 187% की वार्षिक वृद्धि (सभी डेटा लाल रंग में हाइलाइट किए गए)

राज्य-स्तरीय सरकारी वित्त कोविड से कैसे प्रभावित हुए?

- राज्यों ने राजस्व आघात से निपटने के लिए अपने राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत व्यय को भी नियंत्रित किया। हालांकि, कुल प्राप्तियों में दबाव की भरपाई के लिए व्यय की रोकथाम पर्याप्त नहीं थी।
- परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों (तीन तिमाहियों) में, इन राज्यों ने देखा कि उनका राजस्व घाटा बजट लक्ष्य से लगभग 240% अधिक है और उनका राजकोषीय घाटा 40% से अधिक है।
- कुल मिलाकर, राज्यव्यापी भिन्नताएं थीं - राजस्व और किए गए व्यय दोनों के संदर्भ में (तालिका 3 देखें)

2019 की तुलना में 2020 में वार्षिक वृद्धि (%) (तिमाही 3 तक)	कमी (% में)	बढ़ा हुआ (% में)
कुल प्राप्तियां	हरियाणा (-21%), गुजरात (-19%), कर्नाटक (-18%), महाराष्ट्र (-18%) और पश्चिम बंगाल (-17%), उत्तर प्रदेश (-15%)	आंध्र प्रदेश (10%), पंजाब (18%)
कुल व्यय	हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा	आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरल

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- **उपकर पूल:** GST पर CAG की रिपोर्ट पर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में सुधार, निवेश की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों ने वृद्धि में योगदान दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत के FDI में प्रवृत्तियां हैं:

- वर्ष 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह।
- यह पिछले वर्ष (74.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 10% अधिक है।
- शीर्ष निवेशक देश: सिंगापुर (29%), U.S.A (23%) और मॉरीशस (9%)
- क्षेत्रों में अधिकतम FDI प्राप्त हुआ: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (44%), निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) गतिविधियां (13%) और सेवा क्षेत्र (8%)
- राज्यों में अधिकतम FDI प्राप्त हुआ: गुजरात (37%), महाराष्ट्र (27%) और कर्नाटक (13%)।

संबंधित आलेख

- पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य
 - COVID-19 और FDI नीति
-

शाही लीची

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - ट्रेड; जीआई टैग

सुर्खियों में-

- शाही लीची हाल ही में चर्चा में थी।
- बिहार से शाही लीची की सीजन की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई।
- यह GI प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ा बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2018 में, शाही लीची बिहार से जीआई प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला चौथा कृषि उत्पाद है।
- जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान राज्य के अन्य जीआई प्रमाणित उत्पाद हैं।
- चीन के बाद भारत दुनिया में लीची (Litchi chin) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- शीर्ष निर्माता: बिहार

अन्य सम्बंधित तथ्य

- लीची एक उपोष्णकटिबंधीय फल है।
 - यह नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा फलता-फूलता है।
 - वृद्धि के लिए आदर्श स्थितियां: गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, पीएच 5 से 7 के बीच और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो।
-

भारत की GST के सामने चुनौतियां

संदर्भ: माल और सेवा कर (GST) परिषद की 43 वीं बैठक 28 मई को आयोजित होनी है। जिन 31 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, उनमें से 17 सदस्य सत्तारूढ़ भाजपा या उसके गठबंधन सहयोगियों से हैं और शेष 14 गैर सत्तारूढ़ गठबंधन से हैं।

क्या आपको पता है?

- सत्तारूढ़ दल के 17 सदस्य और GST काउंसिल में गैर-भाजपा सरकार के 14 सदस्य भारत की आबादी के ठीक आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- हालांकि, गैर-भाजपा समूह कुल जीएसटी राजस्व में 60% का अधिक योगदान देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद का 63% हिस्सा है।

मुद्दे

- **GST बैठक नहीं हुई:** GST काउंसिल को हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करने के लिए अनिवार्य किया गया, लेकिन यह महामारी के कारण दो तिमाहियों के लिए नहीं मिला था।
- **बढ़ी निर्भरता:** राज्य अपने कर राजस्व के लगभग आधे हिस्से के लिए GST संग्रह पर निर्भर हैं। हालांकि, आर्थिक मंदी के मद्देनजर राज्यों को मुआवजा स्थिर नहीं है।
- **अतिरिक्त उधार के लिए शर्तें:** पिछले साल केंद्र ने महामारी के बीच में राज्यों को अतिरिक्त उधारी के लिए मंजूरी देने के लिए अचानक और कठोर नीतिगत शर्तें लगाईं।
- **डिफरेंशियल वैक्सिन प्राइसिंग:** इस बात पर विश्वासघात की भावना है कि कैसे राज्यों को केंद्र की तुलना में COVID-19 टीकों के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया गया।
- **उपकर का दुरुपयोग:** राज्य उपकर लगाने में केंद्र के दोहरी चाल से सावधान हैं जो राज्यों के साथ साझा किए बिना केंद्र के लिए महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करते हैं।
- **शुरुआती वादों को पूरा करने में विफलता:** GST भारी आर्थिक दक्षता लाभ प्रदान करने, कर उछाल और संग्रह में सुधार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिककरण की शुरुआत करने के लिए था। हालांकि, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट औपचारिक रूप से स्वीकार करती है कि GST एक आर्थिक विफलता रही है जिसने अपने शुरुआती वादों को पूरा नहीं किया।
- **GST को रेखांकित करने में समस्याएं जारी हैं:** अर्थशास्त्री भारत के जीएसटी को रेखांकित करने वाली समस्याओं के रूप में कई दरों की संरचना, उच्च कर स्लैब और टैक्स फाइलिंग की जटिलता की ओर इशारा करते हैं।
- **2022 के बाद गारंटीकृत राजस्व पर अनिश्चितता:** GST मुख्य रूप से अब तक कायम है क्योंकि राज्यों को हर साल अपने कर राजस्व में 14% की वृद्धि की गारंटी दी गई थी, जिससे इस नए प्रयोग के उनके जोखिम को कम किया गया और वित्तीय संप्रभुता के नुकसान की भरपाई की गई। यह राजस्व गारंटी जुलाई 2022 में समाप्त हो जाती है और राज्यों से 2022 के बाद भी इस मुआवजे की व्यवस्था को जारी रखने की मांग बढ़ रही है।

निष्कर्ष

- 2017 में GST में परिवर्तन को सही ठहराने के लिए 'सहकारी संघवाद' वाक्य को भारत के राजनीतिक शब्दकोष में पेश किया गया।
- सहकारी संघवाद का अर्थ केवल राजकोषीय संघवाद से कहीं बड़ा है। इसमें राज्यों और केंद्र के बीच सहकारी राजनीतिक, प्रशासनिक और शासन संघवाद भी शामिल है।

यह भी पढ़ें

- जीएसटी सुधार के लिए एक नए बड़े सौदे की जरूरत है

- जीएसटी का महत्वपूर्ण कार्य
-

आर्थिक स्लाइड को गिरफ्तार करें

संदर्भ: सीआईआई के अध्यक्ष और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने सरकार से विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों के लिए आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से वित्तीय सहायता का एक और दौर प्रदान करने का आग्रह किया है।

मुद्दे

- **आर्थिक सुधार मुश्किल:** 2021-22 के केंद्रीय बजट के बाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2020-21 में हुए सभी नुकसान की भरपाई करने की उम्मीद थी, जब यह लगभग 8% अनुबंधित था, और इस वित्तीय वर्ष में 12% से अधिक की वृद्धि होगी। लेकिन ये दोनों धारणाएं गलत साबित हुईं। शांतिर दूसरी कोविड लहर के लिए धन्यवाद, अर्थशास्त्री भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमानों को तेजी से डायल कर रहे हैं। यह भी संभव है कि, चालू वित्त वर्ष (मार्च 2022) के अंत में, भारत मार्च 2020 में पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर वापस न आ पाए।
- **गरीबों पर ज्यादा बोझ:** दूसरी लहर के परिणामस्वरूप नौकरियां छूट गईं और लगभग सभी आय वर्गों में मजदूरी कम हो गई, जबकि गरीबों के लिए मामला और भी खराब हो गया।
- **घटी हुई कुल मांग:** कम आय के मद्देनजर, लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खर्चों को सीमित कर दें, विशेष रूप से ऐसी किसी भी चीज पर जिसे वे गैर-जरूरी समझते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आएगी।
- **सरकारों की वसूली की रणनीति खतरे में:** मांग में कमी, बदले में देरी, अगर पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरी, तो सरकार की कोविड वसूली रणनीति की आधारशिला - कॉर्पोरेट भारत से ताजा निवेश।
- **दुष्चक्र:** व्यवसाय निवेश को रोकना जारी रखेंगे क्योंकि उपभोक्ता मांग पर्याप्त नहीं है, और उपभोक्ता अधिक मांग नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त आय नहीं है। और यह दुष्चक्र और भी खराब हो सकता है यदि टीकाकरण की गति नहीं बढ़ती है या यदि कोई घातक तीसरी लहर है।

आगे की राह

- कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण व्यापक तबाही को देखते हुए, यह समय सरकार या कंपनियों के लिए अपनी वित्तीय बैलेंस शीट को देखने का नहीं है।
 - केवल एक आर्थिक इकाई इस चक्र को तोड़ सकती है: सरकार। गरीबों को अतिरिक्त प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता प्रदान करके और छोटे व्यवसायों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का विस्तार करके, सरकार स्लाइड को रोक सकती है।
-

खाद्य तेल की कीमतों में भारी उछाल

भाग-जीएस प्रीलैम्स और जीएस -III – अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल के महीनों में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- छह खाद्य तेलों - मूंगफली तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल और ताड़ के तेल में कीमतों में वृद्धि देखी गई।
- बढ़ती आय और खाने की बदलती आदतों के साथ, खाद्य तेलों की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है।
- कीमतों में वृद्धि का एक मुख्य कारण खाद्य तेलों के उपयोग में खाद्य से जैव ईंधन में बदलाव है।

- **अन्य कारण हैं:** चीन द्वारा अधिक खरीद, मलेशिया में श्रमिक मुद्दे, ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर लानीना (La Nina) का प्रभाव और इंडोनेशिया तथा मलेशिया में कच्चे ताड़ (palm) तेल पर निर्यात शुल्क लगाना।
- कीमतों को तुरंत कम करने के लिए आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए जो बजट के बाद उपकर लगाने के कारण बढ़ गया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- इन आयातों के प्रमुख स्रोत सोयाबीन तेल के लिए अर्जेंटीना और ब्राजील हैं; इंडोनेशिया और मलेशिया ताड़ (palm) तेल; और यूक्रेन और अर्जेंटीना फिर से सूरजमुखी तेल के लिए।
- खाद्य तेल की घरेलू मांग लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) है जबकि भारत केवल 11 मिलियन टन का उत्पादन करता है।
- इस प्रकार, 13 एमटी खाद्य तेलों का आयात किया जाता है।
- जबकि सरसों के तेल की खपत ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है, वहीं रिफाइनड तेल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी शहरी इलाकों में ज्यादा है।

पेटेंट 'ग्राम चावल'

भाग- जीएस प्रील्लिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में, एक स्टार्ट-अप उदय एग्रो फार्म द्वारा कुंभकोणम, तंजावुर जिले, तमिलनाडु से प्राप्त पेटेंट वाले 'ग्राम चावल' को घाना और यमन को निर्यात किया गया।
- प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार के खनिजों से समृद्ध, 'ग्राम चावल' सीधे तंजावुर के किसानों से लिया जाता है, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- मार्च, 2021 में असम से 'लाल चावल' की पहली खेप अमरीका को निर्यात की गई थी।
- लौह युक्त 'लाल चावल' असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के उगाए जाते हैं। चावल की किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है।

संबंधित आलेख

शाही लीची

कटहल

गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन

भाग- जीएस प्रील्लिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में पुराने गोवा गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया।
- **मंत्रालय:** बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- जेट्टी पर्यटकों को सुरक्षित, परेशानी मुक्त परिवहन प्रदान करेगी।
- भारत सरकार ने पुराने गोवा और पणजी को जोड़ने के लिए मोंडोवी नदी (NW-68) पर दो कंक्रीट फ्लोटिंग जेट्टी की स्थापना को मंजूरी दी है।

- ये मोंडोवी नदी (NW-68) पर बनी दूसरी तैरती हुई जेटी है।
- कैप्टन ऑफ पोर्ट्स पणजी में स्थित पहली जेटी का उद्घाटन भी 21 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने किया था।

अन्य सम्बंधित तथ्य

कंक्रीट की अस्थायी घाटियों के स्थिर घाटों की तुलना में कई लाभ हैं

- उनकी कीमत एक निश्चित घाट की कीमत का लगभग 1/5 है।
- इसी तरह, वे बनाने और स्थापित करने में तेज होते हैं, और उपयोग में आसान होते हैं।
- फ्लोटिंग जेटी का डिजाइन किया गया जीवन 50 वर्ष तक है।
- इसके अलावा, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण उन्हें CRZ क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन या जेटी साइट के हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल में परिवर्तन के अनुसार उन्हें आकार में बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

कृषि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना' (PLISFPI) के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।
- **उद्देश्य:** भारत के प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैपियनों के निर्माण का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना।
- **श्रेणी-I:** इस श्रेणी के तहत आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं और एक सामान्य आवेदन के साथ योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **श्रेणी-II:** SMEs आवेदकों नवीन/कार्बनिक उत्पादों का निर्माण जो बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं।
- **श्रेणी-III:** विदेशों में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक।

कृषि सहयोग पर भारत-इजरायल समझौता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - अंतराष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- भारत और इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए तीन वर्षीय कार्य कार्यक्रम (2021-23) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत और इजरायल दोनों 'भारत-इजरायल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र' और 'भारत-इजरायल उत्कृष्टता गाँव' (IIVOE) को लागू कर रहे हैं।

- यह 5वीं भारत-इजरायल कृषि कार्य योजना (IIAP) है।
 - **उद्देश्य:** मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, CoE's की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
 - "इंडो-इजराइल विलेज ऑफ़ एक्सीलेंस" एक नई अवधारणा है
 - **उद्देश्य:** 75 गांवों के भीतर 13 उत्कृष्टता केंद्रों के साथ-साथ आठ राज्यों में कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
 - **फोकस:** (1) आधुनिक कृषि अवसंरचना, (2) क्षमता निर्माण, (3) बाजार से जुड़ाव।
-

सुर्खियों में फसल: कटहल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था; व्यापार; कृषि

सुर्खियों में-

- ताजा कटहल की खेप त्रिपुरा से लंदन निर्यात की गई।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कटहल अंजीर, शहतूत और ब्रेडफ्रूट फैमली (मोरेसी) में पेड़ की एक प्रजाति है।
- यह एक बहुभागी फल है, जो सैकड़ों से हजारों अलग-अलग फूलों और मोठे गुदगुदे पंखुड़ियों से बना होता है।
- **वैज्ञानिक नाम:** आर्टोकार्पस हेटरोफिलस।
- **विश्व में प्रमुख उत्पादक देश :** भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और नेपाल।
- **भारत के प्रमुख उत्पादन राज्य:** केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम।
- केरल विश्व में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह केरल और तमिलनाडु का राज्य फल है।

क्या आप जानते हैं?

- हाल ही में, 'लाल चावल' की पहली खेप असम से यूएसए भेजी गई।
- लौह युक्त 'लाल चावल' असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के उगाए जाते हैं।
- चावल की किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है।

संबंधित आलेख

शाही लीची

डेयरी क्षेत्र पर संकट

डेयरी क्षेत्र का महत्व

- **आजीविका:** खेत पर निर्भर आबादी में वैसे किसान और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं जो डेयरी और पशुधन पर निर्भर हैं। इनकी संख्या लगभग 70 मिलियन है।
- **महिला सशक्तिकरण:** इसके अलावा मवेशी और भैंस पालन में कुल कार्यबल 7.7 मिलियन में 69 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। जो देश में कुल महिला कार्यबल का 5.72 प्रतिशत है, जिसमें से 93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- **आर्थिक विकास:** कृषि से सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में पशुधन क्षेत्र का योगदान 2019-20 में 28 प्रतिशत का योगदान दिया।
- **सुरक्षा कवच प्रदान करता है:** दुग्ध उत्पादन में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर से किसानों को सूखे और बाढ़ के दौरान एक बड़ा आर्थिक सहारा प्राप्त होता है।

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर दूध का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि किसान तब पशुपालन पर अधिक निर्भर होते हैं।

मुद्दे

1. **उच्च संवेदनशीलता:** दुग्ध उत्पादक मामूली झटके के लिए भी अतिसंवेदनशील होते हैं क्योंकि दूध और दूध उत्पादों की मांग उपभोक्ताओं के रोजगार और आय में बदलाव के प्रति संवेदनशील होती है।
2. **राजनीतिक दबदबे का अभाव:** गन्ना, गेहूं और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत पशुपालक असंगठित हैं और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिये राजनीतिक ताकत नहीं है।
3. **कोई MSP नहीं:** हालांकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है लेकिन उत्पादन की लागत और दूध के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
4. **सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली कम कीमतें:** भले ही डेयरी सहकारी समितियाँ देश में दूध के कुल विपणन योग्य अधिशेष में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करती हैं, लेकिन वे भूमिहीन या छोटे किसानों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा खरीदा गया 75 प्रतिशत से अधिक दूध अपने न्यूनतम मूल्य पर है।
5. **जनशक्ति की कमी:** अगस्त 2020 में विभाग ने भारत में 2.02 लाख कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination- AI) तकनीशियनों की आवश्यकता की सूचना दी, जबकि उपलब्धता केवल 1.16 लाख है।
6. **ऋणों का धीमा वितरण:** भारत में 230 दुग्ध संघों के कुल 1.5 करोड़ किसानों में से अक्टूबर 2020 तक डेयरी किसानों के ऋण आवेदनों का एक-चौथाई भी बैंकों को नहीं भेजा गया था।
7. **सरकार द्वारा अपर्याप्त उपाय:** किसानों को कोविड-19 के कारण आय के नुकसान की भरपाई के लिये डेयरी को मनरेगा के तहत लाया गया था। हालाँकि 2021-22 के लिये बजटीय आवंटन में 34.5 प्रतिशत की कटौती की गई थी।

8. COVID-19 प्रभाव

- **बढ़ी हुई लागत और कम मांग:** दुकानों के बंद होने से दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग में कमी आई है, जबकि चारे और पशुओं के भोजन की भारी कमी ने इनपुट लागत को बढ़ा दिया।
- **कम खरीदार:** महामारी के दौरान, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों द्वारा दूध की घर-घर बिक्री पर स्व-प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे किसानों को पूरी उपज डेयरी सहकारी समितियों को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **पशु चिकित्सा देखभाल की कमी :** इसके अलावा, कोविड -19 के कारण निजी पशु चिकित्सा सेवाएं लगभग बंद हो गईं, जिसके कारण दुधारे पशुओं की मृत्यु हो गई।

आगे की राह

- डेयरी किसानों को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
- पहला, दूध के लिए एक स्टेबल बाजार और लाभकारी मूल्य (वसा की मात्रा को नजरअंदाज करना या दूध की मात्रा को अधिक महत्व देना);
- दूसरा, उचित मूल्य पर चारे और पशुओं के भोजन की निर्बाध आपूर्ति; तथा
- तीसरा, पशु चिकित्सा सेवाओं और दवाओं की नियमित आपूर्ति।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महिला और डेयरी सहकारिता
- भारत के डेयरी क्षेत्र पर RCEP का प्रभाव
- भारत अपनी डेयरी कार्ट को कैसे आगे बढ़ा सकता है

पर्यावरण/प्रदूषण

समाचारों में प्रजातियां: ज़ाइलोफिस दीपकी" (Xylophis Deepaki)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता

सुर्खियों में-

- एक छोटे साँप की प्रजाति "ज़ाइलोफिस दीपकी" (Xylophis Deepaki) का नामकरण एक भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के नाम पर किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2021 के पहले चार महीनों में, पश्चिमी घाट ने नई तितलियाँ, मेंढक, फ्रूट मक्खियाँ और यहाँ तक कि मीठे पानी का केकड़ा भी दिखाये दिए।
- ज़ाइलोफिस दीपाकी इंद्रधनुष की तरह चमकीली शल्क वाला मात्र 20 सेमी. लंबाई का एक छोटा साँप है।
- इसे पहली बार कन्याकुमारी में एक नारियल के बागान में देखा गया था।

- इस प्रजाति का नाम भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने जाइलोफिस की नई उपप्रजाति खोजने तथा लकड़ी के साँप को पालने के लिए जाने जाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- ये गैर-विषैले होते हैं, जिन्हें अक्सर पश्चिमी घाट के जंगलों में और खेतों में मिट्टी की खुदाई करते समय देखा जाता है। इनका प्रमुख भोजन केंचुए और अन्य अकशेरुकीय जीव होते हैं।
- इनके निकट संबंधी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं जो आर्बोरियल (Arboreal- पेड़ों में रहने वाले) वर्ग के होते हैं।

जलवायु परिवर्तन कारकों से पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन

संदर्भ: बढ़ते समुद्र के स्तर, गर्मी की लहरें, पिघलते ग्लेशियर और तूफान जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रसिद्ध परिणाम हैं। नए शोध ने इस सूची में एक और प्रभाव जुड़ा है - धुरी में चिह्नित बदलाव जिसके साथ पृथ्वी घूमती है।

पृथ्वी की धुरी कैसे बदलती है?

- पृथ्वी के घूमने की धुरी वह रेखा है जिसके साथ यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने चारों ओर घूमती है। जिन बिंदुओं पर धुरी ग्रह की सतह को काटती है वे भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं।
- ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है, हालांकि, ग्रह के चारों ओर पृथ्वी के द्रव्यमान को कैसे वितरित किया जाता है, इसमें परिवर्तन के कारण धुरी चलती है। इस प्रकार, जब धुरी चलती है तो ध्रुव चलते हैं, और दोलन को "ध्रुवीय गति" कहा जाता है।
- नासा के अनुसार, 20वीं सदी के आंकड़ों से पता चलता है कि चक्रीय -अक्ष प्रति वर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर खिसकती है। अर्थात् एक सदी से भी अधिक समय में, ध्रुवीय गति 10 मीटर से अधिक हो जाती है।
- सामान्यतः ध्रुवीय गति जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस पृथ्वी में परिवर्तन के कारण होती है। लेकिन अब, जलवायु परिवर्तन उस स्थितिको जोड़ रहा है जिसके साथ ध्रुव घूम रहे हैं।

नया अध्ययन क्या कहता है?

- 1990 के दशक से, जलवायु परिवर्तन के कारण अरबों टन हिमनद बर्फ महासागरों में पिघल गई है। इससे पृथ्वी के ध्रुव नई दिशाओं में घूमने लगे हैं।
- अध्ययन के अनुसार, जलमंडल में परिवर्तन (अर्थात् जिस तरह से पृथ्वी पर पानी जमा होता है) के कारण 1990 के दशक से उत्तरी ध्रुव एक नई पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो गया है।
- 1995 से 2020 तक, बहाव की औसत गति 1981 से 1995 की तुलना में 17 गुना तेज थी। साथ ही, पिछले चार दशकों में, ध्रुव लगभग 4 मीटर की दूरी पर चले गए।
- जहां ध्रुवीय गति में वृद्धि के पीछे बर्फ का पिघलना प्रमुख कारक है, वहीं भूजल की कमी भी इस घटना में जोड़ती है। चूंकि भूमि के नीचे से लाखों टन पानी हर साल पीने, उद्योग या कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, इसका अधिकांश हिस्सा अंततः समुद्र में मिल जाता है, इस प्रकार ग्रह के द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस जलवायु समझौता
- कार्बन तटस्थता

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

संदर्भ: नीतिगत वॉक्स, जलवायु वार्ताकारों, शिक्षाविदों, कॉरपोरेट्स और गैर सरकारी संगठनों को वर्तमान में "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन" की अवधारणा और इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य वर्ष पर तय किया गया।

प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है?

- वृद्धि से ऐसी प्रतिकूलताएं (चुनौतियां) उत्पन्न नहीं होंगी जो कोयला खदानों को बंद करने के विकल्प के कारण हो सकती हैं।
- इससे उद्योगों को अपने सिस्टम की रेट्रोफिटिंग में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी
- यह सरकार को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति देगा।
- इसके अलावा, इसे कार्यकारी अध्यादेश के माध्यम से और विधायी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना प्राप्त किया जा सकता है।

भारत की ऊर्जा यात्रा में प्राकृतिक गैस को "अगले पड़ाव" बनाने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है?

1. अधिकारियों को प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता देनी चाहिए

- सरकार को इसकी क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानना चाहिए।
- प्राकृतिक गैस प्रतिस्पर्धी ईंधन है; एशियाई/ME उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध; सभी जीवाश्म ईंधनों के बहु उपयोग और "हरिततम"।

2. अधिकारियों को मौजूदा प्रोत्साहन नीति विकृतियों को सही करना चाहिए

- प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण कठिन है। कई मूल्य सूत्र हैं-एक PSUs द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित गैस के लिए, एक निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस के लिए, एक गहरे पानी से उत्पादन के लिए आदि।
- कराधान भी तुलनात्मक रूप से प्रतिगामी है - कैस्केडिंग संरचना - गैस के स्रोत से दूरी पर स्थित ग्राहक स्रोत के करीब की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं।

3. अधिकारियों को उद्योग की संरचना में सुधार करना चाहिए

- वर्तमान में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL) गैस के उत्पादन, परिवहन और विपणन में लगा हुआ है।
- यह प्रभुत्व GAIL को अपने प्रतिस्पर्धियों को बाजार तक पहुंच से वंचित करने के लिए अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क का दुरुपयोग करने की अनुमति देता है।
- अधिकांश देशों ने अपस्ट्रीम (उत्पादन/आयात) और डाउनस्ट्रीम (मार्केटिंग) हितों को परिवहन से अलग करके हितों के टकराव की इस स्थिति से निपटारा किया है।

4. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को सक्षम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए

- केंद्र-राज्य मतभेदों ने आयात सुविधाओं के निर्माण और गैस बाजारों के निर्माण में देरी की है।
- इन मुद्दों को राजनीतिक पटल से हटाने और एक एकीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया के ढांचे के भीतर लाने के लिए एक रास्ता खोजना होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस जलवायु समझौता
-

जलवायु संकट के लिए कोविड-19 महामारी से सबक

संदर्भ: सदी में एक बार होने वाली, कोविड -19 महामारी एक काला हंस, भारी स्वास्थ्य प्रणाली, प्रशासनिक क्षमता और सामुदायिक लचीलापन थी।

महामारी चार सबक प्रदान करती है जो बता सकती है कि हम जलवायु संकट के लिए कैसे तैयारी करते हैं

- 1. ग्रहों के खतरे राजनीतिक सीमाएं नहीं रोक सकती :** वायरस की उत्पत्ति भले ही चीन में हुई हो, लेकिन कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। जलवायु खतरे अलग नहीं हैं।
- 2. लहरों में झटके आते हैं :** महामारी की तरह जलवायु के झटके एक बार में नहीं, बल्कि लहरों में आते हैं। समय के साथ जलवायु संकट की संभावना बढ़ जाती है। लगातार तीन या चार साल तक बारिश सामान्य से कम रहने पर एक साल में मानसून की विफलता को दर्शाता है।
- 3. कुछ अन्य की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं:** दैनिक वेतन भोगी, प्रवासी श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक और सह-रुग्णता वाले लोग महामारी के दौरान सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं। इसी तरह किसी भी उचित मौसम की घटनाओं/जलवायु संकट के साथ भेद्यता होगी।
- 4. आर्थिक भेद्यता:** आपकी अर्थव्यवस्था जितनी अधिक गतिशील होगी, आपको उतना ही अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा: आर्थिक गतिविधि को बहाल करने की आवश्यकता की मांग है कि महामारी के बाद के झटकों का जवाब देने के लिए भी तत्परता हो। जोखिमों को नजरअंदाज करना आर्थिक सुधार को खतरे में डाल सकता है। इसी तरह, जलवायु संकट दुनिया के विकास के इंजनों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

इन अध्यायों को कार्रवाई में अनुवाद करना चाहिए

1. सबसे पहले, एक जलवायु जोखिम आयोग बनाएं

- आयोग समय-समय पर जलवायु खतरों का विश्लेषण और रिपोर्ट करने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण होगा।
- वित्त आयोग की तरह, इसे न केवल जलवायु विशेषज्ञों से बल्कि राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग, मीडिया और नागरिक समाज से भी परामर्श करना चाहिए।
- आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए।

2. विकेंद्रीकृत क्षमता के साथ जलवायु झटकों के लिए तैयार रहें

- राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां एक शुरुआत हैं। जिला स्तर पर इसी तरह के ढांचे की जरूरत है।
- विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचे, वितरित बिजली स्रोतों से, वितरित जल भंडारण, संशोधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ऑफ-ग्रिड पावर का उपयोग करके), या तटीय बाढ़ को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान समुदाय के लचीलेपन को बहुत बढ़ा सकते हैं।

3. कठिन बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण कमजोरियों का आकलन करें

- यह बिजली संयंत्रों, पुलों, हवाई अड्डों, या दूरसंचार बुनियादी ढांचे को होने वाले भौतिक नुकसान को कम करने तक सीमित नहीं है। भारत को वित्तीय खतरों को समझना चाहिए।
- आरबीआई को बैंकों के ऋण संविभागों में जलवायु खतरों की नियमित रिपोर्टिंग की मांग करनी चाहिए। सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों से इसे अनिवार्य करना चाहिए।
- कोयले में पुराने निवेश, प्राकृतिक गैस में चल रहे निवेश, और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला खतरों का आकलन करने की आवश्यकता है।

4. भारत को एक पुनर्गठित अर्थव्यवस्था की जरूरत है

- पुनर्गठित अर्थव्यवस्था मूल्यों और प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण का मुद्राकरण करती है, उन क्षेत्रों में निवेश करती है जो निम्न-कार्बन और रोजगार-गहन दोनों हैं।

- यह नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है (बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, पुनर्योजी कृषि, टिकाऊ माल और परिवहन और अन्य के बीच)।

निष्कर्ष

अगर हम इसके सबक पर ध्यान नहीं देंगे तो महामारी की त्रासदी और बढ़ जाएगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस जलवायु समझौता
-

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिये नीति आयोग की परियोजना

भाग- जीएस प्रीलिमिन्स और जीएस - III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- हाल ही में एक पर्यावरण मूल्यांकन समिति (EAC) - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के बुनियादी ढांचे, जिसने ग्रेट निकोबार द्वीप से संबंधित नीति आयोग की महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हालांकि, समिति ने परियोजना के सामने आने वाली पहली बाधा को दूर कर दिया है।
- इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययनों के लिए इसे "संदर्भ की शर्तों (TOR)" के लिए "अनुशंसित" किया है, जिसमें पहली बार तीन महीनों में आधारभूत अध्ययन शामिल होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

गैलाथिया की खाड़ी

- गैलाथिया की खाड़ी बंदरगाह का स्थल है और जो नीति आयोग के प्रस्ताव का केंद्रबिंदु है।
 - गैलाथिया की खाड़ी, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए 'एंजीमेटिक जिआंट टर्टल' का 'नेस्टिंग' स्थल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है।
 - पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिक सर्वेक्षणों ने ऐसी कई नई प्रजातियों की सूचना दी है, जो केवल गैलाथिया क्षेत्र तक सीमित हैं।
 - इनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय निकोबार छछूंदर (Nicobar Shrew), ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार मेंढक, निकोबार कैट स्नेक (Nicobar Cat Snake), एक नया स्किंक (Lipinia Sp), एक नई छिपकली (Dibamus Sp) और लाइकोडोन एसपी (Lycodon Sp) का एक साँप शामिल है।
-

जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे पुराने रॉक पेंटिंग का अपक्षय

भाग- जीएस प्रीलिमिन्स और जीएस- III - पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन

सुर्खियों में-

- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण क्षरण विश्व की मानव विरासत के सबसे पुराने और सबसे कीमती टुकड़ों में से एक को खत्म रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 45,000-20,000 साल पहले की प्लेइस्टोसिन-युग की रॉक पेंटिंग एक खतरनाक दर से अपक्षय कर रही हैं।
- **स्थान:** मारोस-पैंगकेप क्षेत्र में गुफा स्थल, दक्षिणी सुलावेसी, इंडोनेशिया

- कलाकृति में वह शामिल है जिसे माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना हाथ का स्टैंसिल है जिसे एक गुफा की दीवार पर हाथ दबाकर बनाया गया है, और उस पर गीले लाल-शहतूत के रंग का छिड़काव किया गया है।
 - 45,500 साल पहले पास की एक गुफा में दीवार पर चित्रित एक जानवर, एक मस्से वाला सुअर का दुनिया का सबसे पुराना चित्रण है।
 - सुलावेसी की गुफा कला यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा कला से काफी पुरानी है।
-

A-76: विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- स्पेन के मालोर्का द्वीप से भी बड़ा बर्फ का एक विशाल हिमखंड/हिमशैल अंटार्कटिका के जमे हुए किनारे से टूट कर वेडेल सागर में गिर गया है।
- अब यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वैज्ञानिकों द्वारा हिमखंड को A-76 नामित किया गया।
- A-76 अंटार्कटिका के रॉन आइस शेल्फ (Ronne Ice Shelf) से अलग हो गया।
- इसे कॉपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा ली गई हाल की उपग्रह छवियों में देखा गया।

क्या आप जानते हैं?

- यह अब दूसरे स्थान पर मौजूद A-23A हिमखंड को पार कर गया जो वेडेल सागर में भी तैर रहा है।
 - स्पेन का लोकप्रिय पर्यटन द्वीप मालोर्का भूमध्य सागर में स्थित है।
 - वेडेल सागर दक्षिणी महासागर का हिस्सा है और इसमें वेडेल गायरे शामिल हैं।
 - इसकी भूमि की सीमाएं कोट्स लैंड और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटों से बनी खाड़ी द्वारा परिभाषित की गई हैं।
-

सभी आक्रामक सफेद मक्खियों की सीमा बढ़ रही है

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि सभी आक्रामक सफेद मक्खियों की मेजबान सीमा उनके बहुभक्षी प्रकृति (विभिन्न प्रकार का भोजन करने की क्षमता) और अनुकूल प्रजनन के कारण बढ़ रही है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- सफेद मक्खियाँ हेमीप्टेरान होती हैं जो आमतौर पर पौधों की पत्तियों के नीचे के हिस्से पर भोजन करती हैं।
- इनमें एलेरोडिडे परिवार शामिल है, जो सुपरफैमिली एलेरोडोइडिया में एकमात्र परिवार है।
- गर्म या उष्णकटिबंधीय जलवायु और विशेष रूप से ग्रीनहाउस में, सफेद मक्खियाँ फसल सुरक्षा में प्रमुख समस्याएं उत्पन्न करती हैं।
- इसके अलावा, Bt. कपास सफेद मक्खियों के प्रति प्रतिरोधी नहीं है।

- वे नारियल, केला, आम, चीकू, अमरूद, काजू, ताड़ के तेल और सजावटी पौधों तथा महत्वपूर्ण औषधीय पौधों जैसे मूल्यवान पौधों की प्रजातियों पर अपनी मेजबान सीमा का विस्तार करने के लिए भी पाए गए।
- सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करके सफेद मक्खियों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है।
- वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीट परभक्षी, पैरासिटोइड्स और एंटोमोपैथोजेनिक कवक (कवक जो इनसेट को मार सकते हैं) का उपयोग किया जा रहा है।

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) का निर्माण

भाग- जीएस प्रीलिमिन्स और जीएस-II- राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- लक्षद्वीप के लोग नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) के निर्माण से नाराजगी व्यक्त की गई है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- श्री पटेल प्रशासक के रूप में पहली राजनीतिक नियुक्ति हैं, यह पद ज्यादातर सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के पास है।
- द्वीपवासियों ने बताया है कि यह कानून द्वीपसमूह की सामाजिक और पर्यावरणीय वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है।
- व्यापक शक्तियों के साथ लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) के निर्माण में भूमि मालिकों को बेदखल करना शामिल है।
- इसे व्यापक रूप से रियल एस्टेट लॉबी द्वारा और द्वीपवासियों के हितों के खिलाफ ज़ोर देने के रूप में देखा जाता है।
- सैकड़ों द्वीपवासियों ने प्रशासक को पत्र लिखकर प्रस्तावित विनियम को वापस लेने की मांग की।
- इसमें प्रावधान शामिल हैं जैसे:
 1. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूमि का व्यवस्थित और प्रगतिशील विकास और उसकी सुविधाओं का संरक्षण और सुधार करना;
 2. भूमि के विकास की अनुमति देना और भूमि के उपयोग पर नियंत्रण की अन्य शक्तियाँ प्रदान करना;
 3. योजना के लिए भूमि के अधिग्रहण और विकास के संबंध में अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करना।

संबंधित आलेख

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग का 'सतत' दृष्टिकोण

हैबिटेट गिल्ड्स ने भूमि-उपयोग परिवर्तन का अनुभव किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- एक नए अध्ययन में उत्तराखंड में सभी संशोधित परिदृश्यों में पक्षियों की प्रजातियों के भारी नुकसान का उल्लेख किया गया है।
- प्राकृतिक ओक बहुल वनों और संशोधित वनों का विश्लेषण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उत्तराखंड पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण वनों का घर है जो बड़ी संख्या में स्थानिक पक्षी प्रजातियों को आश्रय देते हैं।
- छह प्रमुख भूमि-उपयोग के प्रकारों का अध्ययन किया गया जिसमें प्राकृतिक ओक वन, निम्नीकृत ओक वन (हल्के से उपयोग किए जाने वाले), लोण्ड ओक वन (गहन रूप से उपयोग किए जाने वाले), देवदार के जंगल, कृषि खेती क्षेत्र और इमारतों वाले स्थलों का अध्ययन किया गया।
- परिणामों से पता चला कि मोनोकल्चर क्षेत्रों और शहरी स्थलों में प्रजातियों की विविधता कम थी।
- इसने उन क्षेत्रों में कुछ आवास संघों में भी भारी गिरावट देखी, जिन्होंने भूमि-उपयोग परिवर्तन का अनुभव किया।
- हैबिटेट गिल्ड पक्षी प्रजातियों के समूह हैं जिनकी आवास प्राथमिकताएं समान हैं।

समाचारों में एम्स / नेशनल पार्क्स

एशियाई शेरों का हैदराबाद चिड़ियाघर में SARS-CoV2 वायरस के लिए परीक्षण पॉजिटिव

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; विज्ञान और तकनीक; संरक्षण

सुर्खियों में-

- CCMB-LaCONES की रिपोर्ट के आधार पर, अब यह पुष्टि हो गई है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क (NZP) में 8 एशियाई शेर SARS-CoV2 वायरस से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए लैकोन्स या प्रयोगशाला, हैदराबाद में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला है।
- यह CCMB (सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र) का एक हिस्सा है।
- इसकी परिकल्पना लालजी सिंह ने की थी।
- यह भारत की एकमात्र अनुसंधान सुविधा है जो वन्यजीवों और उसके संसाधनों के संरक्षण में लगी हुई है।
- यह 2007 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

एशियाई शेर

- यह भारत में एक पैंथेरा लियो आबादी है।
- इसकी वर्तमान सीमा भारतीय राज्य गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और परिवेश तक सीमित है।
- यह भारत में रहने वाली पांच तेंदुआ बिल्लियों में से एक है। तथा अन्य हैं:
 - बंगाल टाइगर
 - भारतीय तेंदुआ
 - हिम तेंदुआ
 - क्लाउडेड लेपर्ड
- इसे "भारतीय शेर" और "फारसी शेर" के रूप में भी जाना जाता है।

स्थिति:

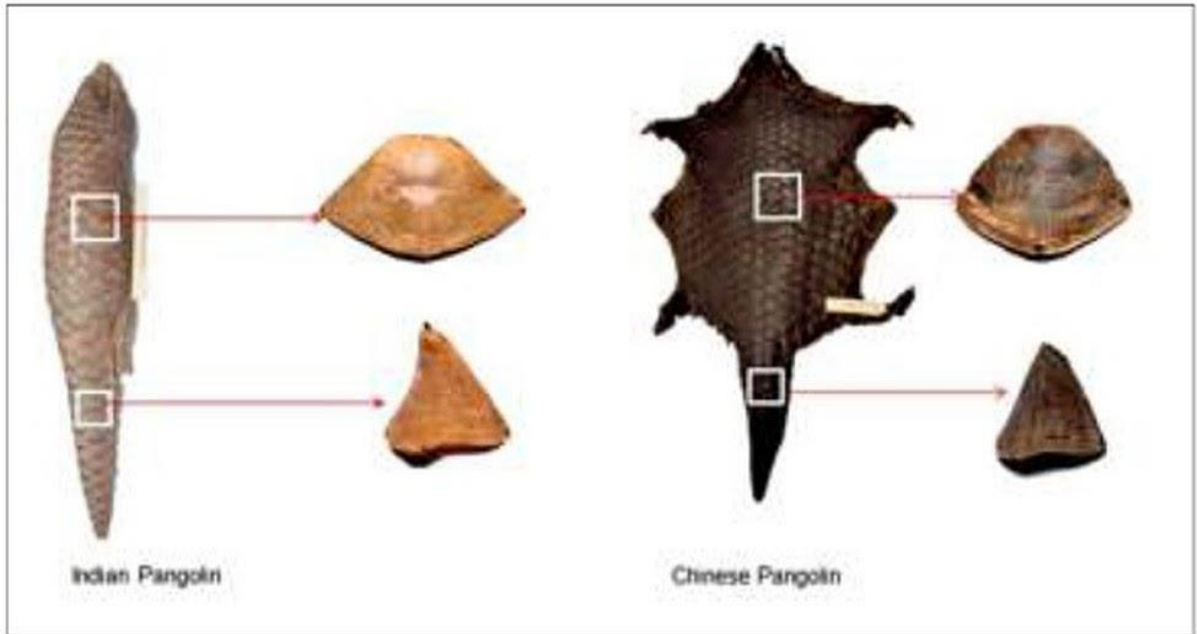
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध
 - CITES का परिशिष्ट I
 - IUCN रेड लिस्ट पर संकटग्रस्त।
 - यह अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा है।
 - सबसे आकर्षक रूपात्मक चरित्र एशियाई शेरों के पेट के साथ चलने वाली त्वचा की एक अनुदैर्घ्य तह है।
-

भारतीय शोधकर्ताओं ने पैंगोलिन शल्क का अनुक्रम किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- भारतीय शोधकर्ताओं ने 624 पैंगोलिन शल्क को अनुक्रमित किया है, जिससे भारतीय और चीनी पैंगोलिन को वर्गीकृत किया गया है।



Developing protocols: Indian and Chinese pangolins are both endangered, therefore, it is important to identify species and the number poached. ■ FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL

महत्वपूर्ण तथ्य

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध होने के बावजूद पैंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपायी बना हुआ है।
- पारंपरिक पूर्वी एशियाई दवाओं के निर्माण में इसके शल्क (स्केल) की प्राथमिक मांग के कारण हर साल अनुमानित रूप से \$2.5 बिलियन का अवैध व्यापार होता है।
- उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने और प्रजातियों की गिरावट को ट्रैक करने के लिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), कोलकाता के शोधकर्ताओं ने अब भारतीय पैंगोलिन (मैनिस् क्रैसिकौडाटा) और चीनी पैंगोलिन (मैनिस् पेंटाडैक्टाइल) के शल्क (स्केल) को अलग करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं।
- हालांकि चीनी पैंगोलिन ज्यादातर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया में वितरित किया जाता है, भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा भी इसका घर है।

रेलवे लाइन पर हाथी हताहत

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस- III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, 2009-10 और 2020-21 के बीच संपूर्ण भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हो गई।

- रेलवे ट्रैक (62) पर हाथियों के हताहत होने की सबसे अधिक संख्या असम में है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (57) और ओडिशा (27) का स्थान है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मौत देखी गई।

रेलवे लाइन पर हाथियों के हताहत होने से बचने के उपाय

- रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और MoEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया।
- लोको पायलटों के लिए स्पष्ट दृश्य को सक्षम करने के लिए रेलवे पटरियों के साथ वनस्पति साफ़ करना।

संबंधित आलेख

केरल में हथिनी की हत्या पर

प्रोजेक्ट Re-HAB का शुभारंभ

समाचारों में प्रजातियां: रेड-ईयर स्लाइडर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता

सुर्खियों में-

- पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला एक पालतू अमेरिकी कछुआ समूचे क्षेत्र के जल निकायों को नष्ट कर रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र देश में पाए जाने वाले ताजे जल के कछुओं (Turtles and tortoises) की 29 में से 21 संवेदनशील स्थानिक प्रजातियों का निवास स्थल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अगस्त 2018 और जून 2019 के बीच, 'हेल्प अर्थ' नामक NGO के सरीसृप विज्ञानियों के दल ने असम के गुवाहाटी स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य तथा उग्रतारा मंदिर के जलाशय में इस कछुए की उपस्थिति का पता लगाया था।
 - इस कछुए को 'रेड-ईअर्ड स्लाइडर' इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसके सिर में कानों के स्थान पर लाल रंग की पट्टी बनी होती है और यह किसी भी सतह से जल में बहुत तेजी से सरकता है। इसका वैज्ञानिक नाम 'ट्रेकेमिस स्क्रिप्टा एलिगन्स' (Trachemys scripta elegans) है।
 - यह यू.एस. और उत्तरी मेक्सिको का मूल निवासी है।
 - यह कछुआ बेहद लोकप्रिय पालतू जीव है।
 - यह बहुत जल्दी बड़ा होता है और जिस भी स्थान पर रहता है, वहाँ अन्य स्थानिक प्रजातियों के भोजन के लिये कुछ भी नहीं छोड़ता।
 - यह पहले ही कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों को प्रभावित कर चुका है, जहां यह 33 प्राकृतिक जल निकायों में पाया गया है।
 - इस आक्रामक प्रजाति को पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र और अन्य नदी पारिस्थितिक तंत्र से आगे निकलने से रोकना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर देश में कछुओं की 72% से अधिक प्रजातियों का घर है, ये सभी बहुत दुर्लभ हैं।
-

समाचारों में प्रजातियां: सबडॉलूसेप्स नीलगिरिऐन्सिस

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट से एक एशियाई ग्रेसिल स्किंक प्रजाति की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसका नाम सबडॉलूसेप्स नीलगिरिएन्सिस है।
- इसका पतला शरीर (7 सेमी) है।
- यह रेतीले भूरे रंग का होता है।
- यह पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले सबडॉलूसेप्स प्रुथी से संबंधित है।
- यह प्रजाति, पिछली सहस्राब्दी के दौरान भारत की मुख्य भूमि में खोजी जाने वाली तीसरी स्किंक प्रजाति है।

क्या आप जानते हैं?

- अधिकांश स्किंक दिनचर (diurnal) तथा विषहीन होते हैं।
- वे अक्सर अगोचर अंगों और जमीन पर चलने के तरीके के कारण सांप से मिलते जुलते हैं।
- खतरे: क्षेत्र में मौसमी जंगल की आग, आवास निर्माण और ईंट भट्टा उद्योग।



5G प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम परीक्षण

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को 5G तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आवेदक कंपनियों (TSPs) में भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियोइन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एमटीएनएल शामिल हैं।
- वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिए है।
- प्रत्येक टीएसपी को शहरों के अलावा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी परीक्षण करना होगा ताकि देश भर में 5G टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त हो।
- **उद्देश्य:** विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में 5G स्पेक्ट्रम प्रसार विशेषताओं का परीक्षण; मॉडल ट्यूनिंग और चुने हुए उपकरण और विक्रेताओं का मूल्यांकन; स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परीक्षण; अनुप्रयोगों का परीक्षण; और 5G फोन और उपकरणों का परीक्षण करने के लिए।
- 5जी तकनीक से डेटा डाउनलोड दरों (4जी के 10 गुना होने की उम्मीद), तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता और उद्योग 4.0 को सक्षम करने के लिए अल्ट्रा लो लेटेंसी के मामले में बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने की उम्मीद है।

क्या आप जानते हैं?

5Gi तकनीक

- TSPs को पहले से मौजूद 5जी प्रौद्योगिकी के अलावा 5जीआई प्रौद्योगिकी (5Gi Technology) का उपयोग कर परीक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने भी 5Gi तकनीक को मंजूरी दे दी है क्योंकि यह 5G टावरों और रेडियो नेटवर्क की बहुत बड़ी पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।
- 5Gi तकनीक को IIT मद्रास, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (CEWiT) और IIT हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है।

देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली के निर्माण हेतु मसूरी स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रस्तावित रोपवे पुर्कुल गांव, देहरादून और लाइब्रेरी, मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा एक मोनो-केबल रोपवे है, जिसका निर्माण 285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।
- इसकी वहन क्षमता 1,000 व्यक्ति प्रति घंटे प्रति दिशा होगी।
- इससे देहरादून से मसूरी तक सड़क मार्ग पर यातायात का प्रवाह काफी कम हो जाएगा।
- इससे 350 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
- यह रोपवे “पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगी, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है।
- जिसे 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत, 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के मद्देनजर उठाया गया था।
- "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992" भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए आईटीबीपी के गठन और विनियमन का प्रावधान करता है।

एकजीबिशन/प्रदर्शनी स्थलों और कन्वेंशन/सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा

भाग-जीएस प्रीलिमिंस और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए 'बुनियादी ढांचे' का दर्जा दिया है।
- इस कदम से ऐसी परियोजनाओं के लिए बैंक वित्तपोषण को आसान बनाने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मूल सूची में शामिल किया गया है।
- इसके लिए सोशल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में नया आइटम डाला जाता है।
- टैग से ऐसी परियोजनाओं को बैंकों से आसान वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के MICE गंतव्य जिसमें मीटिंग (Meetings), इंसेंटिव (Incentive), कॉन्फ्रेंस (Conference) और एकजीबिशन (Exhibition) शामिल हैं, बनने से देश में सक्रिय कई वैश्विक कंपनियों से महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है।
- पिछले अगस्त में, सरकार ने किफायती किराये की आवास परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया था।

ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन

भाग- जीएस प्रारंभिक और जीएस -III - ऊर्जा संसाधन

सुर्खियों में-

- हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है।

उद्देश्य:

- ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिये बायोमास को-फायरिंग (co-firing) के स्तर को वर्तमान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाना।
- बायोमास पेलेट एवं कृषि-अवशेषों की आपूर्ति शृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाने के लिए।
- बायोमास को-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।

विशेषताएं:

- मिशन में सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी।
- समिति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) आदि के प्रतिनिधियों सहित हितधारक शामिल हैं।
- कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सदस्य (थर्मल), सीईए करेंगे।
- **मिशन की अवधि:** न्यूनतम 5 वर्ष।

प्रस्तावित मिशन का महत्व

- यह खेत पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करेगा और थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा।
- इससे ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लक्ष्य में और मदद मिलेगी।
- यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में भी योगदान देगा।

संबंधित आलेख

- बंगाल की खाड़ी में फाइटोप्लांकटन बायोमास
-

मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस- III इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मेकेदातु में हो रही अनधिकृत निर्माण गतिविधि के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्त की है।
- कर्नाटक सरकार ने उसी स्थान पर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था।

अन्य संबंधित तथ्य

- मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना में रामनगरम जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलित जलाशय का निर्माण शामिल है।
 - इसमें बिजली उत्पादन के अलावा बेंगलूरु और रामनगरम जिलों में पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
 - हालांकि, तमिलनाडु ने इसका विरोध इस आधार पर किया है कि यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन करती है।
-

श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावरग्रिड को स्थानांतरित किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर; अर्थव्यवस्था
सुर्खियों में-

- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने प्रतिष्ठित 220 केवी क्षमता वाले श्रीनगर-द्रास-कारगिल-खालत्सी-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को भारत सरकार के महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (पावरग्रिड) को स्थानांतरित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह ट्रांसमिशन सिस्टम फरवरी 2019 में चालू की गई थी।
 - यह गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए लद्दाख क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है।
-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कोविड -19 टीकों की ड्रोन डिलीवरी

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; शासन
सुर्खियों में-

- नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोविड-19 टीकों की प्रायोगिक डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार को ड्रोन परिनियोजन के लिए सशर्त छूट प्रदान की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ड्रोन का उपयोग करते हुए विजुअल (वीएलओएस) रेंज के भीतर अनुमति दी गई है।
- यह एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक वैध है।
- इस महीने की शुरुआत में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को IIT कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके कोविड -19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई।

- इन अनुमतियों के अनुदान का उद्देश्य तेजी से वैक्सीन वितरण और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है:
 1. नागरिक के द्वार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना
 2. हवाई वितरण के माध्यम से COVID भीड़भाड़ वाले या COVID संभावित क्षेत्रों में मानव खतरे को सीमित करना
 3. अंतिम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में
 4. लंबी दूरी के ड्रोन के लिए चिकित्सा लोजिस्टिक्स के मध्य मील में संभावित एकीकरण
 5. चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, विशेष रूप से तीसरे टीके के चालू होने और लाखों खुराक को संपूर्ण भारत में ले जाने की उम्मीद के साथ।

नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में परिवर्तित करना

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - स्वास्थ्य और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने की व्यवहार्यता का पता लगाया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ऐसे विभिन्न संभावित उद्योगों की पहचान की गई है जिनमें मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।
- नाइट्रोजन संयंत्रों में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव (सीएमएस) का उपयोग किया जाता है जबकि ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिथोलाइट मॉलीक्यूलर सीव (जेडएमएस) की आवश्यकता होती है।
- इसलिए, सीएमएस को जेडएमएस के साथ बदलकर और कुछ अन्य परिवर्तन जैसे ऑक्सीजन विश्लेषक, नियंत्रण कक्ष प्रणाली, प्रवाह वाल्व आदि को पूरा करके मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए संशोधित किया जाता है।
- ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संशोधित नाइट्रोजन संयंत्र को या तो पास के अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- यदि संयंत्र को स्थानांतरित करना संभव नहीं है, तो इसका उपयोग ऑक्सीजन के ऑन-साइट उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसे विशेष पोत / सिलेंडर से अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है।

खाना पकाने के प्रयुक्त तेल (यूसीओ) से उत्पादित बायो-डीजल

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इंडियन ऑयल के टिकरीकलां टर्मिनल, दिल्ली से ईओआई योजना के तहत यूको (यूज्ड कुकिंग ऑयल) आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- UCO को बायोडीजल में परिवर्तित करने और उद्यमिता के अवसरों को विकसित करने को लेकर एक इको-सिस्टम बनाने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 10 अगस्त 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर "प्रयुक्त खाना पकाने के तेल से उत्पादित बायो-डीजल की खरीद" के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) शुरू की थी।
- यह भारत के जैव ईंधन के अनुसरण में एक मील का पत्थर है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- बायोडीजल पारंपरिक या 'जीवाश्म' डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है।
- इसे वनस्पति तेलों, पशु वसा, लोंगो और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से उत्पादित किया जा सकता है।

- बायोडीजल का एक महत्वपूर्ण लाभ इसकी कार्बन-तटस्थता है, अर्थात तिलहन CO₂ की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है जितना कि किसी वाहन में ईंधन के दहन के दौरान छोड़ा जाता है।
- इसके अलावा, बायोडीजल तेजी से बायोडिग्रेडेबल और पूरी तरह से गैर विषैले है।

संबंधित लेख

- जैव ईंधन कैसे कृषि आय को दोगुना कर सकते हैं।
-

विनकोव-19

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; जैव प्रौद्योगिकी

सुर्खियों में-

- सीएसआईआर- सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने संभवतः COVID-19 उपचार के लिए पहली विशिष्ट दवा विकसित की है, जिसमें चिकित्सीय एंटीबॉडी होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

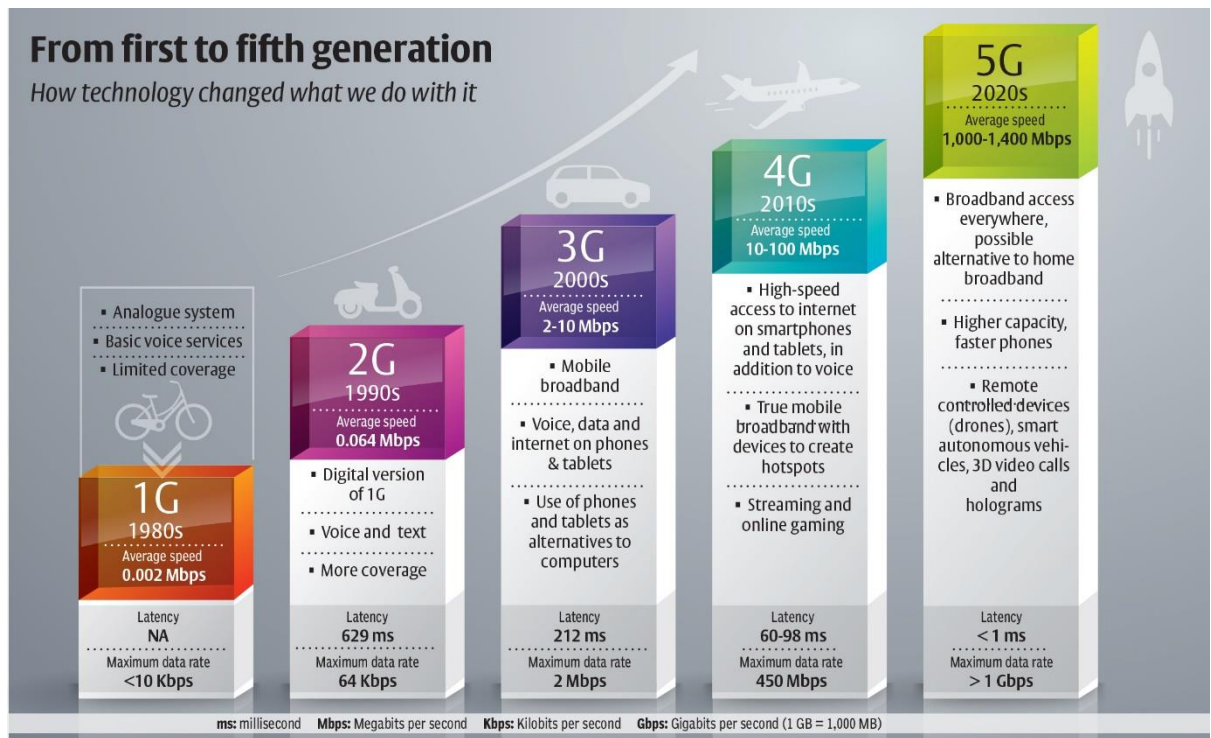
- भारत के औषध महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने विनकोव-19 के मानव परीक्षण, चरण- I और चरण- II के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही दिल्ली और राजस्थान में इसके परीक्षण की उम्मीद है।
 - विनकोव-19 निष्क्रिय कोरोना वायरस के इंजेक्शन लगाने के बाद घोंड़ों से एंटीबॉडी का एक संग्रह है।
 - चरण I और II के परिणाम घोषित होने के बाद इसके आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन अपेक्षित है।
 - संक्रमण के प्रारंभिक चरण के दौरान दिए जाने पर यह सबसे अच्छा काम करता है।
-

भारत में 5जी परीक्षण

संदर्भ: दूरसंचार विभाग ने निजी टेलीकॉम एयरटेल, रिलायंस जियो और Vi तथा और साथ ही राज्य द्वारा संचालित टेलको MTNL को 5G तकनीक के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी। प्रारंभ में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिये है।

5जी क्या है?

- 5जी पांचवीं पीढ़ी की सेल्युलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड (1 जीबीपीएस की स्पीड) को बढ़ाने के अलावा विलंबता यानी नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय को भी कम करती है।
- यह ऊर्जा दक्षता भी बढ़ाता है और अधिक स्थिर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है।
- 5G को पहले के सेल्युलर नेटवर्क की तुलना में अधिक मजबूती से सिग्नल देने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है
- 5G का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (फ्रीक्वेंसी की रेंज) में एक व्यापक क्षेत्र होगा जो सुनिश्चित करेगा कि कोई नेटवर्क कंजेशन न हो।
- इसके अलावा, यह एक पूर्ण सर्कल से कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा अर्थात सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा रहेगा।
- 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने और हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने में मदद करेगा और
- 5G का लाभ प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को नए फोन खरीदने होंगे, जबकि वाहकों को तेज सेवा प्रदान करने के लिए नए ट्रांसमिशन उपकरण स्थापित करने होंगे।



5जी में बैंड्स- 5G मुख्य रूप से 3 बैंड (लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम) में कार्य करता है, जिसमें सभी के बैंड्स के कुछ विशिष्ट उपयोग और कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं।

- **लो बैंड स्पेक्ट्रम (Low Band Spectrum):** इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के इंटरैक्शन-प्रदान की अधिकतम गति 100Mbps (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) तक होती है।
- **मिड बैंड स्पेक्ट्रम (Mid-Band Spectrum):** इसमें लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
- **हाई बैंड स्पेक्ट्रम (High-Band Spectrum):** इसमें उपरोक्त अन्य दो बैंड्स की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।

दूरसंचार कंपनियों के लिए 5जी तकनीक के परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- **कट-थ्रोत मार्केट :** भारतीय बाजार में दूरसंचार की केवल तीन निजी दूरसंचार कंपनियां बची हैं, इसलिए प्रति उपयोगकर्ता अपने औसत राजस्व को बढ़ाने के लिए, दूरसंचार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जल्द से जल्द नई 5जी प्रौद्योगिकी की पेशकश शुरू करें।
- **सरकार को स्थायी समिति की चेतावनी:** सूचना प्रौद्योगिकी पर लोकसभा की एक स्थायी समिति ने 5जी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि अगर सरकार ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो भारत को 5जी सेवा की कमी महसूस होगी।

भारत में अभी के लिए 5G ट्रायल क्या होगा?

- प्रारंभिक चरण में, ये परीक्षण 6 महीने के लिए होंगे, जिसमें उपकरणों की खरीद और इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिये 2 महीने की अवधि भी शामिल है।
- इन 6 महीनों में, दूरसंचार कंपनियों को शहरी क्षेत्रों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेटअप का परीक्षण करना होगा।
- इस अवधि के दौरान, दूरसंचार कंपनियों को विभिन्न बैंडों में प्रायोगिक स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा, जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज का मिड-बैंड, 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज का मिलीमीटर वेव बैंड और अन्य।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- दूरसंचार क्षेत्र में समायोजित सकल राजस्व संकट
-

लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट का पुनः प्रवेश

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - स्पेस; विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- चीन लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट के मलबे ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश किया और हिंद महासागर में विघटित हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 29 अप्रैल को लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था ताकि नए तियान्हे अंतरिक्ष स्टेशन के एक कोर मॉड्यूल को कक्षा में स्थापित किया जा सके, जिसके 2022 में चालू होने की उम्मीद है।
- कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या मलबा पृथ्वी की सतह पर आबादी वाले क्षेत्र से टकराएगा।

रॉकेट ने चिंता क्यों पैदा की?

- जब एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो इसके छोड़े गए बूस्टर चरण लिफ्टऑफ के तुरंत बाद वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हैं और हानिरहित रूप से समुद्र में गिर जाते हैं।
- इस मामले में, हालांकि 18 मीट्रिक टन वजनी रॉकेट का एक 10-मंजिल बड़ा वाहन निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के खंड के साथ कक्षा में चला गया, जिसे वह ले जा रहा था।
- इस प्रकार एक "अनियंत्रित पुनः प्रवेश" अपरिहार्य हो गया, लेकिन चीन ने 8 मई तक इस तथ्य को विश्व के सामने स्वीकार नहीं किया।
- मनुष्य के चोटिल होने की संभावना कम थी क्योंकि वायुमंडल में जला हुआ अधिकांश मलबा और पृथ्वी के बड़े हिस्से महासागरों से ढके हुए हैं और बड़े पैमाने पर भूमि क्षेत्र निर्जन हैं।

क्या आप जानते हैं?

- जब रॉकेट अपने पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो कक्षा में पहुंचने वाले उनके बूस्टर चरण अपना काम पूरा करने के बाद फिर से इंजन में आग लगाते हैं ताकि पृथ्वी पर वापस आ जाएं और कक्षा में न रहें।
 - अंतरिक्ष एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया की योजना बनाती हैं कि ऐसे रॉकेट के पुर्जे समुद्र के बीच जैसे निर्जन क्षेत्रों में समाप्त हो जाएं।
 - चीन ने अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट के लिए ऐसा नहीं करने का फैसला किया, जिससे उसका वाहन अनियंत्रित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
-

2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज डीजीसीआई द्वारा अनुमोदित

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य; जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपातकालीन उपयोग के लिए एंटी-कोविड दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज को मंजूरी दी।
- द्वारा विकसित:** परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान (INMAS), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक प्रयोगशाला, डॉ रेड्डीज प्रयोगशालाओं (DRL), हैदराबाद के सहयोग से।

महत्वपूर्ण तथ्य

- क्लीनिकल ट्रायल्स के परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेजी से ठीक होने में मदद करता है और पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को कम करता है।

- 2-डीजी के साथ इलाज किए गए रोगियों के उच्च अनुपात ने COVID रोगियों में RT-PCR नकारात्मक रूपांतरण दिखाया।
- यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी।
- यह दवा पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मुख द्वारा लिया जाता है।
- यह वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है।
- विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं में इसका चयनात्मक संचय इस दवा को अद्वितीय बनाता है।

धुआं रहित शवदाह प्रणाली विकसित

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ ने एकगतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है। यह अपनी तरह की पहली तकनीक का उपयोग करने का दावा करता है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआंरहित शवदाह होता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह शवदाह के लिए जरूरी लकड़ी की आधी मात्रा का ही इस्तेमाल करता है।
- दहन वायु प्रणाली का उपयोग करने वाली तकनीक के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल है।
- यह विक-स्टोव तकनीक पर आधारित है जिसमें बत्ती जलाने पर पीली चमकती है।
- इसे बत्तियों के ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआंरहित नीली लौ में परिवर्तित किया जाता है।
- शवदाह प्रणाली या भट्टी 1044 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, जो पूर्ण रोगाणुनाश सुनिश्चित करता है।
- वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि इस प्रणाली को अपनाया जाता है, तो यह उन लोगों के निकट और प्रियजनों को सम्मानजनक दाह संस्कार प्रदान कर सकता है जो लकड़ी की व्यवस्था का वित्तीय बोझ नहीं उठा सकते हैं।

चीन द्वारा मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपने पहले मार्स रोवर को लेकर एक अंतरिक्ष यान उतारा, जिससे उसकी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को काफी बढ़ावा मिला।

महत्वपूर्ण तथ्य

- जुलाई 2020 में चीन ने लैंडर और रोवर लेकर अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया था।
- फरवरी से तियानवेन-1 कक्षा में था।
- हाल ही में, एक लैंडर जूरोंग नामक रोवर को लेकर मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा।
- पहले केवल रूस और यू.एस.ए ने ही मंगल पर सफल लैंडिंग की थी।
- रोवर "मंगल ग्रह के अंतरिक्ष पर्यावरण, सतह स्थलाकृति और मिट्टी की संरचना पर अनुसंधान के लिए पहली हाथ से बनी सामग्री प्रदान करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- 2019 में, चौथी चंद्र सम्बन्धी जांच में, चांग ई-4 ने चंद्रमा के सबसे दूर की ओर विश्व की पहली लैंडिंग की।
- अगले वर्ष मंगल मिशन शुरू किया गया था।

- पिछले महीने, एक लांग मार्च-5B Y2 रॉकेट ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तीन घटकों में से पहले काम किया, जिसे तियान्हे या स्वर्गीय सद्भाव मॉड्यूल कहा जाता है।

सुर्खियों में प्रजातियाँ: कॉमन क्रेन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- हाल ही में कॉमन क्रेन को आयरलैंड में देखा गया।
- यह तीन सदी से भी अधिक समय पहले आयरलैंड से बिलुप्त हो गये थे।
- कॉमन क्रेन एक ऐसा पक्षी है जो आयरलैंड की लोककथाओं, इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रहा है और मध्ययुग के दौरान यह एक लोकप्रिय पालतू पक्षी भी था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पिछले साल एक बहाल (रिस्टोर्ड) पीट बोग पर क्रेन की एक जोड़ी देखी गई थी
- पीट बोग एक प्रकार की आर्द्रभूमि है जो ज्यादातर उत्तरी अक्षांश देशों में पाई जाती है।
- यह पक्षी आयरलैंड के मिडलैंड्स क्षेत्र में मिलता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनके सही स्थान को गुप्त रखा गया है।
- कॉमन क्रेन 4 फीट ऊँचे और 7 फुट से अधिक पंखों के साथ खड़े होते हैं, और यह आयरलैंड का सबसे बड़ा पक्षी हुआ करता था।
- हालांकि पक्षी कभी आयरलैंड में एक आम दृश्य थे, हालांकि, उनके आवास के विनाश ने उन्हें 16 वीं और 17 वीं शताब्दी के आसपास गायब कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

दलदल की बहाली क्यों महत्वपूर्ण है?

- दलदल (जिसे दलदल भी कहा जाता है) नरम, स्पंजी आर्द्रभूमि होते हैं जो पीट जमा करते हैं।
- पीट एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग उत्तरी यूरोप में घरों और व्यवसायों को गर्म करने के लिए किया जाता है।
- वे उत्तरी जलवायु में बनते हैं, और विकसित होने में हजारों साल लगते हैं।
- बोम्स कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं, साइबेरिया और स्कैंडिनेविया में पर्यावरण से लगभग 200 मिलियन टन कार्बन को अलग करते हैं।
- हालांकि, सदियों से, पीट निकालने या विकास के लिए दलदलों को सूखा दिया गया , जिससे उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हुआ, जिसमें यहां प्रजनन करने वाली क्रेन जैसी प्रजातियों को नुकसान भी शामिल है।



राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप और क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप सुखियों में-

- हाल ही में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप' (National Mobile Monitoring Software- NMMS app) और क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप (Area officer monitoring App) लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यस्थलों पर श्रमिकों की जीओ-टैग फोटोग्राफ के साथ रियलटाइम उपस्थिति लेने की अनुमति देता है।
 - जो संभावित रूप से प्रसंस्करण भुगतानों को तेजी से सक्षम करने के अलावा कार्यक्रम की नागरिक निगरानी में वृद्धि करेगा
 - **क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप:** इसके जरिए महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैप और जीओ-कोऑर्डिनेट के साथ टैग की गई तस्वीरों (geo-coordinate tagged photograph) और निष्कर्षों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है।
 - यह न केवल क्षेत्रीय और पर्यवेक्षी अधिकारियों को निरीक्षणों के बेहतर रिकॉर्ड रखने में सक्षम करेगा बल्कि इसके माध्यम से बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए निष्कर्षों का विश्लेषण करने की भी सुविधा मिलेगी।
-

आपदाप्रबंधन

सार्वजनिक भवन और अग्नि सुरक्षा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - आपदा प्रबंधन

सुर्खियों में-

- पिछले एक साल में, अस्पताल की इमारतों में घातक आग लगने की कई घटनाएँ देखी गईं। इसमें COVID-19 के उपचार वाले अस्पताल भी शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2019 में वाणिज्यिक आग कि घटनाओं से 330 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
- इनमें आवासीय या आवासीय भवनों में कुल मौत 6,329 हुई हैं।
- अस्पतालों में हाल ही में आग लगने के पीछे मुख्य कारण के रूप में बिजली से जुड़ी हुई समस्या बताई जा रही है।
- सुरक्षा कानूनों के निर्माण में शिथिलता और सार्वजनिक भवनों को आधुनिक तकनीक से लैस करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकारों की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है।
- अस्पताल के आईसीयू आग का एक बड़ा जोखिम वाला क्षेत्र हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन से भरे होते हैं, और उन्हें उच्च मानकों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता का भाग 4 अग्नि और रेखा सुरक्षा से संबंधित है।
- दस्तावेज़ डिज़ाइन और सामग्रियों के लिए विनिर्देश और दिशानिर्देश प्रदान करता है जो विनाशकारी आग के खतरे को कम करते हैं।
- अस्पताल कोड में संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

eCLP
e-Classroom Mentorship Program
(Foundation Course)

ILP
ONLINE Integrated Learning Program
(Mentorship Based)

AIPTS+
All India Prelims Test Series
+ Video Discussions

ILP Basic ILP Plus ILP Connect

LEARN MORE

P-8I गश्ती विमान

भाग-जीएस प्रीलिमिन्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- यू.एस. विदेश विभाग ने भारत को छह P-8I गश्ती विमानों और उससे संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दी, इस सौदे की अनुमानित लागत \$2.42 बिलियन है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नवंबर 2019 में, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने बोइंग द्वारा निर्मित लंबी दूरी की समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दी।
- संभावित बिक्री विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से आती है और इसके लिए आवश्यक है कि यू.एस. कांग्रेस को सूचित किया जाए।
- भारत के यू.एस. के साथ संचार सुसंगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) के मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, छह विमान एन्क्रिप्टेड सिस्टम से सुसज्जित होंगे।
- पी-8आई बोइंग 737 वाणिज्यिक विमान पर आधारित है और भारत इसका पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक था।

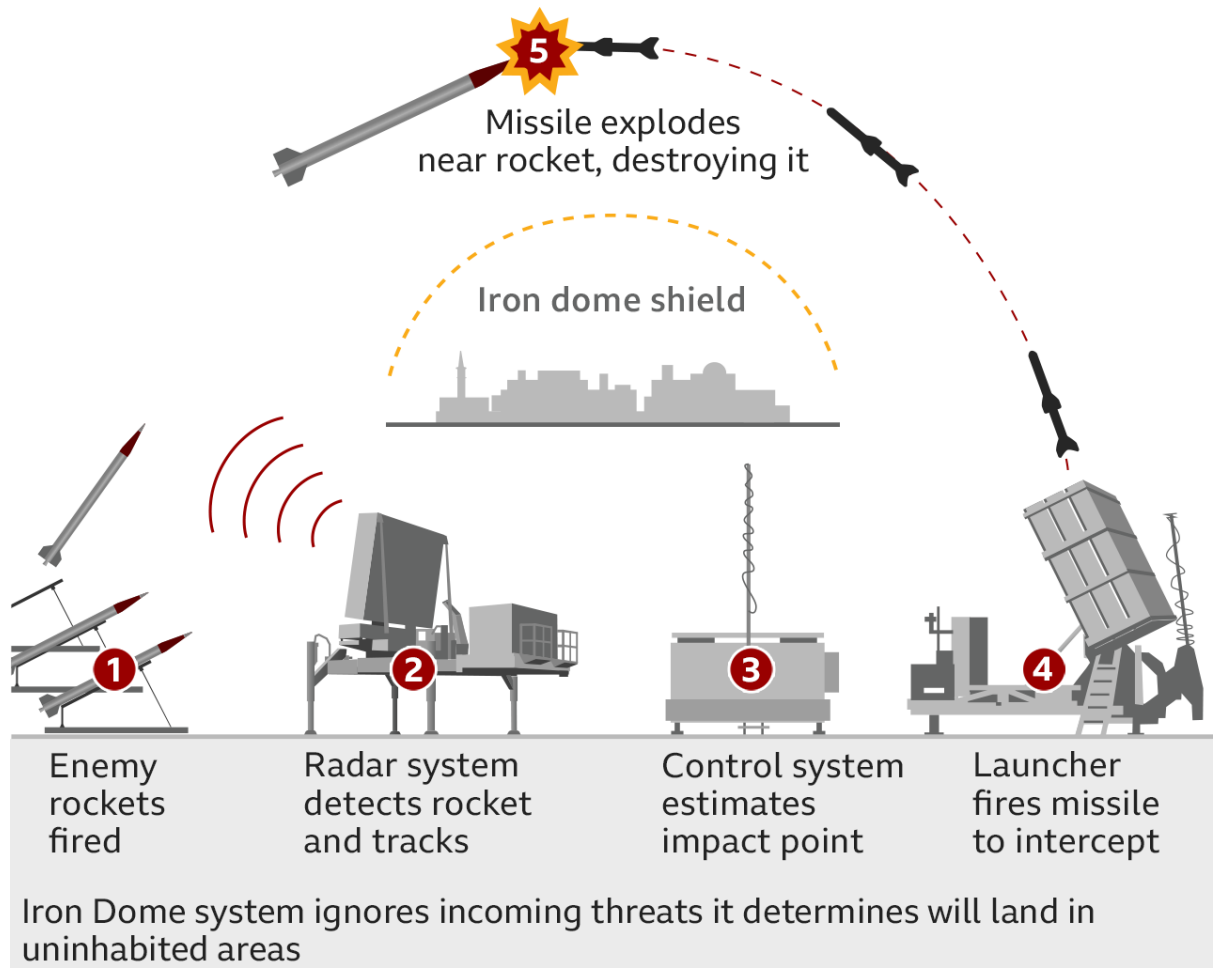
इजराइल का आयरन डोम रॉकेट रक्षा प्रणाली

संदर्भ: इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हाल की हिंसा में, हमास ने गाजा से पूरे इजराइल में 1,500 से अधिक रॉकेट दागे हैं, जिसे आयरन डोम द्वारा रोक दिया गया।

आयरन डोम क्या है?

- **रक्षा प्रणाली:** आयरन डोम एक बहु-मिशन प्रणाली है जो 70 किमी तक की छोटी दूरी पर रॉकेट, तोपखाने, मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी को रोकने में सक्षम है।
- **बहुमुखी प्रतिभा:** यह हर मौसम में चलने वाली प्रणाली है और एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और इसे जमीन और समुद्र पर तैनात किया जा सकता है।
- **डेवलपर्स:** आयरन डोम राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और 2011 से इजरायली वायु सेना के साथ सेवा में है। यह रडार सिस्टम एल्टा द्वारा विकसित किया गया था।
- **विकास करने का संदर्भ:** 2000 के दशक में हिज्बुल्लाह और हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमलों की एक श्रृंखला के बाद इसके विकास को प्रेरित किया गया था। 2006 के लेबनान युद्ध में, इजराइल के उत्तरी हिस्सों पर लगभग 4,000 रॉकेट दागे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 44 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और इस सिस्टम के विकास के बाद लगभग 250,000 नागरिकों को निकाला गया था।

How Israel's Iron Dome defence system works



Source: Rafael Advanced Defense Systems

BBC

स्रोत: बीबीसी

यह कैसे काम करता है?

- आयरन डोम बैटरी में एक युद्ध प्रबंधन नियंत्रण इकाई, एक पता लगाने और ट्रैकिंग रडार और तीन ऊर्ध्वाधर लांचरों की एक फायरिंग इकाई होती है, जिसमें प्रत्येक में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं।
- इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में लक्ष्य वारहेड को विस्फोट करने के लिए एक नजदीकी फ्यूज का उपयोग करती है।
- आयरन डोम को डेविड की स्लिंग और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ एक स्तरित रक्षा में तैनात किया गया है जिसे मध्यम और लंबी दूरी के खतरों के लिए बनाया किया गया है।
- सिस्टम के महत्वपूर्ण लाभों में से एक खतरनाक रॉकेट के प्रभाव के प्रत्याशित बिंदु की पहचान करने की क्षमता है, यह गणना करने के लिए कि यह एक निर्मित क्षेत्र में गिरेगा या नहीं, और इस आधार पर निर्णय लेना है कि इसे संलग्न करना है या नहीं।
- यह रॉकेट के अनावश्यक अवरोधन को रोकता है जो खुले क्षेत्रों में गिरेंगे और इस प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेपर कहता है।
- प्रणाली ने अब तक हजारों रॉकेटों को रोक दिया है और राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स के अनुसार, इसकी सफलता की दर 90% से अधिक है।

- आई-डोम एक ही ट्रक पर सभी घटकों के साथ मोबाइल संस्करण है और सी-डोम जहाजों पर तैनाती के लिए नौसेना संस्करण है।

सिस्टम की सीमाएं क्या हैं?

- सिस्टम ने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि, जब यह प्रोजेक्टाइल के बैराज से अभिभूत होता है, तो सिस्टम सीमाओं को देख सकता है। सिस्टम में एक 'संतृप्ति बिंदु' होता है।
- यह एक ही समय में एक निश्चित (अप्रकाशित) लक्ष्यों को शामिल करने में सक्षम है, और अधिक नहीं। भीड़भाड़ वाली सैल्वो में दागे गए अतिरिक्त रॉकेट सुरक्षा को भंग करने और नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकते हैं।
- कई आकलनों से पता चलता है कि हमारा प्रक्षेपास्त्रों के प्रक्षेप पथ को कम करने सहित शमन करने वाली रणनीतियां विकसित कर रहा है, जबकि बेहतर सटीकता के साथ हजारों रॉकेटों को जमा करना जारी रखता है।
- संभावित सीमाओं में से एक प्रणाली की बहुत कम दूरी के खतरों से निपटने में असमर्थता है क्योंकि अनुमान के अनुसार आयरन डोम की न्यूनतम अवरोधन सीमा 5-7 किलोमीटर है।
- अन्य कारक अवरोधन की लागत अधिक है। इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000-50,000 डॉलर है।

मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- हाल ही में लागू हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज आउटलेट्स के लिए नए नियम, जिन्हें इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दिशानिर्देशों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया था, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल थी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इन प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
- इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स की तीसरी आवश्यकता संदेश के पहले प्रवर्तक को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना था।
- इन आवश्यकताओं में से किसी एक का पालन करने में विफलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति (सुरक्षा) को छीन लेगी।

क्या आप जानते हैं?

- धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

नियम और शासक: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

संदर्भ: नया सोशल मीडिया कोड लागू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अधिकांश वैश्विक सोशल मीडिया दिग्गज नए नियमों का पालन करने से चूक जाएंगे।

- फरवरी 2021 में नए नियम पेश किए गए थे।
- अन्य बातों के अलावा, उन्हें बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को तीन महीने के भीतर नियमों के एक बड़े सख्त सेट का पालन करने की आवश्यकता है, जो 25 मई को समाप्त हो गया।
- नए नियमों के लिए इन प्लेटफॉर्मों को नियुक्त करने की आवश्यकता है
 - नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी,

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी,
- शिकायत अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान दें
- एक अन्य नियम के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने प्रवर्तकों (ट्रेसिबिलिटी) को समस्याग्रस्त संदेशों का पता लगा सके।

मुद्दे

- गैर-अनुपालन कुछ सोशल मीडिया प्लेयर्स और सरकार के बीच पहले से ही खराब संबंधों को और भी खराब करने वाला था
 - उनके बीच नवीनतम गतिरोध, ट्विटर पर भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा कुछ पोस्ट को 'हेरफेर मीडिया' के रूप में टैग करने के परिणामस्वरूप, दिल्ली पुलिस को कंपनी के कार्यालयों का दौरा करना पड़ा।
- ट्रेसिबिलिटी नियम इस बारे में असहज प्रश्न उठाता है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सेवाएं इसका पालन कैसे कर सकती हैं।
- इन नियमों को बिना ज्यादा सार्वजनिक परामर्श के पेश किया गया था।
- इन नए नियमों को लाने के बारे में भी आलोचना हुई है, जिन्हें सामान्य रूप से केवल विधायी कार्रवाई के माध्यम से शुरू किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया कंपनियां नए नियमों के खिलाफ कानूनी अदालत में लड़ें, यदि वे उन्हें समस्याग्रस्त पाते हैं।
- कंपनियों द्वारा गैर-अनुपालन को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि यू.एस. सरकार के पास उनकी पीठ है।
- सीआईआई, फिक्की और यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउंसिल सहित पांच उद्योग निकायों ने अनुपालन के लिए 6-12 महीने के विस्तार की मांग की है। यह सरकार के लिए उद्योग को सुनने और नियम बनाने के अपने उच्च-स्तरीय तरीके को छोड़ने का एक अवसर है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बड़ी तकनीक का प्रभुत्व
- ऑस्ट्रेलिया का समाचार मीडिया बार्गेनिंग कोड



IAS BABA

RAPID REVISION (RaRe) SERIES

Road Map For The Next 120 Days For UPSC 2021!

10 Stepping Stones To Success!
A Dedicated Portal For Focused Preparation

REGISTER NOW

Prelims+Mains Focus **#ReviseWithBaba** **Starting From 31st May, 2021**



विविध

समाचार	विवरणमें
1. मूरहेन योगा मैट (Moorhen Yoga Mat)	● हाल ही में असम के मछुआरे समुदाय द्वारा जलकुंभी से एक बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल योगा मैट विकसित की गई है। ● इस चटाई को 'मूरहेन योगा मैट' कहा जाता है ● इसे जल्द ही एक अनोखे उत्पाद के रूप में विश्व बाजार में लाया जाएगा। ● जलकुंभी से आजीविका तथा मछुआरे समुदाय द्वारा जलकुम्भी की समस्या से निजात पाने के लिए 6 लड़कियों की अगुवाई में समस्त महिला समुदाय 'सिमांग' (जिसका अर्थ स्वप्न) को शामिल करते हुए यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय 'उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र' की एक पहल है। ● जलकुम्भी एक एकबीजपत्री, सपुष्पक जलीय पौधा है। क्योंकि इससे मछुआरे समुदाय को लाभ नहीं होता है और उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचता है।
2. दीपोर बील	● दीपोर बील असम में एक स्थायी मीठे पानी की झील है। ● इसे रामसर साइट और पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।
3. चक्रवाती तूफान 'तौकते'	● चक्रवाती तूफान 'तौकते', जो लक्षद्वीप के पास अरब सागर के ऊपर एक गहरे दबाव के रूप में था, यह पश्चिमी तट के कई हिस्सों में भारी बारिश लाने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। ● अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चक्रवाती तूफान गुजरात तट को पार करेगा या 18 मई तक इसे पार कर जाएगा। ● इसके अगले 12 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान में बदलने की अधिक संभावना है और इसके बाद के 24 घंटों के दौरान और तेज होने और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ● चक्रवात तौकते चेतावनी के मद्देनजर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 24 टीमों को तैनात किया है।
4. फेकबस्टर	● भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, और मॉनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधानकर्ताओं ने 'फेकबस्टर' (FakeBuster) नामक एक ऐसा अनोखा डिटेक्टर (unique detector) विकसित किया है, ● महत्व: जो ऐसे किसी भी ऑनलाइन फरेबी का पता लगा सकता है, जो बिना किसी जानकारी के वर्चुअल सम्मेलन में घुसपैठ कर जाते हैं। ● फेकबस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परिदृश्यों के लिए एक 'डीपफेक्स' (DeepFakes) डिटेक्शन टूल या उपकरण है। ● तकनीक यह पता लगाएगी कि क्या कोई धोखेबाज वेबिनार में भाग ले रहा है या आपके किसी सहकर्मी की ओर से उसकी छवि को अपनी छवि से बदलकर आभासी बैठक में भाग ले रहा है।

	● मौजूदा महामारी के दौर में ज्यादातर कामकाज और आधिकारिक बैठकें ऑनलाइन हो रही हैं। इस अनोखी तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के वीडियो के साथ छेड़-छाड़ की जा रही है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन घुसपैठ कर रहा है।
5. चक्रवात यास	● भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात यास के 26 मई को "प्रचंड चक्रवाती तूफान" में बदलने और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। ● पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। ● इस चक्रवात को यास नाम ओमान द्वारा दिया गया है। ● यह एक ऐसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसकी सुगंध अच्छी होती है और अंग्रेजी में यह शब्द जैस्मीन के समान है। ● म्यामांर द्वारा नामित चक्रवात ताउते का बर्मी बोली में अर्थ है "गेको" - एक अत्यधिक मुखर छिपकली।
6. वाइनयार्ड पवन परियोजना	● यूएसए ने देश के पहले प्रमुख अपतटीय पवन फार्म को मंजूरी दी है जो बिजली क्षेत्र से उत्सर्जन को खत्म करने में मदद करेगा। ● इसे वाइनयार्ड पवन परियोजना के नाम से जाना जाता है। ● यह मैसाचुसेट्स के तट पर स्थित होगा। ● यह 2023 की दूसरी छमाही तक 400,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी। ● प्रशासन का अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 3600 रोजगार सृजित होंगे।
7. ऑरोविले	● पेरिस में ऑरोविलियन क्रिस्टोफ पोहल की डॉक्यूमेंट्री एवरस्लोग्रीन को प्रतिष्ठित चेंजनाउ शिखर सम्मेलन में स्क्रीनिंग के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया। ● यह ऑरोविले की अनूठी वनरोपण परियोजना की कहानी बताती है जिसने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक मरुस्थलीय पठार पर जड़ें जमा लीं। ● ऑरोविले, विल्लुपुरम जिले में एक प्रायोगिक टाउनशिप है। ● इसकी स्थापना 1968 में एक फ्रांसीसी आध्यात्मिक गुरु और श्री अरविंदो के सहयोगी मीरा अल्फासा ("माँ" के रूप में जानी जाती है) द्वारा की गई थी, जो उन्हें अपने समान योगिक कद का मानते थे और उन्हें "द मदर" नाम से पुकारते थे।
8. अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार 2020	● भारत रत्न प्रोफेसर सी.एन.आर. राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। ● इस पुरस्कार को 'एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार' (Energy Frontier award) भी कहा जाता है। ● यह आधिकारिक समारोह रोम के क्विरिनल पैलेस में आयोजित किया जाएगा। ● ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करना है।

	● इसे ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है।
9. लेटे हुए बुद्ध	● एक लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध को उनकी अंतिम बीमारी के दौरान, परिनिर्वाण में प्रवेश करने के बारे में दर्शाती है, मृत्यु के बाद महान मुक्ति का चरण जिसे केवल प्रबुद्ध आत्माओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ● लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों और छवियों में उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ दिखाया गया है, उनका सिर एक कुशन पर या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। ● इसे सबसे पहले गांधार कला में दर्शाया गया था। ● विश्व में सबसे बड़ा झुकनेवाला बुद्ध 600 फुट का विंसीन ताव्या बुद्ध है जिसे 1992 में म्यांमार के मौलामायिन में बनाया गया था। ● इसके अलावा, अजंता की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की गुफा संख्या 26 में 24 फुट लंबी और नौ फुट ऊंची झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में तराशा गया था।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है?

- a) ऑपरेशन राहत b) ऑपरेशन समुद्र सेतु
c) ऑपरेशन समुद्र सेतु-II d) ऑपरेशन मदद

Q.2 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना WHO ने अकेले की थी।
2. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3 मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत मेजबान देश है।
2. हाल ही में समिति ने आयोजित अपने पांचवें सत्र में लौंग, अजवायन, तुलसी और अदरक के लिए मानकों को विकसित और अंतिम रूप दिया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जाइलोफिस दीपाकी तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है।
2. उपपरिवार जाइलोफीनी लकड़ी के सांपों को समायोजित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 वोरुख हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है?

- a) रूस और कजाकिस्तान
- b) कजाकिस्तान और किर्गिस्तान
- c) किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान
- d) तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान

Q.6 पटोला नाच भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कठपुतली है?

- a) असम b) नागालैंड
- c) बिहार d) छत्तीसगढ़

Q.7 लूजोन जलडमरूमध्य किसके बीच है:

- a) फिलीपींस का ताइवान और लूजोन द्वीप
- b) फिलीपींस का चीन और लूजोन द्वीप
- c) जापान और फिलीपींस का लूजोन द्वीप
- d) फिलीपींस का सिंगापुर और लूजोन द्वीप

Q.8 निम्नलिखित में से कौन G-7 का सदस्य देश नहीं है?

- a) फ्रांस b) जापान
- c) इटली d) रूस

Q. 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्बन आण्विक छलनी (सीएमएस) का उपयोग किया जाता है जबकि जिओलाइट आण्विक छलनी (जेडएमएस) ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
2. नाइट्रोजन संयंत्र को ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्र में परिवर्तित करने के बाद स्थानांतरित करना संभव नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.10 बायो-डीजल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उत्पादन वनस्पति तेलों, पशु वसा, वसा और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जा सकता है।

2. बायोडीजल तेजी से बायोडिग्रेडेबल और पूरी तरह से गैर विषैले है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 'दीपोर बील' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक रामसर स्थल है?

- a) असम b) नागालैंड
- c) मेघालय d) मणिपुर

Q.12 स्वामित्व योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?

- a) पर्यावरण मंत्रालय
- b) वित्त मंत्रालय
- c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- d) पंचायती राज मंत्रालय

Q.13 एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।
2. इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 एशियाई विकास बैंक (ADB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसका मुख्यालय शंघाई में है।
2. भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 ट्रिप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है।
2. टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर के अंत में ट्रिप्स पर बातचीत हुई थी।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 'दहला बांध' कहाँ स्थित है?

- a) पाकिस्तान
- b) श्रीलंका
- c) भारत
- d) अफगानिस्तान

Q.17 राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे APEDA द्वारा कार्यान्वित किया जाता है
2. यह घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 APEDA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- a) पर्यावरण मंत्रालय
- b) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- c) वित्त मंत्रालय
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.19 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिसूचित किया गया है?

- a) असंगठित कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए

- b) संगठित श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए
- c) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के डेटाबेस के लिए आधार विवरण एकत्र करने के लिए
- d) केवल बेरोजगार महिलाओं के डेटाबेस के लिए आधार विवरण एकत्र करने के लिए

Q.20 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं:

1. तुर
2. उड़द
3. कपास
4. गेहूं

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1, 2 और 4
- b) 1, 2, और 3 केवल
- c) केवल 2, 3 और 4
- d) केवल 2 और 3

Q.21 ड्रग 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-DG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे एम्स द्वारा विकसित किया गया है।
2. यह वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.22 लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था?

- a) जापान
- b) रूस
- c) भारत
- d) चीन

Q.23 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच MoU के माध्यम से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की गई है?

- a) यूएसए
- b) इजराइल
- c) रूस
- d) यूके

Q.24 निम्नलिखित में से सबसे हाल ही का संप्रभु देश कौन सा है?

- a) सोमालिया b) लीबिया
- c) दक्षिण सूडान d) सूडान

Q. 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक लाइनमेंट एक अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना जैसे कि एक गलती द्वारा निर्धारित परिदृश्य में एक रेखिक विशेषता है।
2. उत्तर-पूर्वी भारत को भूकंपीय क्षेत्र-V के रूप में सीमांकित किया गया है, जो कम खतरे वाले क्षेत्र को दर्शाता करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख टीके दुनिया में COVID-19 के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो केवल निष्क्रिय वायरस का उपयोग करते हैं?

1. सिनोफार्म
2. कोवैक्सिन
3. सिनोवैक
4. कोविशील्ड

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 4
- c) केवल 1, 2 और 4
- d) केवल 1, 2 और 3

Q.27 'म्यूकोर्मिकोसिस' हाल ही में खबरों में रहा। निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?

- a) कवक b) बैक्टीरिया
- c) वायरस d) प्रोटोजोआ

Q.28 गैलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है?

- a) फिलीपींस b) जापान
- c) भारत d) चीन

Q.29 एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ACC उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है

2. प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) योजना 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज' के कार्यान्वयन को हाल ही में मंजूरी दी गई थी।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.30 मसूरी का हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है?

- a) गढ़वाल हिमालयन रेंज
- b) अरावली रेंज
- c) कैमूर रेंज
- d) माईकल रेंज

Q.31 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- a) रक्षा मंत्रालय
- b) शहरी मामलों के मंत्रालय
- c) गृह मंत्रालय
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.32 अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) फंड के लिए विशेष विंडो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिवली पार्क विंटरग्रीन राजस्थान में स्थित होने वाली पहली परियोजना है।

2. स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड भारत में सबसे बड़ी निजी इक्विटी टीमों में से एक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 पेंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपायी है।
2. वे भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.34 'बोंडा समुदाय' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

- a) महाराष्ट्र
- b) गुजरात
- c) छत्तीसगढ़
- d) ओडिशा

Q.35 रेड ईयर स्लाइडर, हाल ही में खबरों में, निम्नलिखित में से किस देश का मूल निवासी है?

- a) चीन
- b) वियतनाम
- c) यूएसए
- d) श्रीलंका

Q.36 रेलवे लाइनों पर हाथियों के हताहत होने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं?

1. रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और MoEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया।
2. लोको पायलटों के लिए स्पष्ट दृश्य को सक्षम करने के लिए रेलवे पटरियों के साथ वनस्पति साफ़ करना।
3. हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास/ओवरपास की स्थापना।
4. संवेदनशील इलाकों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक ट्रेन की गति का नियमन फैलाना।

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1, 2 और 4
- c) केवल 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.37 'काजाकी बांध' कहाँ स्थित है?

- a) उज़्बेकिस्तान
- b) ताजिकिस्तान

c) चीन

d) अफगानिस्तान

Q.38 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है।
2. यह भारत में विस्फोटकों और पेट्रोल स्टेशनों के उपयोग को नियंत्रित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.39 प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रक्त का एक पीला तरल पदार्थ है।
2. यह पूरे शरीर में कोशिकाओं और प्रोटीनों को वहन करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को विभागीय जांच के बिना बर्खास्त किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह सुविधाजनक नहीं है ऐसी जांच करो?

- a) अनुच्छेद 311
- b) अनुच्छेद 312
- c) अनुच्छेद 313
- d) अनुच्छेद 314

Q.41 स्कैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे विषैले होते हैं।
2. वे सांपों से मिलते जुलते हैं।
3. ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटों में पाए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.42 मारोस-पैंगकेप क्षेत्र, दक्षिणी सुलावेसी, इंडोनेशिया, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चा में था?

- a) टीकाकरण के बावजूद कोविड-19 मामलों में वृद्धि
- b) जंगल की आग
- c) ज्वालामुखी विस्फोट
- d) सबसे पुराने रॉक पेंटिंग का पर्यावरण क्षरण

Q.43 RNA निम्न में से किसके कारण DNA से कम स्थिर है?

1. अणु DNA से भिन्न शर्करा से बने होते हैं।
 2. RNA में डबल स्ट्रैंड के बजाय सिंगल स्ट्रैंड होता है।
- सही कोड का चयन करें:**
- a) केवल 1
 - b) केवल 2
 - c) 1 और 2 दोनों
 - d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 हाल ही में, सरकार व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, IGCR 2017 में बदलाव लाई है, जिसके माध्यम से आयातक अब पूरी तरह से जॉब वर्क के आधार पर निर्मित अंतिम माल प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस परिवर्तन से बाहर रखा गया है?

1. सोना
2. आभूषण
3. कीमती पत्थर
4. धातु

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.45 जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्टन संयुक्त पहल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- a) जनजातीय मामलों के मंत्रालय
- b) शिक्षा मंत्रालय
- c) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- d) विदेश मंत्रालय

Q.46 'सतपुड़ा टाइगर रिजर्व' कहाँ स्थित है?

- a) महाराष्ट्र
- b) गुजरात
- c) मध्य प्रदेश
- d) उत्तर प्रदेश

Q.47 'वेडेल सागर' निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है?

- a) हिंद महासागर
- b) प्रशांत महासागर
- c) दक्षिणी महासागर
- d) आर्कटिक महासागर

Q.48 महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कानून राज्यों को सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने, स्कूलों और बड़े संस्थानों को काम बंद करने के लिए कहना और कंपनियों को घर से काम करने के मॉडल का पता लगाने के लिए सलाह जारी करने में सक्षम बनाता है।
2. यह राज्य को गलत सूचना फैलाने वाले मीडिया संगठनों को दंडित करने का अधिकार भी देता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत दुनिया के शीर्ष पांच शहद उत्पादकों में शामिल है।
2. 2005-06 की तुलना में शहद उत्पादन और निर्यात में भारी कमी आई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.50 सफेद कवक और काले कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दोनों घातक रोग है
2. सफेद कवक कैडिडा के कारण होता है जबकि काले कवक का प्रेरक घटक अभी अज्ञात है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.51 निम्न में से कौन सा लेख जीवन के मौलिक अधिकार से संबंधित है?

- a) अनुच्छेद 19
- b) अनुच्छेद 22
- c) अनुच्छेद 21
- d) अनुच्छेद 24

Q.52 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया:

- a) पर्यावरण मंत्रालय
- b) वित्त मंत्रालय
- c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- d) शहरी मामलों का मंत्रालय

Q.53 'कलाक्षेत्र फाउंडेशन' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. भरतनाट्यम की कलाक्षेत्र शैली रेकाका और अंगों के ग्रंथिमुक्त श्रो (कसेपा) से बचाती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 सफेद मक्खियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीटी. कपास सफेद मक्खियों के खिलाफ प्रतिरोधी है।
2. सफेद मक्खियों को कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.55 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना शहर में है।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IAEA के सदस्य हैं

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. माउंट न्यारागोंगो एक सक्रिय स्ट्रेटोवोलकानो है।
2. माउंट न्यारागोंगो अपनी लावा झीलों के लिए जाना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.57 लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है?

- a) केरल का उच्च न्यायालय
- b) महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय
- c) कर्नाटक का उच्च न्यायालय
- d) पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय

Q.58 निम्नलिखित में से कौन-सा देश भूमि से घिरा देश नहीं है?

- a) लिथुआनिया b) बेलारूस
- c) नेपाल d) अज़रबैजान

Q.59 “इंडो-इजरायल विलेज ऑफ एक्सीलेंस” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत-इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों में एक नई अवधारणा है।
2. यह केवल आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.60 'वेसाक' निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए सबसे पवित्र दिन है:

- a) हिंदू धर्म b) बौद्ध धर्म
- c) जैन धर्म d) ईसाई धर्म

Q.61 जरदालु आम, कतरनी चावल और मगही पान निम्नलिखित में से किस राज्य के GI प्रमाणित उत्पाद हैं?

- a) बिहार b) झारखंड
- c) राजस्थान d) उत्तर प्रदेश

Q.62 'मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना' का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जाना प्रस्तावित है?

- a) कावेरी b) यमुना
- c) कृष्णा d) गोदावरी

Q.63 'सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली-कंसल्टेशन (SeHAT) OPD पोर्टल' के लॉन्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है।
2. इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.64 OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक ओवर-द-टॉप (OTT) मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली मीडिया सेवा है।
2. इसकी प्रदान की जाने वाली सेवाएं निःशुल्क हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 विश्व में निम्न में से कौन कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक है?

- a) केरल b) ढाका
- c) न्यूयॉर्क d) बीजिंग

Q.66 निम्नलिखित में से किसे GST से छूट प्राप्त है:

1. ताजे फल और सब्जियां
2. कॉफी बीन्स (बिना भुना हुआ)
3. पान के पत्ते
4. चारकोल

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1, 2, और 3 b) केवल 2 और 4
- c) केवल 1 और 2 d) केवल 1, 2, 3 और 4

Q.67 मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित मदरसों / मकतबों में पढ़ने वाले कक्षा 1-12 वीं के बच्चे शामिल हैं।
2. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नहीं आता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 मुद्रा विनिमय समझौतों के निम्नलिखित लाभों पर विचार करें:

1. इन स्वैप परिचालनों में कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं होते हैं, क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती हैं।
2. यह तीसरी मुद्रा के मुकाबले अस्थिरता के खतरे को कम करता है।
3. यह कई मुद्रा एक्सचेंजों में शामिल शुल्कों को दूर करता है।
4. यह घरेलू मुद्रा पर काल्पनिक हमलों को हतोत्साहित करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

- a) केवल 1, 2, और 3
- b) केवल 2 और 4
- c) केवल 1 और 2
- d) केवल 1, 2, 3 और 4

Q.69 हाल ही में समाचारों में देखी गई झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है?

- a) यह बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा और प्रसारण का प्रतिनिधित्व करता है
- b) यह बुद्ध के जागरण के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है
- c) यह बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करने का प्रतिनिधित्व करता है
- d) यह स्वयं को दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़कर सर्वोच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है

Q.70 'फ्लोटिंग जेटी' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उनकी कीमत एक निश्चित घाट की कीमत का लगभग 1/5 है।
2. वे एक निश्चित घाट की तुलना में निर्माण और स्थापित करने के लिए तेज़ हैं, और उपयोग में आसान हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

मई 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	C
2	B

3	C
4	C

5	C
6	A

7	A
8	D

9	A
10	C
11	A
12	D
13	C
14	B
15	C
16	D
17	A
18	D
19	C
20	B
21	B
22	D
23	D
24	C
25	A

26	D
27	A
28	C
29	C
30	A
31	C
32	B
33	C
34	D
35	C
36	D
37	D
38	B
39	C
40	A
41	C
42	D

43	C
44	D
45	A
46	C
47	C
48	C
49	A
50	D
51	C
52	C
53	C
54	D
55	A
56	C
57	A
58	A
59	A

60	B
61	A
62	A
63	A
64	A
65	A
66	D
67	D
68	D
69	C
70	C



eCLP

e-Classroom Mentorship Program
(Foundation Course)



ILP

ONLINE Integrated Learning Program
(Mentorship Based)

ILP Basic

ILP Plus

ILP Connect



AIPTS+

All India Prelims Test Series
+ Video Discussions



TLP / TLP+

MAINS Mentorship-Based Answer Writing
Program Online + Offline



PEP

Prelims Exclusive Program
With Mentorship



ADMISSION OPEN